6 | संपादकीय
जनसत्ता | 15 दिसंबर, 2025

कल्पमेधा

आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे, जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते।

– महात्मा बुद्ध

रोजगार के अवसर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा गांवों के अकुशल लोगों के लिए काम पाने और अपनी आजीविका चलाने का एक बहुत बड़ा सहारा है। अगर किसी ग्रामीण को और कहीं काम न मिले तो वह मनरेगा के तहत रोजगार पा सकता है। इस कानून के तहत सौ दिन के कार्य की गारंटी दी गई है। केंद्र सरकार ने अब इन कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर एक सौ पच्चीस करने का फैसला किया है और इससे संबंधित विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मगर इसे अब मनरेगा नहीं बल्कि 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' के नाम से जाना जाएगा। यानी अब इसके नए स्वरूप में काम की गांरटी होगी या नहीं, इसको लेकर अभी आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं है। मगर कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय देश की ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के लिहाज से एक महत्त्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आज भी रोजगार का अभाव है और अगर सौ दिन काम मिल भी जाए, तो उसके पारिश्रमिक से घर-परिवार चलाना व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल है।

यह दूसरी बार है, जब इस कानून या योजना का नाम बदला गया है। इसे वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के नाम से लागू किया गया था। इसके बाद वर्ष 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। अब उसके कार्य दिवस में बढ़ोतरी की पहल स्वागतयोग्य है, लेकिन यह सही मायने में तभी सफल मानी जाएगी, जब इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। इसमें दोराय नहीं कि कोविड महामारी के दौरान जब कई उद्योग-धंधे बंद हो गए और हजारों लोग बेरोजगार हुए, तो इसी योजना ने ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहारा दिया था। देश भर में करोड़ों परिवारों की आजीविका का एक हिस्सा इस योजना पर टिका हुआ है।

ग्रामीण इलाकों में इस रोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर पहले से चुनौतियां कम नहीं हैं। शुरुआत से ही इसे लेकर कई तरह की अनियमितताओं के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें गारंटी के मुताबिक सौ दिन का रोजगार न मिलना, कागजों में फर्जी तरीके से रोजगार देना और वित्तीय गड़बड़ियां प्रमुख हैं। अब काम के दिनों में बढ़ोतरी तभी सार्थक होगी, जब पुरानी गड़बड़ियां और अनियमितताओं को दूर किया जाए। ऐसे में इस योजना की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। एक अन्य चुनौती आर्थिक बजट की है, सरकार पर इस योजना के लिए धन आबंटन में कटौती के आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि, सरकार का तर्क है कि यह मांग आधारित योजना है और मांग बढ़ने पर धनराशि का आबंटन भी बढ़ाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम के दिन बढ़ाने के सरकार के निर्णय को इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि अगर रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित किए जाएं, तो गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराने जैसी योजनाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से ज्यादा जरूरी है कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

अराजकता का मैदान

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कोई खिलाड़ी अगर किसी आयोजन के तहत लोगों के बीच जाता है, तो उम्मीद की जाती है कि वहां हर स्तर पर चाक-चौबंद व्यवस्था होगी। कार्यक्रम का स्वरूप पूरी तरह ठोस और मुकम्मल होगा तथा सुरक्षा-व्यवस्था में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मगर कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यात फुटबाल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी जब पहुंचे, तो आयोजकों की अदूरदर्शिता और अव्यवस्था की वजह से वहां व्यापक अराजकता फैल गई। यह हैरानी की बात इसलिए है कि लियोनेल मेस्सी की लोकप्रियता और उनके प्रशंसकों के बीच उन्हें देखने को लेकर दीवानगी के बारे में तस्वीर पहले ही साफ थी। फिर मेस्सी के कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी क्यों बनाई गई, जिसकी वजह से उन्हें देखने आए लोगों के बीच आक्रोश भड़का। गौरतलब है कि मेस्सी अपने भारत दौरे के क्रम में कोलकाता आए थे और वहां स्टेडियम में वे अपने प्रशंसकों से मिलने गए थे। मगर वहां उनके आसपास कई नेता और अन्य लोग इस तरह मौजूद थे कि वे एक तरह से वहां गुम हो गए और दर्शकों के लिए उन्हें देखना मुश्किल हो गया। इस पर लोगों के भीतर गुस्सा पैदा हुआ और उन्होंने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। आखिर मेस्सी को वहां से बाहर निकलना पड़ा।

सवाल है कि आयोजकों ने इस बात को क्यों भुला दिया कि वहां स्थानीय से लेकर बाहर से बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मेस्सी को सिर्फ देखने के लिए अगर पांच हजार से पच्चीस हजार रुपए तक की टिकट खरीदी है, तो वादे के अनुरूप व्यवस्था का ध्यान रखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर लोगों के धीरज खोकर अराजक होने को उचित नहीं कहा जाएगा, लेकिन यह भी तथ्य है कि आयोजकों की लापरवाही की वजह से स्टेडियम में अराजकता छाई, जिसका अंजाम त्रासद भी हो सकता था। इस घटना के बाद स्वाभाविक ही वहां की कानून-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अगर आयोजन और वहां पहुंचे लोगों के मकसद को ध्यान में रख कर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती और एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने का इंतजाम किया जाता, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती।

पशु-पक्षियों के संकेत और मौसम का रंग

आज के तकनीकी संसाधनों के दौर में भी पशु-पक्षियों के व्यवहार से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन उनके व्यवहार, प्रवास, प्रजनन और शारीरिक विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं।

अमित बैजनाथ गर्ग

राजस्थान में जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग ने हाल ही में एक अध्ययन में यह साबित किया है कि पक्षियों के घोंसले बनाने के तरीके से लेकर जानवरों के व्यवहार तक से मौसम के संकेतों को समझा जा सकता है। यह शोध 'इंटरनेशनल जर्नल आफ एनवायरमेंटल साइंस' में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि जानवरों के व्यवहार से अस्सी फीसद तक मौसम का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। यह अध्ययन सिद्ध करता है कि पुराने समय से चली आ रही यह पारंपरिक जानकारी जो ग्रामीणों की ओर से इस्तेमाल की जाती रही है, अब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुकी है। उदाहरण के लिए मोर का नृत्य या कूजन मानसून की शुरुआत का संकेत देता है। इसी तरह चींटियों का भोजन इकट्ठा करना सूखा पड़ने का संकेत है।

विश्वविद्यालय के इस शोध दल का कहना है कि प्रकृति के संकेत आज भी कारगर हैं। पशु-पक्षियों के व्यवहार से मौसम का पूर्वानुमान लग जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन में इन बातों और तथ्यों की पुष्टि हुई है। यानी इससे पुरानी प्रथाओं के वैज्ञानिक प्रमाण साबित हुए हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि पशु-पक्षियों का व्यवहार आज भी मौसम के संकेत बताने में पूरी तरह सक्षम है। यह भी दावा किया गया है कि पारंपरिक ज्ञान का आज भी कोई तोड़ नहीं है। इसके संकेत आज भी वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं। यह भी बताया गया कि कैसे पुराने समय में लोग पारिस्थितिकी तंत्र के सदस्यों के व्यवहार से मौसम की भविष्यवाणी करते थे। लोमड़ी, सियार और अन्य जानवरों का व्यवहार भी इस प्रणाली का हिस्सा था। उदाहरण के लिए लोमड़ी खेतों में चूहों की संख्या को नियंत्रित करती है, जो कृषि के लिए अच्छा संकेत है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भील, मीणा और बंजारा समुदायों के लोग अब भी पशु-पक्षियों के संकेतों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए लाल चींटियां जब अपने अंडे इधर-उधर ले जाती हैं, तो यह बारिश के करीब आने का संकेत होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के इन जीवों की सूझबूझ को दर्शाता है, जो मौसम की सटीक जानकारी देते हैं।

राजस्थान में मारवाड़ के गांवों में भी मौसम के पूर्वानुमान के लिए आज भी प्रकृति के संकेतों का अनुसरण किया जाता है। जहां एक ओर विज्ञान ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का विकास किया है, वहीं दूसरी ओर ये पारंपरिक तरीके आज भी बड़े काम आते हैं। पशु-पक्षियों के व्यवहार में मौसम के महत्त्वपूर्ण संकेत छिपे होते हैं। यह पारंपरिक ज्ञान न केवल ग्रामीणों के लिए, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक अहम संदर्भ बन चुका है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। प्राचीन समय से चली आ रही ये पद्धतियां अब आधुनिक विज्ञान के माध्यम से और अधिक प्रमाणित हो रही हैं।

पक्षियों और अन्य जीवों के पारंपरिक संकेतों के कुछ अर्थ होते हैं। सांप का पेड़ों पर चढ़ना बारिश की संभावना का पूर्वानुमान है। इसी

तरह लोमड़ी की उपस्थिति खेतों में चूहों का नियंत्रण होने का संकेत देती है। मौसम के साथ जीवन से पक्षियों के संकेत भी जुड़े हुए हैं, जैसे चिड़िया अथवा गौरैया का घर में घोंसला बनाना खुशहाली और तरक्की का संकेत है। पक्षियों के मौसम के संकेत में उनकी उड़ान की

> **पशु-पक्षियों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को हमारे पूर्वजों ने पूरा मान और सम्मान दिया है। मनुष्य लंबे समय से इनके व्यवहार को बदलते मौसमों के संकेतक के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। कई लोक कथाएं और किस्से हैं, जो बताते हैं कि पक्षियों की बढ़ती या घटती गतिविधि एक अध्याय के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है। हम में से ज्यादातर लोग इस जुड़ाव को भूल चुके हैं, लेकिन कोई भी पक्षी प्रेमी सर्दियों के आखिरी नीरस दिनों में पक्षियों को रंग-बिरंगे रंग में रंगते देखने के उत्साह के बारे में जरूर बता देगा। जब पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपने पंख फड़फड़ाते हैं, तो मौसम में बदलाव की उम्मीद की जाती है।**

ऊंचाई (कम ऊंचाई पर उड़ना बारिश का संकेत है, जबकि ऊंची उड़ानें अच्छे मौसम का संकेत देती हैं), उनकी आवाज (जैसे उल्लू का बोलना या मोर का नाचना बारिश का संकेत माना जाता है) और उनका भोजन व्यवहार (तूफान से पहले खूब खाना) शामिल है। कुछ ग्रामीण परंपराएं पक्षियों के घोंसले बनाने की जगह को भी मौसम का सूचक मानती हैं। उल्लू का चीखना और गौरैया का धूल में लोटना बारिश का संकेत माना जाता है। यदि कौवे कांटेदार पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, तो इसे बारिश कम होने की संभावना के रूप में देखा जाता है।

इसी तरह पक्षियों का आसमान में ऊंची उड़ान भरना अच्छे मौसम का संकेत होता है, यानी बारिश की कोई संभावना नहीं होती। जोड़े में उड़ने वाले कौवे भी अच्छे मौसम का संकेत देते हैं। इसी तरह तूफान से पहले पक्षी वसा जमा करने के लिए अधिक सक्रिय हो जाते हैं और खूब खाना खाते हैं। बारिश आने पर मुर्गियां बेचैन हो जाती हैं या धूल में खुद को रगड़ती हैं। हंस की छाती की हड्डी का लाल या गहरे रंग का होना ठंडी और तूफानी सर्दी का संकेत हो सकता है। यदि सारस आकाश में गोलाकार परावलय बना कर उड़ते हैं, तो यह शीघ्र वर्षा का संकेत है। पेड़ों पर दीमक का तेजी से घर बनाना अच्छी वर्षा का संकेत है। जब पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपने पंख फड़फड़ाते हैं, तो मौसम में बदलाव की उम्मीद की जाती है। वहीं चातक को बारिश का पक्षी माना जाता है। इसका आगमन मानसून के मौसम का संकेत है। इस तरह पशु-पक्षियों की हरकतों को देख कर मौसम का काफी हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

असल में यह हमारा पशु-पक्षियों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान है, जिसे हमारे पूर्वजों ने पूरा मान और सम्मान दिया है। मनुष्य लंबे समय से पशु-पक्षियों के व्यवहार को बदलते मौसमों के संकेतक के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। कई लोक कथाएं और किस्से हैं, जो बताते हैं कि पक्षियों की बढ़ती या घटती गतिविधि एक अध्याय के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है। हम में से ज्यादातर लोग इस जुड़ाव को भूल चुके हैं, लेकिन कोई भी पक्षी प्रेमी आपको सर्दियों के आखिरी नीरस दिनों में पक्षियों को रंग-बिरंगे रंग में रंगते देखने के उत्साह के बारे में जरूर बता देगा। सामान्य पक्षियों की तरह प्रवासी पक्षी भी कई अनुमान बताते हैं, जैसे 'माकिंगबर्ड' और 'ब्लैकबर्ड' का रात भर चहचहाना बताता है कि गर्म दिन आने वाले हैं। कई प्रवासी पक्षी सर्दियों के आगमन अथवा जाने के बारे में इशारा करते हैं।

केवल पर्यावरण की बात करें, तो पक्षियों का अध्ययन पारिस्थितिकी संतुलन को समझने में मदद करता है, क्योंकि वे कीट नियंत्रण, परागण और बीज प्रसार में अहम भूमिका निभाते हैं। पक्षी पर्यावरण में हो रहे बदलाव के शुरुआती संकेत देते हैं। उनकी आबादी में गिरावट आवासों के क्षरण या जलवायु परिवर्तन का संकेत हो सकती है। पक्षी कीटों को नियंत्रित करते हैं, बीज फैलाते हैं और परागण में मदद करते हैं, जो मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई पौधों के लिए अहम है। पक्षी मृत जीवों और कचरे को साफ करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन उनके व्यवहार, प्रवास, प्रजनन और शारीरिक विशेषताओं को समझने में इंसान की पूरी तरह से मदद करता है। हमें केवल इस ज्ञान की समझ होने और इसके वैज्ञानिक प्रयोगों को पहचानने की जरूरत है।

दुनिया मेरे आगे

आत्मबल का सहारा

राजेंद्र बज

जमाने की नजरों में हम कैसे हैं? यह जानने के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। न ही कोई हमें यह समझा पाएगा कि हम कैसे हैं? दरअसल, बहुत संभव होता है कि कोई हमारे प्रति आग्रह या दुराग्रह रखे। ऐसी स्थिति में अपने आप से अपना वास्तविक परिचय जानने के लिए हमें अपनी अंतरात्मा को ही टटोलना होगा। अंतरात्मा की गवाही इस तथ्य की पुष्टि स्पष्ट रूप से कर सकेगी कि वास्तव में हम कैसे है? निश्चित रूप से जब हम अपनी पहचान कर लेते हैं, तब अंतर्मन में किसी प्रकार के बोझ से बाधित नहीं होते। जीवन एकदम सहज और सरल हो जाता है। हमारा यह स्वभाव एक प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को श्रृंगारित करने लगता है।

हम क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे है? क्या कुछ हम कर चुके और क्या कुछ हम करना चाह रहे थे? आने वाले दौर में हम अपने आप को किस मुकाम पर लाकर खड़ा करना चाह रहे थे? क्या कुछ हम पा चुके और क्या खो चुके? अब तक की सारी जिंदगी जमाने भर की उठापटक में गुजर गई कि आखिरकार हमने क्या खोया और क्या पाया? इस तरह के तमाम सवालों का सही जवाब और किसी के एक सवाल का भी नहीं। मगर हमारी अपनी अंतरात्मा को बखूबी ज्ञात होता है। हालांकि जाहिर तौर पर हम अपने अंतर्मन की वास्तविक दशा और मनोदशा को खुलकर अभिव्यक्त नहीं करते। लेकिन हम क्या हैं, यह गवाही तो हमारा मन देता ही रहता है।

हमारा आचार-विचार और व्यवहार हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। इस दृष्टि से हर किसी के बारे में मतभिन्नता बहुत स्वाभाविक होती है। बहुत संभव होता है कि कोई किसी के लिए अच्छे से अच्छा हो और किसी के लिए बुरे से बुरा हो। ऐसी स्थिति में जब हम यह मूल्यांकन करना चाहें कि हम वास्तव में क्या हैं, तब स्वयं के बारे में निष्पक्ष तथा तटस्थ अवधारणा की पुष्टि हमारी अंतरात्मा ही करती है। वास्तव में आदमी जमाने को धोखा दे सकता है और स्वयं भी धोखे में रह सकता है, लेकिन यह संभव नहीं कि कोई लंबे समय तक धोखे में रह सके। अंतरात्मा की गवाही नकारात्मक होने पर अपराधबोध और सकारात्मक होने पर आत्मबल में वृद्धि करती है।

> **बहुत संभव होता है कि कोई किसी के लिए अच्छे से अच्छा हो और किसी के लिए बुरे से बुरा हो। ऐसी स्थिति में जब हम यह मूल्यांकन करना चाहें कि हम वास्तव में क्या हैं, तब स्वयं के बारे में निष्पक्ष तथा तटस्थ अवधारणा की पुष्टि हमारी अंतरात्मा ही करती है।**

दरअसल, व्यक्ति विशेष के अंतरंग और बहिरंग में एकरूपता हो, ऐसी अपेक्षा की जाती है, लेकिन इस अपेक्षा की कसौटी पर हर कोई खरा उतर सके, यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति विशेष के प्रति आम धारणा चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह धारणा पूर्ण रूप से सकारात्मक या पूर्ण रूप से नकारात्मक भी हो सकती है। आजकल के जमाने में सर्वमान्य शख्सियत की परिकल्पना दिवास्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। यह बहुत संभव होता है कि नकारात्मक व्यक्ति के पक्ष में कुछ सकारात्मक बिंदु भी हों। ठीक इसी तरह सकारात्मक में भी नकारात्मकता के अंश को खोजा जा सकता है।

गरज यह कि इस संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है। सामान्य बोलचाल में भी कहा गया है कि लोगों ने राजा राम को नहीं छोड़ा तो आप हम क्या है! ऐसी स्थिति में यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने स्तर पर एकदम सही रहें। हमारा सकारात्मक सोच-विचार तथा कार्य और व्यवहार पूर्ण रूप से सात्विक रहे। एक अर्थ में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को हम खुद ही समय-समय पर तटस्थ एवं निष्पक्ष रूप से आकलित कर प्रमाणित करते रहें। यही आत्म-मूल्यांकन का सिलसिला हमारे अपने अंतर्मन की संतुष्टि का अहम कारण बन सकता है। इससे आत्मबल में वृद्धि होती है, जिसके चलते जीवन संवर जाता है।

हमारा हाव-भाव और व्यवहार भी जमाने भर को हमारे व्यक्तित्व एवं कृतित्व के मूल्यांकन का आधार देता है। चित्त की सहजता और सरलता के मनोभाव आचार-विचार और व्यवहार से परिलक्षित होते हैं। इसके अलावा, चित्त की कुटिलता का आकलन भी प्रयुक्त शब्दावली और भाव-भंगिमा के आधार पर सहज ही किया जा सकता है। दरअसल, इस सहज मनोविज्ञान को औसत स्तर के आम व्यक्ति के लिए भी समझना कोई दुष्कर नहीं है। यह निश्चित है कि जब हम सहज और सरल होते हैं, तो हमारा आत्मबल अत्यंत विकसित अवस्था में आकर सकारात्मक वातावरण का सृजन करने में प्रबल रूप से सहायक होता है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारे अपने आसपास के परिवेश में, जान-पहचान के लोगों के बीच हमारे व्यक्तित्व एवं कृतित्व को लेकर आमतौर पर कोई न कोई धारणा अवश्य होती है। यह धारणा केवल नकारात्मक या केवल सकारात्मक ही हो, यह कतई आवश्यक नहीं होता। ऐसा भी होता है कि जमाने की निगाहों में हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति मिली-जुली धारणा हो। ऐसी स्थिति में कभी-कभी हमें संदेह का लाभ भी मिल जाया करता है। दरअसल, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हर एक दृष्टि से परिपूर्ण नहीं हो सकता। हर किसी के व्यक्तित्व और कृतित्व के आकलन में परस्पर विरोधाभास की स्थिति बहुत स्वाभाविक होती है।

ऐसी स्थिति में हमें अपने प्रति जनमानस में व्याप्त सकारात्मक या नकारात्मक धारणा को लेकर न तो उत्साहित होना चाहिए और न ही निराश। हर किसी के लिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन करने के अपने अलग-अलग पैमाने हुआ करते हैं। उसके आधार पर किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। इन तमाम संदर्भों में हमें हमारे अंतर्मन की आवाज सुनने और सुनते रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम अपने स्तर पर अपनी जगह अगर सही हैं, तो जमाने की विपरीत हवा भी कभी हमारा अहित नहीं कर सकेगी।

दुविधा में किसान

भारतीय कृषि क्षेत्र आज एक गहरी दुविधा में फंसा हुआ है। एक ओर कीटनाशकों और रासायनिक खादों के बढ़ते उपयोग से मनुष्य की सेहत से संबंधित संकट बढ़ रहा है, दूसरी ओर वही रसायन किसानों को बाजार में टिकाए हुए है। ऐसे में किसान क्या करे? बिना रसायनों के खेती की पैदावार कम होती है और कई बार तो पौधों को बीमारियों से फसल तबाह हो जाती है। बाजार का पहला नियम यही है कि जो दिखेगा, वही बिकेगा। जैविक खेती की चर्चा बहुत होती है, पर वास्तविकता यह है कि जैविक खाद की उपलब्धता आज भी बेहद सीमित है। प्रमाणन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि छोटे किसान इसे समझ नहीं पाते। कुछ किसान हिम्मत करके जैविक खेती शुरू भी कर दें, तो शुरुआती वर्षों में उत्पादन में गिरावट उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ देती है। दूसरी ओर उपभोक्ताओं की मजबूरी है कि उन्हें सस्ते दामों में उत्पाद खरीदने होते है, चाहे वे रसायनयुक्त क्यों न हो। ऐसी स्थिति में केवल किसान को दोष देना एकतरफा निर्णय होगा। किसान तभी रसायन-मुक्त खेती अपना पाएगा, जब उसे बाजार, सरकार और समाज, तीनों का समर्थन मिलेगा। जाहिर है कि समाधान किसानों की मजबूरी समझे बिना नहीं निकल पाएगा।

– मो अजहर आलम अंसारी, कुकरौन अमारी

प्रकृति से खिलवाड़

आज हर कोई प्रकृति के संरक्षण की बात करता है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर कार्य करने की बात आती है, तो कदम पीछे खींच लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में छह लाख पेड़ों को काटने की योजना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुई है। मध्य भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल सिंगरौली का कायाकल्प करने की तैयारी चल रही है। सरकार भले ही इन वृक्षों की जगह नए पौधे लगाने की बात कर रही है, लेकिन क्या ये वृक्षारोपण उतना ही कार्बन सोख पाएगा, जितना कि इन लाखों पेड़ों की क्षमता है? एक तरफ हम वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण और जलवायु संकट से निपटने के लिए नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का दावा करते हैं, वहीं दूसरे ओर पेड़ो की कटाई कर वर्ष 2070 तक कार्बन शून्य के लक्ष्य से और दूर होते जा रहे हैं। सवाल है कि विकास के नाम पर हरित संपत्ति का विनाश कहां तक उचित है? सरकार और समाज को इस पर गंभीरता से गौर करना होगा।

– दिनेश शाह, सिंगरौली, मप्र

संरक्षण की ऊर्जा

हमारे देश में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऊर्जा के संरक्षण और इसके सही उपयोग के प्रति जागरूक करना है। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा के मुख्य स्रोत पानी, रसोई गैस, बिजली, पेट्रोल और डीजल ही माने जा सकते हैं। अगर इनका सही और उचित तरीके से इस्तेमाल करें, तो इसका सुख हम भावी पीढ़ी को भी दे सकते हैं। साथ ही इससे हम पर्यावरण को संभालने में भी अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के संकट से बचना है, तो अक्षय ऊर्जा पर जोर देना होगा। अक्षय उर्जा पैदा करने में पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे प्रदूषक तत्त्व नहीं निकलते हैं और इसके स्रोत का भी पुनः-भरण होता रहता है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें अक्षय ऊर्जा के प्रति गंभीरता से काम करें, तो भारत अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

रसायनों की मुश्किल

'कृषि सेहत में सुधार की नई संभावना' (आलेख, 13 दिसंबर पढ़ा)। इसमें दोराय नहीं कि आज कृषि क्षेत्र में रसायनों के इस्तेमाल से मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में खेती में होम्योपैथी एक ऐसा नवाचार है, जो न केवल फसलों की गुणवत्ता और उपज को बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम होगा। होम्योपैथी का यह नया प्रयोग पारंपरिक खेती की कई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, जैसे- जल संरक्षण और प्रदूषण में कमी, भूजल के स्तर में बढ़ोतरी, मिट्टी की गुणवत्ता का बढ़ना और खेती के लिए रसायनों पर निर्भरता से मुक्ति। कृषि-होम्योपैथी से पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे वे रोगों से लड़ने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। यह पद्धति मिट्टी के प्राकृतिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है, जो दीर्घकालिक टिकाऊ कृषि के लिए महत्त्वपूर्ण है।

– प्रसिद्ध यादव, फुलवारी, पटना

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

विशेष
जनसत्ता | 15 दिसंबर, 2025

एआइ क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी क्षमताओं के मामले में भारत तीसरे स्थान पर : रपट

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 'ग्लोबल एआइ वाइब्रेंसी टूल' की हालिया रपट में भारत ने कृत्रिम मेधा (एआइ) में विश्व की प्रतिस्पर्धी क्षमताओं के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। 'ग्लोबल एआइ वाइब्रेंसी टूल' शोध एवं विकास, प्रतिभा, अवसंरचना सहित सात प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का आकलन करता है। नवंबर में जारी रपट के अनुसार, भारत ने चार स्थान की छलांग लगाई है और कृत्रिम मेधा में प्रतिस्पर्धी क्षमता के मामले में ब्रिटेन के साथ-साथ एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2024 के 'ग्लोबल वाइब्रेंसी' सूचकांक में भारत 21.59 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके बाद दक्षिण कोरिया (17.24 अंक) और ब्रिटेन (16.64 अंक) का स्थान है। भारत 2023 में सातवें स्थान पर था, जबकि ब्रिटेन छठे से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। रपट के अनुसार, दोनों देशों ने वैश्विक कृत्रिम मेधा व्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हाल के वर्षों में कई प्रमुख योजनाओं को दोबारा सक्रिय किया है। एआइ इंडेक्स रपट 2025 में देशों की रैंकिंग वर्ष 2024 की 'ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग' के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

हवाई अड्डों के आसपास जीपीएस से छेड़छाड़ पर और कसेगा शिकंजा

सर्वेश कुमार

सख्ती

पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली समेत देश के अलग अलग हवाई अड्डों के आसपास जीपीएस और जीएनएनएस से छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने वैश्विक मानकों के अनुरूप उपायों को लागू किया है। अब उड़ानों को जीपीएस से छेड़छाड़ (स्पूफिंग) होने पर परेशानी न हो इसके लिए पुख्ता मानकों को लागू किया जा रहा है।

नवंबर में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आइजीआइ) पर उड़ानों के उतरने के दौरान जीपीएस के साथ छेड़छाड़ की वजह से प्रभावित उड़ानों के मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इस पर शिकंजा कसने के लिए पुख्ता कदम उठाए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए)ने आइजीआइ हवाई अड्डे के आसपास जीपीएस स्पूफिंग या जीएनएसएस हस्तक्षेप घटनाओं की वास्तविक समय पर सूचना देने के लिए 10 नवंबर को नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर दी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) ने वायरलेस मानिटरिंग संगठन से ऐसी घटनाओं के लिए स्रोत जिम्मेवार की पहचान करने का भी आग्रह किया है।

नवंबर के पहले हफ्ते में आइजीआइ के रनवे 10 पर जीपीएस से छेड़छाड़ की वजह से कुछ उड़ानें प्रभावित हुई थीं, लेकिन दूसरे रनवे के छोरों पर उड़ानों की आवाजाही पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था, जहां पारंपरिक मार्गदर्शक सेवाएं चालू थीं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई क्षेत्र में जीएनएसएस(जीएनएसएस) हस्तक्षेप को संबोधित करने के लिए नवंबर, 2023 से जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग की घटनाओं की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद कोलकाता, अमृतसर, मुंबई, हैदराबाद, बंगलुरु और चेन्नई हवाई अड्डे समेत देश के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों से नियमित रपट प्राप्त हो रही हैं। नवंबर में स्पूफिंग की घटनाओं के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने वायरलेस मानिटरिंग संगठन से हस्तक्षेप कर, स्पूफिंग के स्रोत की पहचान करने का भी अनुरोध किया है। उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान, वायरलेस निगरानी संगठन को डीजीसीए और एएआइ द्वारा साझा किए गए अनुमानित स्पूफिंग स्थान विवरण के आधार पर स्पूफिंग के स्रोत की पहचान करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्यसभा में एक दिसंबर को एस निरंजन रेड्डी द्वारा आईजीआई हवाई अड्डे पर जीपीएस स्पूफिंग के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्री ने माना कि इस तरह की घटना हुई थी। जवाब में उन्होंने भारत ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और तरीकों से अद्यतन रहने के लिए वैश्विक मानकों को भी लागू कर रहा है ताकि सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहे। यह भी कहा कि विमानन क्षेत्र के लिए वैश्विक साइबर सुरक्षा खतरे रैंसमवेयर या मैलवेयर के रूप में हैं। इन खतरों से साइबर सुरक्षा में बढ़ोतरी के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क सहित अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा समाधानों को लागू किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत, सर्वोत्तम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के मुताबिक, पारंपरिक, भू-आधारित मार्गदर्शन और निगरानी प्रणालियों का एक न्यूनतम परिचालन नेटवर्क (एमओएन) बनाए रखना जारी रखे हुए है।

जीपीएस हस्तक्षेप की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय: आइएटीए

अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आइएटीए) ने कहा कि विमानों में दिशा-निर्देशन प्रणाली से जुड़े जीपीएस संकेतों में छेड़छाड़ और बाधा डालने की घटनाओं में बढ़ोतरी एक गंभीर चिंता का विषय है और ऐसे में पायलटों को अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आइएटीए विश्व की लगभग 360 विमानन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनके माध्यम से वैश्विक हवाई यातायात का 80 फीसद से अधिक हिस्सा संचालित होता है। इस संगठन में एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट जैसी भारतीय एयरलाइन भी शामिल हैं। हाल के दिनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमृतसर, हैदराबाद, बंगलुरु और चेन्नई हवाई अड्डों पर भी विमानों के जीपीएस संकेतों में छेड़छाड़ और हस्तक्षेप की घटनाएं सामने आई हैं। इस सप्ताह जिनेवा में आयोजित बैठकों के दौरान आईएटीए अधिकारियों ने कहा कि जीपीएस संकेतों में हस्तक्षेप की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो चिंता का विषय है।

कोविड टीकाकरण और अचानक मृत्यु के बीच वैज्ञानिक संबंध नहीं

जनसत्ता विशेष

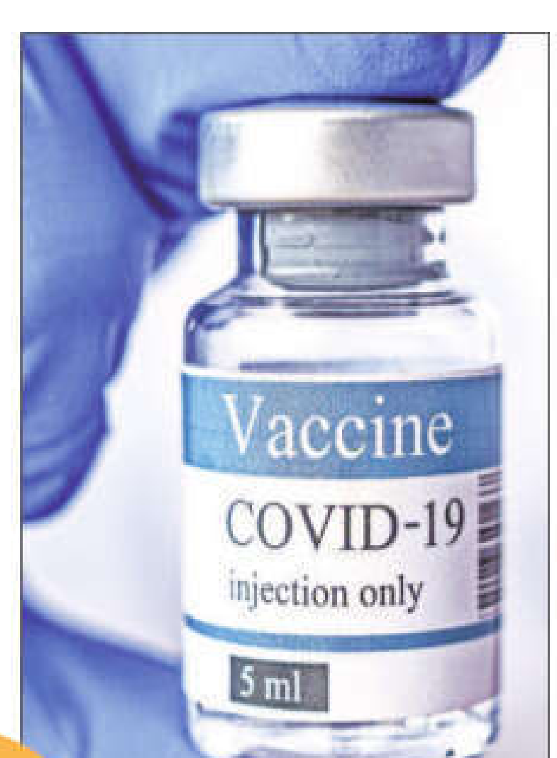

दिल्ली के एम्स में किए गए एक व्यापक, एक वर्षीय शव परीक्षण-आधारित अवलोकन अध्ययन में कोविड-19 टीकाकरण और युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है, जो कोविड टीकों की सुरक्षा की पुष्टि करता है।

अध्ययन में कहा गया है कि युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है जिसके लिए लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों की आवश्यकता है, अंतर्निहित कोरोनरी धमनी रोग इसका प्रमुख कारण बना हुआ है और श्वसन संबंधी और अस्पष्टीकृत मौतों की आगे जांच की जानी चाहिए।

शोध परिणामों ने टीकों और ऐसी मौतों के बीच किसी भी प्रत्यक्ष संबंध को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। इसके बजाय, वे पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों, आनुवंशिक कारकों, जीवनशैली विकल्पों और कुछ मामलों में, कोविड-19 के बाद की जटिलताओं के संयोजन को अंतर्निहित कारणों के रूप में इंगित करते हैं।

शोध

भारत के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए व्यापक अध्ययनों में कोविड-19 टीकाकरण और वयस्कों, विशेष रूप से 18-45 आयु वर्ग के लोगों में अचानक मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है। एम्स सहित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अध्ययनों से यह पुष्टि हुई है कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण और युवा वयस्कों में अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई सीधा वैज्ञानिक संबंध नहीं है। ये मौतें आनुवंशिकी, जीवनशैली, या कोविड-19 के बाद की जटिलताओं जैसी अन्य वजहों से हो सकती हैं, और टीके सुरक्षित व प्रभावी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ये निष्कर्ष भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एआइआइएमएस), नई दिल्ली द्वारा किए गए विस्तृत शोध पर आधारित हैं।

कोविड-19 महामारी के बाद अचानक और अस्पष्ट मौतों को लेकर बढ़ती जन चिंता के बीच इन अध्ययनों की शुरुआत की गई थी। हालांकि, शोध परिणामों ने टीकों और ऐसी मौतों के बीच किसी भी प्रत्यक्ष संबंध को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। इसके बजाय, वे पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों, आनुवंशिक कारकों, जीवनशैली विकल्पों और कुछ मामलों में, कोविड-19 के बाद की जटिलताओं के संयोजन को अंतर्निहित कारणों के रूप में इंगित करते हैं। आइसीएमआर के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (एनआइई) द्वारा किए गए प्रमुख अध्ययनों में से एक, 'भारत में 18-45 वर्ष की आयु के वयस्कों में अज्ञात कारणों से होने वाली अचानक मृत्यु से जुड़े कारक' शीर्षक से एक बहुकेंद्रीय मिलानित केस-कंट्रोल अध्ययन था। मई और अगस्त 2023 के बीच किए गए इस अध्ययन में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 तृतीयक देखभाल अस्पताल शामिल थे। इसमें उन मामलों की जांच की गई जिनमें स्वस्थ दिखने वाले व्यक्तियों की अक्तूबर 2021 और मार्च 2023 के बीच अचानक मृत्यु हो गई। परिणामों में कोविड-19 टीकाकरण के बाद अज्ञात कारणों से होने वाली अचानक मृत्यु के जोखिम में कोई वृद्धि नहीं पाई गई।

इसी क्रम में, एम्स नई दिल्ली, आइसीएमआर के सहयोग से युवाओं में अचानक होने वाली अज्ञात मौतों के कारणों का पता लगाना शीर्षक से एक भावी अध्ययन कर रहा है। हालांकि अध्ययन अभी जारी है, प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि 'मायोकार्डियल इन्फार्क्शन' (दिल का दौरा) युवा वयस्कों में अचानक होने वाली मौतों का प्रमुख कारण बना हुआ है। कारणों का तरीका पिछले वर्षों के रुझानों के अनुरूप ही बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, कई मामलों में, आनुवंशिक उत्परिवर्तन को भी एक सहायक कारक के रूप में पहचाना गया है।

दोनों अध्ययनों के निष्कर्ष सामूहिक रूप से युवा वयस्कों में अचानक होने वाली मौतों की ठोस वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और भारत में लगाए गए कोविड-19 टीकों की सुरक्षा को पुष्ट करते हैं। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि टीकों को ऐसी मौतों से जोड़ने वाली गलत सूचना या अपुष्ट दावे न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत हैं, बल्कि टीकाकरण कार्यक्रमों में जनता के विश्वास के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अटकलबाजी और निराधार दावों को फैलाने से टीकाकरण के प्रति हिचकिचाहट बढ़ सकती है। एक ऐसा परिणाम जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को कमजोर कर सकता है और महामारी के प्रबंधन में हुई प्रगति को उलट सकता है।

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष के पीछे जटिल राजनीति

जनसत्ता विशेष

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद सात दिसंबर को फिर से शुरू हो गया। तब से इस संघर्ष में 20 से अधिक लोग कथित तौर पर अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें थाईलैंड के चार और कंबोडिया के 11 नागरिक शामिल हैं। इससे पहले जुलाई में सीमा विवाद भड़क गया था। दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगभग पांच लाख लोगों को निकाला जा चुका है।

विश्लेषण

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद सात दिसंबर को फिर से शुरू हो गया। तब से इस संघर्ष में 20 से अधिक लोग कथित तौर पर अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें थाईलैंड के चार और कंबोडिया के 11 नागरिक शामिल हैं। इससे पहले जुलाई में सीमा विवाद भड़क गया था। दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगभग पांच लाख लोगों को निकाला जा चुका है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल और कंबोडिया के उनके समकक्ष हुन मानेत द्वारा मलेशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) की बैठक के दौरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के दो महीने से भी कम समय में सीमा विवाद एक बार फिर भड़क गया। संघर्ष को समाप्त कराने में मध्यस्थता करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को 'ऐतिहासिक' बताया था। लेकिन एक बार फिर, दोनों देश दोबारा लड़ रहे हैं?

अनुतिन के लिए शांति समझौता एक स्पष्ट घरेलू चुनौती बन गया क्योंकि सीमा विवाद के कारण अति-राष्ट्रवादी भावनाएं उमड़ पड़ीं। अनुतिन ने हाल ही में पैतोंगटार्न शिनावात्रा की जगह ली थी। शिनावात्रा को कंबोडिया के प्रति अत्यधिक सुलहवादी रुख अपनाने के कारण प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था।

अनुतिन, सितंबर की शुरुआत में प्रगतिशील 'पीपुल्स पार्टी' के समर्थन से सत्ता में आए। उन्होंने अल्पमत सरकार का नेतृत्व करने और पदभार ग्रहण करने के चार महीने के भीतर ही चुनाव कराने पर सहमति जताई। तब से, उन्होंने शक्तिशाली सेना और थाईलैंड के मतदाताओं के अधिक रूढ़िवादी वर्गों को लुभाकर अपनी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने का प्रयास किया। चूंकि ये दोनों समूह संघर्ष के पक्ष में थे इसलिए अनुतिन कमजोर दिखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्हें नवंबर में इस बात का एहसास हुआ, जब उन्हें सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने के लिए माफी मांगनी पड़ी कि थाईलैंड ने भी कंबोडिया की तरह अपने पड़ोसी देश की सीमा पर अतिक्रमण किया है। अनुतिन ने सत्ता संभालने के कुछ ही हफ्तों के भीतर राष्ट्रवादी रुख को और मजबूत करते हुए 2000 के दशक की शुरुआत के सीमा विवाद पर दो द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों को जनमत संग्रह के लिए रखने की घोषणा की। इन समझौता ज्ञापनों में दोनों देशों को अपनी विवादित भूमि और समुद्री सीमाओं के सीमांकन पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। जनमत सर्वेक्षणों से पता चला कि थाईलैंड के कई नागरिक इन समझौता ज्ञापनों को निलंबित करने के लिए जनमत संग्रह का समर्थन करेंगे। थाईलैंड की सेना कभी भी पूरी तरह से नागरिक नियंत्रण में नहीं रही है। हालांकि, अनुतिन की सीमा विवाद से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को छूट देने की इच्छा, बिना किसी और राजनयिक विकल्प पर विचार किए, देश के लोगों की उस पुरानी धारणा को बल देती है, जिसमें सेना को राष्ट्र के निस्वार्थ संरक्षक के रूप में चित्रित किया जाता है। नए सिरे से शुरू हुए सीमा विवाद के महज पांच दिन बाद अनुतिन ने 11 दिसंबर को संसद भंग कर दी।

कंबोडिया की बात करें तो हुन मानेत भी घरेलू दबावों से अछूते नहीं हैं। उन्हें धीमी आर्थिक वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके विकासवादी एजेंडे के विपरीत है। सीमा विवाद ने इसमें योगदान दिया लेकिन अमेरिकी शुल्क, कंबोडिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और विदेशी निवेशक चीन से घटते निवेश का भी इसमें योगदान है। फिलहाल, हुन मानेत सीमा विवाद के दौरान उत्पन्न हुए एकजुटता के प्रभाव का लाभ उठाकर लोगों का ध्यान इन मुद्दों से हटा सकते हैं। कंबोडिया में लगातार फैल रहे घोटालेबाजी नेटवर्क के कारण देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के विभिन्न निर्णयों ने प्राचीन प्रेह विहार मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर कंबोडिया के स्वामित्व की पुष्टि की है, जो थाईलैंड के साथ लगातार सीमा संघर्ष का स्थल रहा है।

केंद्र की देरी से जमीन तक नहीं पहुंच पा रही अमृत योजना

पंकज रोहिला

रपट

शहरों में पेयजल - सीवर योजनाओं को लागू करने के लिए शुरू की गई अमृत योजना के लिए राज्यों को वक्त पर पैसा नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार का यह हिस्सा नहीं मिल पाने की वजह से ये योजनाएं बीच में फंसी हैं। अमृत और अमृत - 2 के तहत शुरू की गई योजनाओं को लेकर जारी रपट में यह बात सामने सामने आई है। इस पर हाल ही में संसदीय समिति ने चिंता दर्ज कराई है और कहा है कि इस लापरवाही की वजह से पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने में लगातार देरी हो रही है। हालांकि रपट में सरकार ने खुद दावा किया है कि देश में आगामी 2030 तक शहरी क्षेत्रों में पानी की मांग दो गुना तक बढ़ सकती है।

रपट में यह भी सामने आया है कि दुनिया के बीस सबसे अधिक जल संकटग्रस्त शहरों में से पांच भारत में हैं और इन शहरों में दिल्ली भी शामिल है, जो कि वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त भारत में 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 80 लाख बच्चे स्वास्थ्य और स्वच्छता संबगंधित कमियों के कारण जोखिम में हे। ऐसे ही जोखिमों को कम करने के लिए अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की शुरुआत की गई थी। इसके तहत पांच सौ चुनिंदा शहरों में 65 फीसद शहरी आबादी के लिए कार्य करना था और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर जल, सीवर समेत अन्य योजनाओं को लागू करना था।

रपट बताती है कि अमृत एक योजना के तहत 83550 करोड़ रुपए की थी, इस योजना में 77640 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इस लागत से कुल 6010 परियोजनाओं को शुरू किया गया है और 95 फीसद भौतिक कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। कुल राशि में अब तक भी केवल 87 फीसद धनराशि का ही प्रयोग किया गया है। अभी भी इस योजना के तहत स्वीकार की गई 4073 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। इन योजनाओं को अमृत दो योजना के तहत शामिल किया गया था, जो पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने में लगातार देरी को दर्शाता है। अमृत मिशन के तहत कुल 4.68 करोड़ घरों तक नल से पानी और सीवर सेवाओं का विस्तार 31 से 62 फीसद करना था।

केंद्र सरकार ने अमृत दो के तहत लगभग 1.90 करोड़ रुपए की 8791 परियोजनाओं को मंजूरी दी दी है। रपट बताती है कि इन परियोजनाओं में से केवल 1.54 लाख करोड़ की विस्तृत कार्य योजना (डीपीआर) तैयार किए गए हैं और 1.47 लाख करोड़ रुपए के लिए निविदा (एनआइटी) व 1.18 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध दिए गए हैं। लेकिन भौतिक कार्य केवल 48050 करोड़ रुपए का ही है। जबकि व्यय केवल 35520 करोड़ रुपए का ही हुआ है। जो कि विभिन्न परियोजनाओं में प्रक्रियात्मक अड़चनों और धीमी जमीनी प्रगति का दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त अब तक केवल 12724 करोड़ रुपए ही जारी किए गए है, जो कि केंद्रीय हिस्से का केवल 19 फीसद है। ये पैसा नहीं मिलने की वजह से राज्यों व निकायों का योगदान को हतोत्साहित कर सकता है। समिति ने यह भी साफ कहा कि इस परियोजनाओं को लेकर राज्यवार आवंटन में काफी असमानताएं सामने आई है।

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति ने संसद से सिफारिश की है कि समिति ने जनसंख्या परिवर्तन के मद्देनजर 2050 तक भारत की आधी से अधिक आबादी का शहरों में रहने का अनुमान जताया है और कहा है कि यह भी सवाल किया है कि यहां बढ़ने वाली आबादी के लिए केंद्र सरकार ने क्या दीर्घाकालीन समय के लिए शहरी पेयजल की मांग का अनुमान लगाने के लिए कोई व्यापक मूल्यांकन किया है। समिति ने सिफारिश की है कि बढ़ती मांग की स्थिति को देखते हुए अगले 25 से 30 वर्ष के लिए शहरी पेयजल की मांग का एक एकीकृत राष्ट्रीय स्तर का आकलन ओर अनुमान तत्काल शुरू किया जाए। इसके निष्कर्ष को एक राष्ट्रीय शहरी जल सुरक्षा नीति का आधार बनाया जाना चाहिए जो भविष्य में जल सुरक्षित शहरों को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

मस्ती

उत्तराखंड के ऋषिकेश में रविवार को लोग गंगा नदी में नौकायान का आनंद लेते हुए।

मां बनने के लिए उम्र के साथ अन्य कारण भी महत्त्वपूर्ण

जनसत्ता विशेष

विशेषज्ञ

स्त्री रोग विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय परिवारों और समाज में अक्सर मां बनने को लेकर उम्र से जुड़ी अपेक्षाएं होती हैं और जब कोई महिला 30 साल की उम्र पार कर लेती है, तो उसे चिंता होने लगती है, और यह फ्रिक अक्सर समाज और परिवार की सोच के कारण बढ़ जाती है।

हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मातृत्व के बारे में निर्णय किसी महिला द्वारा मानसिक रूप से तैयार होने, समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच के आधार पर लिया जाना चाहिए, न कि किसी निश्चित समय सीमा के आधार पर। भारत के शहरी क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव आया है, जहां महिलाएं परिवार नियोजन से पहले शिक्षा, करियर, आर्थिक स्वतंत्रता और भावनात्मक स्थिरता को प्राथमिकता देना पसंद कर रही हैं।

चिकित्सकों का कहना है कि इन बदलती वास्तविकताओं के बावजूद, महिलाओं को रिश्तेदारों और सामाजिक स्तर पर तीव्र दबाव का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर चिकित्सा तथ्यों के बजाय उम्र से संबंधित भय पर केंद्रित होता है। विशेषज्ञों के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ प्रजनन क्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती है, लेकिन इस तथ्य को लेकर चिंता या जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने चाहिए। इसके बजाय, विशेषज्ञ परामर्श और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर जोर देते हैं। 'सिल्वरस्ट्रीक मल्टीस्पेशलिटी' अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. स्वप्निल अग्रहरि ने कहा, 'उम्र और प्रजनन क्षमता के बीच स्पष्ट चिकित्सीय संबंध है, लेकिन इसे तथ्य को जिम्मेदारी से बताया जाना चाहिए। मातृत्व के वास्ते महिलाओं पर दबाव डालने के लिए उम्र का इस्तेमाल करना न तो उचित है और न ही मददगार। आज गर्भावस्था के परिणाम जीवनशैली, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और समय पर चिकित्सा सहायता जैसे कई कारकों से प्रभावित होते हैं।'

संपादकीय जागरण
सोमवार, 15 दिसंबर, 2025 : पौष कृष्ण - 11 वि. 2082

जीवन की हर कठिनाई हमें नई दिशा देने आती है

एक और आतंकी हमला

आस्ट्रेलियाई शहर सिडनी के समुद्र तट पर आतंकियों ने जिस तरह यहूदी समुदाय के लोगों को निशाना बनाया और दस से अधिक लोगों की जान ले ली, उसने जिहादी आतंक के खतरे को खौफनाक रूप में फिर से सामने खड़ा कर दिया। चूंकि हमलावरों की पहचान हो गई है, इसलिए न तो इसमें संदेह रह जाता है कि वे कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा से ग्रस्त थे और न ही इसमें कि उनका मकसद यहूदियों को ही निशाना बनाना था, क्योंकि उन पर तब हमला किया गया जब वे हनुक्का पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में समुद्र तट पर एकत्रित हुए थे। आस्ट्रेलिया सरकार ने इस दिल दहलाने वाले हमले को आतंकी कृत्य तो करार दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उस पर यह आरोप लग रहा है कि उसने उन चरमपंथी इस्लामिक समूहों की गतिविधियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जो यहूदियों को धमकाने में लगे हुए थे। इस आतंकी घटना को गाजा में हमास और इजरायल के बीच चली लंबी लड़ाई के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। इस लंबे संघर्ष ने दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ एक माहौल बनाया। यह माहौल चरमपंथी इस्लामिक समूहों की ओर से ही बनाया गया और इसके चलते अमेरिका में भी यहूदियों पर हमले हुए। इसके अतिरिक्त, पश्चिम के अन्य देशों में भी यहूदियों को निशाना बनाने की छिटपुट घटनाएं हुईं, लेकिन यह कहना समस्या का सरलीकरण करना होगा कि गाजा में इजरायल और हमास के बीच के संघर्ष ने ही कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों को उग्र होने का अवसर दिया है। यह ध्यान रहे कि पश्चिम के साथ-साथ विश्व के अन्य अनेक देशों में एक लंबे समय से अतिवादी इस्लामिक विचारधारा वाले समूह आतंकी हमले करते रहे हैं। उनमें बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए हैं।

यह स्वाभाविक है कि आस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले की वैश्विक स्तर पर निंदा होगी और शोक-संवेदनाएं व्यक्त की जाएंगी, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। दुनिया भर में जिहादी आतंक का खतरा जिस तरह उभर रहा है, उसे देखते हुए विश्व समुदाय को इस खतरे का मिलकर सामना करने की आवश्यकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकी घटनाओं का सिलसिला कायम रहने के बावजूद वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया जा पा रहा है। इससे भी खराब बात यह है कि आतंकी संगठनों को सहयोग, समर्थन एवं संरक्षण देने वाले देशों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने से बचा जा रहा है। ऐसे देशों में सबसे ऊपर पाकिस्तान का नाम आता है। विश्व समुदाय को यह समझना होगा कि आतंकवाद का सामना केवल आतंकी गतिविधियों की भर्त्सना करके नहीं किया जा सकता। इस आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व समुदाय को एकजुटता के साथ-साथ आवश्यक इच्छाशक्ति का भी परिचय देना होगा।

चिंताजनक स्थिति

दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर स्ट्रीट लाइटें न जलना अत्यंत चिंताजनक है और घोर लापरवाही है। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है, जब कोहरे में सड़क पर लाइट न होने से कट नहीं दिखाई देते और सड़क हादसे की आशंका बढ़ जाती है। रविवार रात कोहरे के समय एक्सप्रेसवे पर महिपालपुर से सिरहौल बार्डर तक अधिकतर लाइटें बंद नजर आईं। स्थिति ये थी कि वाहन चालकों को सड़क के बाईं ओर बने कट तक नहीं दिख रहे थे। कुछ वाहन चालक जो अंधेरा होने के कारण कट पार कर गए, उन्हें काफी घूमकर वापस आना पड़ा। वहीं, दिखाई न देने के कारण कट पार कर गए कुछ वाहन चालक अचानक ब्रेक लगाते भी देखे गए, जिससे पीछे से आ रहे वाहन टकराते-टकराते बचे।

> एक्सप्रेसवे पर स्ट्रीट लाइटें न होना एनएचआइ की बड़ी लापरवाही है, इसे तत्काल ठीक किया जाना चाहिए

दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी को साइबर सिटी से जोड़ता है और इसपर प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन चालक गुजरते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर अंधेरा तब है, जबकि एनएचएआइ को खेड़कीदौला स्थित टोल प्लाजा से वार्षिक 200 करोड़ की आय होती है। इतनी बड़ी धनराशि वसूलने के बावजूद एक्सप्रेसवे पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न कराना घोर निराशाजनक है। ये एक्सप्रेसवे भीषण यातायात जाम के लिए पहले से कुख्यात है। ऐसे में इसपर स्ट्रीट लाइटें न होना एनएचएआइ की बड़ी लापरवाही है, जिसे तत्काल ठीक किया जाना चाहिए। एनएचएआइ के आला अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस एक्सप्रेसवे पर स्ट्रीट लाइटों समेत सभी चीजें दुरुस्त रहें।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाने से पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलेगा?

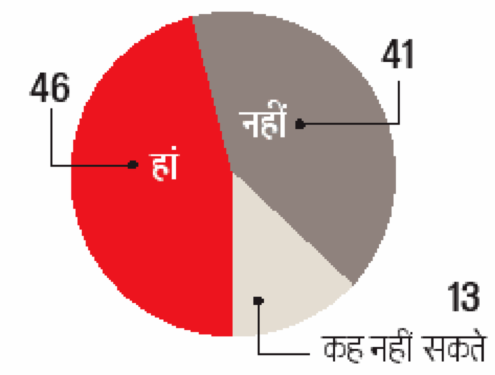

आज का सवाल

क्या भाजपा द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नितिन नबीन का चयन एक सही फैसला है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

स्थापित करने होंगे जवाबदेही के मानदंड

विवेक काटजू

इंडिगो की सेवाओं में गतिरोध से न केवल लाखों हवाई यात्रियों को पीड़ा पहुंची, बल्कि इससे भारत की छवि पर भी आघात हुआ

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस का परिचालन इस महीने की शुरुआत में ऐसा लड़खड़ाया कि अभी तक कुछ समस्याएं कायम हैं। विमानन बाजार में करीब 65 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली कंपनी की उड़ानों में देरी और उनके रद होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ना स्वाभाविक था। हालांकि अब कुछ स्थिति सुधरी है, लेकिन पूर्ण राहत अभी दूर है। सेवाओं में इस गतिरोध से न केवल लाखों हवाई यात्रियों को पीड़ा पहुंची, बल्कि इससे भारत की छवि पर भी आघात हुआ। सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए इंडिगो पर कार्रवाई भी की है। यह तो जांच में ही सामने आएगा कि इस अराजकता के क्या कारण रहे, किंतु प्रथमदृष्ट्या पायलटों के लिए अधिक विश्राम संबंधी नियमों की पूर्ति के लिए अपेक्षित प्रयास न करने को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। कंपनी के पास पायलटों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय था, पर वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।

इंडिगो प्रकरण में एक प्रश्न यह भी उभरा है कि कंपनियों के मामले में सरकार को आखिर कब हस्तक्षेप करना चाहिए? समस्याओं के पहले या उनके उत्पन्न होने के बाद? विशेषकर तब जब उनकी लापरवाही से जनता और देश को नुकसान पहुंचने की आशंका हो। यह प्रश्न राजनीतिक जवाबदेही की ओर भी ले जाता है। यह मुद्दा किसी विशेष सरकार या पार्टी से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक वर्ग और भारत की राजनीतिक संस्कृति से संबंधित है। हमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी पीएसयू और निजी कंपनियों की प्रकृति एवं स्वरूप में अंतर को भी समझना होगा। पीएसयू सरकारी स्वामित्व में होती है। उनकी जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों और विभागों की होती है। संबंधित मंत्री के माध्यम से सरकार इन सार्वजनिक कंपनियों को लेकर संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। निजीकरण से पहले विमानन में सरकारी कंपनी को ही अनुमति थी। तब एयरलाइंस ने अपने परिचालन को लेकर ऐसी लापरवाही दिखाई होती तो नागरिक उड्डयन मंत्री को संसद में प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता।

यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का वास्तविक संचालन-प्रबंधन भी खांटी पेशेवरों द्वारा किया जाता है और संबंधित मंत्रियों से अपेक्षा नहीं की जाती कि वे रोजमर्रा के कामकाज में हस्तक्षेप करें। हालांकि, यह सुनिश्चित करना उनका राजनीतिक कर्तव्य है कि वे इसके लिए उचित व्यवस्था बनाएं। इस क्रम में वे वरिष्ठ लोकसेवकों को दायित्व सौंपते हैं। संबंधित लोक सेवकों को इन कंपनियों की स्थिति के बारे में सूचित रखना होता है। उनकी ओर से किसी भी उभरती समस्या के बारे में चेतावनी दी जाए। ऐसी संभावित समस्या जिससे

इंडिगो एयरलाइंस का परिचालन लड़खड़ाने से बढ़ी यात्रियों की परेशानी ● फाइल

लोगों के हित प्रभावित हो सकते हों। ऐसे में, मंत्री यह बहाना नहीं बना सकते कि लोक सेवक उन्हें अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि यह भी मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वे उचित लोक सेवकों का चयन करें जो अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाएं। कुल मिलाकर, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के मामले में सरकार और संबंधित मंत्रियों की संसद के प्रति और उनके माध्यम से जनता के प्रति राजनीतिक जवाबदेही सीधी होती है। यह एक अलग मामला है कि कई दशकों से राजनीतिक वर्ग ने हमेशा प्रशासनिक विफलताओं की जिम्मेदारी लोक सेवकों और प्रबंधकों पर डालने की कोशिश की है। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में मंत्रियों ने नैतिक जिम्मेदारी ली और यहां तक कि इस्तीफा भी दिया। वह दौर बहुत पहले ही बीत चुका है। मंत्रियों से जुड़ी कंपनियों में भ्रष्टाचार का मामला एक अलग श्रेणी में आता है।

उदारीकरण के साथ अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। इसका ही परिणाम है कि इंडिगो जैसी भीमकाय कंपनियां उभरीं, जो अपने बाजार के एक बड़े हिस्से पर काबिज होकर उसे नियंत्रित करती हैं। ऐसी स्थिति केवल कुछ कानूनों में परिभाषित आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों तक भी है जो ऐसे कानूनों के अंतर्गत नहीं आते। जैसे कि सीमेंट और बिजली उत्पादन क्षेत्र। इन क्षेत्रों में निजी कंपनियों की विफलता से अर्थव्यवस्था पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बड़ी निजी कंपनियां स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि कंपनियां कानूनों और नियमों के अनुसार संचालित हों। यह स्पष्ट है कि इंडिगो का बोर्ड अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा। चूंकि इन कंपनियों के संचालन में सार्वजनिक हित जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसे तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करें कि अधिकारियों को समय पर सूचित किया जाए कि कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होगा कि कंपनी के प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप होगा। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सरकार और कंपनियां दोनों संतुलन के साथ कार्य करें। यह अच्छी बात है कि राजनीतिक वर्ग और उद्योग जगत में इस मोर्चे पर परिपक्वता दिखती है।

नियामकीय संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे इसकी निगरानी करें कि कोई कंपनी नियमों के पालन को लेकर सही दिशा में बढ़ रही है या नहीं। इंडिगो के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए की यही जिम्मेदारी थी। क्या डीजीसीए ने इस पर नजर रखी कि इंडिगो नए नियमों के अनुपालन को लेकर आवश्यक पायलटों की भर्ती के लिए प्रयास कर रही है? क्या उसने मंत्रालय के अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया, जिससे जानकारी और आगे बढ़ती। ये प्रश्न किसी को आलोचना के कठघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हैं ताकि इंडिगो प्रकरण से सबक सीखकर यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। जवाबदेही के राजनीतिक एवं प्रशासनिक मानदंड तो स्थापित करने ही होंगे।

तेजी से वृद्धि कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में विमानन क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि इंडिगो की मौजूदा समस्याएं उन पहलुओं के समाधान तलाशने की दिशा में उन्मुख करें कि कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा जनता और अर्थव्यवस्था को न भुगतना पड़े। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र विशेष में किसी कंपनी का इतना वर्चस्व न हो जाए कि उसकी समस्याएं पूरे देश को नुकसान पहुंचाएं।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

उद्योगपतियों के प्रति रवैया बदले विपक्ष

प्रो. अमिताभ श्रीवास्तव

ट्रंप टैरिफ वार को नाकाम करने में उद्यमियों का भी योगदान रहा है, जो दुर्भाग्य से विपक्ष के निशाने पर रहे हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय धान पर टैरिफ लगाने की परोक्ष धमकी देकर भारत को डराने की फिर कोशिश की है, पर तथ्य इस बात के गवाह हैं कि ट्रंप प्रशासन स्वयं डरा हुआ है। पचास प्रतिशत टैरिफ का ट्रंप कार्ड 'जोकर' साबित हो चुका है। इसका क्रेडिट काफी हद तक भारतीय उद्योगपतियों को जाता है, जो दुर्भाग्य से अपने ही देश में विपक्ष के हमलों का शिकार हो रहे हैं। मौजूदा विश्व अर्थव्यवस्था में हर देश अपने उद्योगपतियों को मूल्यवान समझता है। याद कीजिए लगभग तीन दशक पहले गेट यानी जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ एंड ट्रेड के जरिए भारत समेत विकासशील देशों पर दुनिया भर में टैरिफ कम करने का दबाव डाला गया था। आज अमेरिका खुद उसी टैरिफ की आड़ ले रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून का उल्लंघन हो रहा है। घरेलू मोर्चे पर एलन मस्क जैसे बड़े उद्योगपति ट्रंप से मुंह मोड़ चुके हैं। ट्रंप के दबाव के बावजूद हाल में माइक्रोसाफ्ट और गूगल ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है, पर लाख टके की बात यह है जब तक हम अपने उद्योगपतियों को ताकत नहीं देते, विकसित देशों के उद्योगपतियों से मुकाबला कठिन है।

हाल में रूसी प्रतिनिधिमंडल में तेल और ऊर्जा क्षेत्र के रोसनेफ्ट, स्बेयर बैंक, यूरिया उत्पादन से जुड़ी यूराल नेट, हथियार उत्पादन के लिए मशहूर रोजोबारोनेक्सपोर्ट जैसी कंपनियों के आला अधिकारी आए थे। वहीं भारत की ओर से टाटा, अंबानी, अदाणी किसी की भी रूसी प्रतिनिधिमंडल से सीधी बात नहीं हुई। ऐसा नहीं कि सीधी बात न होने से भविष्य में व्यापार की सारी संभावनाएं ही समाप्त हो गई हों, पर यह भी साफ है कि रूसी राष्ट्रपति की मौजूदगी में भारत की प्रमुख कंपनियों की उपस्थिति एक सकारात्मक असर डालती। यह अवसर हम चूक गए। शायद नीति निर्धारकों का सोच यह रहा हो कि कुछ अहम समूहों की उपस्थिति सियासी विवाद को जन्म देती और संसद सत्र के दौरान सरकार कोई मुद्दा विपक्ष को देने को तैयार नहीं थी।

जरा सोचिए कि अफगानिस्तान में आतंक के दौरान भारतीय कंपनियों ने किन परिस्थिति में कार्य किया होगा और भारत सरकार ने तब

अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते उद्योगपति ● फाइल

उन्हें संरक्षण देकर सही किया या गलत? और आज फार्मा से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में निजी कंपनियों को अफगानिस्तान में भेजा जाना क्या जरूरी नहीं है? अफगानिस्तान ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, अफ्रीका आदि देशों में अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों से सहयोग लिया और आवश्यक संरक्षण प्रदान किया। घरेलू मोर्चे पर भी संकट के समय वैक्सीन का अतिरिक्त उत्पादन हो या ऊर्जा संकट के दौर में वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर, सभी कुछ निजी कंपनियों के जरिए हासिल किया गया, पर कभी तीन सौ तो कभी तीन व्यावसायिक समूहों के नाम पर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। भले स्वशासित राज्यों में उद्योगपतियों को महत्व देने के लिए खुलेआम भ्रष्टाचार तक का सहारा लिया गया हो। विपक्ष के नेता को वैचारिक खाद-पानी दे रहे एक वामपंथी नेता के पुत्र रियल स्टेट और बिस्किट फैक्ट्री के क्षेत्र में बंगाल के बड़े उद्योगपति बने। उनके उत्थान का काल सबसे लंबे दौर तक बंगाल में चला पिता जी का कार्यकाल ही रहा। उनकी ईस्टर्न बिस्किट कंपनी पर भी 37.68 लाख रुपये बकाये का केस बना। अदालत ने अन्य अपेक्षाओं के साथ पंद्रह लाख रुपये की बैंक गारंटी का आदेश दिया, जो नहीं भरी गई। बाद में अंतरिम आदेश रद हो गया। फाइल वर्षों बाद 2005 में मिली।

आज वामपंथ के असर से मुक्ति पाकर बड़ी मुश्किल से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत ने तमाम कामयाबी हासिल की है। जापान पिछड़ चुका है और अब जर्मनी की बारी है, लेकिन सच यह भी है भारत की अर्थव्यवस्था जहां अब तक पांच ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर का आंकड़ा नहीं छू पाई है वहीं अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्थाएं तीस और बीस ट्रिलियन डालर से ऊपर की हो चुकी हैं। यानी अभी काफी कुछ किया जाना है, क्योंकि दुनिया आकाश से आई आवाज ही सुनती है। ताकतवर प्रतिद्वंद्वियों के साथ क्या करते हैं यह पहले चीन और फिर ट्रंप के बर्ताव से साफ है। दुनिया में आवाज शिखर की सुनी जाती है। बाकी आवाज या तो दब जाती है या उन आवाजों का दम घोंटने की कोशिश की जाती है।

ट्रंप का मौजूदा रूप आपको यकीनन अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यह भी है कि ट्रंप से पहले भी समय-समय पर अमेरिका ने इसी तरह से भारतीय हितों में बाधा डालने का प्रयास किया था। यह बात अलग है कि डरावने नाखूनों वाले शरीर पर तब नफासत की नकाब लगी थी। याद कीजिए वह दौर जब भारतीय कपड़ों की खेप को यह कह कर लौटाया गया था कि इसमें आग लग जाती है। फलों की खेप कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग कह कर लौटा दी जाती थी, पर जब अमेरिकी पेय पदार्थों में कीटनाशकों का मामला आया तो पूरा अमेरिका प्रशासन मोर्चा संभालने लगा। जिस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी मोटर साइकिल कंपनी के हित को अपने देश का हित बता रहे हों, उस दौर में भारत के व्यवसायियों के वाजिब हितों के लिए कौन लड़ेगा? समाज और राजनीति, दोनों को व्यापार जगत के अपने योद्धाओं यानी उद्योगपतियों के प्रति रवैया बदलना होगा। ध्यान यह भी रहे व्यवसायियों को भी समाज के प्रति अपने दायित्व का पालन करना होगा।

(लेखक राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान संकाय के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भीतर की यात्रा

आज मनुष्य असंतोष, अशांति, शोषण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, युद्ध और पर्यावरण असंतुलन के अंधकार से घिरा हुआ है। यह अंधेरा बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि मनुष्य की आंतरिक भूलों, विकृत सोच और मूल्यहीनता का परिणाम है। प्रदूषण केवल हवा और पानी में नहीं बढ़ा है, प्रदूषण हमारे विचारों में भी गहरा होता जा रहा है। जब मनुष्य अपने भीतर की रोशनी खो देता है, तब विश्व भी अंधकारमय हो जाता है। दरअसल इन समस्याओं की जड़ें बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। और समाधान भी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छुपा है-आध्यात्मिक चिंतन में, स्व-परिवर्तन में और अच्छे मनुष्य बनने की साधना में।

घृणा को घृणा से समाप्त नहीं किया जा सकता। कट्टरता का उत्तर कट्टरता नहीं है। विरोध का समाधान विरोध नहीं हो सकता। घृणा घृणा को और बढ़ाती है, हिंसा हिंसा को जन्म देती है, परंतु प्रेम, करुणा और शांति ही इनका अंत कर सकते हैं। यही वह युग-सत्य है जिसे बुद्ध ने करुणा में, महावीर ने अहिंसा में और गांधी ने सत्याग्रह में रूपायित किया। शांति कोई वस्तु नहीं, जिसे बाजार से खरीदा जा सके या किसी सत्ता द्वारा बांटा जा सके। शांति एक आंतरिक यात्रा है। यह मनुष्य के अंतःकरण में जन्म लेती है और वहीं से विश्व तक फैलती है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की अच्छाइयों को जगाने लगेगा-सद्भाव, स्वच्छ विचार, करुणा, संयम और सत्यनिष्ठा, उसी दिन दुनिया की अधिकांश समस्याओं का अंत शुरू हो जाएगा। आज आवश्यकता विश्व सुधार की नहीं, मनुष्य सुधार की है। क्योंकि संसार मनुष्यों से बनता है और मनुष्य अपने विचारों से। जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है, आत्मा की आवाज सुनता है और अपने अहं, लालच और द्वेष से ऊपर उठता है, तब उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है-अहिंसा, संतुलन और विश्वबंधुत्व की चेतना। यही चेतना हर संकट की मूल उपचारक है।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

लापरवाही की आग में झुलसता सिस्टम

संजय गुप्त ने अपने आलेख 'नियम-कानूनों की घातक अनदेखी' में प्रशासनिक विफलता को उजागर किया है। गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में पच्चीस लोगों की हृदयविदारक मौत केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि नियम-कानूनों की घातक अनदेखी का ज्वलंत प्रमाण है। जिस क्लब में यह हादसा हुआ, उसके पास फायर एनओसी तक नहीं होना प्रशासनिक तंत्र की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बिना अनिवार्य सुरक्षा मानकों के ऐसा प्रतिष्ठान आखिर कैसे संचालित होता रहा। हर बड़ी घटना के बाद कार्रवाई का दिखावटी दौर शुरू हो जाता है। जांच, निलंबन और मुआवजे की घोषणाएं होती हैं, लेकिन समस्या की जड़ पर प्रहार कभी नहीं होता। नतीजा यह है कि कुछ समय बाद वही लापरवाही फिर किसी नई त्रासदी का कारण बन जाती है। इस घटना के लिए केवल क्लब संचालक ही नहीं, बल्कि आंख मूंदकर अनुमति देने वाले और निरीक्षण में विफल रहे प्रशासनिक पदाधिकारी भी बराबर के दोषी हैं। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी जवाबदेही तय होगी। दरअसल इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति सरकार और प्रशासन की सामूहिक विफलता है। जब तक सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने और दोषियों को कठोर दंड देने की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई जाएगी, तब तक निर्दोष जानें यूं ही लापरवाही की आग में झुलसती रहेंगी। हादसों के बाद की रस्म अदायगी से आगे बढ़कर स्थायी और कठोर समाधान अपनाए जाएं।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

समानता का अधिकार

सरकारी अधिकारियों के लिए 60 साल में अनिवार्य सेवानिवृत्ति और न्यायाधीशों के लिए 62 और 65 वर्ष की लंबी सेवा अवधि के बीच का अंतर संवैधानिक समानता (अनुच्छेद 14) का मजाक है। यह तर्क कि अनुभव की महत्ता केवल न्यायपालिका तक सीमित है, तर्कसंगत वर्गीकरण के आधार को कमजोर करता है, क्योंकि शीर्ष प्रशासनिक पदों पर भी अनुभव उतना ही निर्णायक होता है। इस दोहरे मापदंड का सीधा प्रभाव यह है कि वरिष्ठों की लंबी पारी के कारण योग्य कनिष्ठों की पदोन्नति में अनावश्यक देरी होती है, जिससे पूरी व्यवस्था में अवसर की समानता बुरी तरह प्रभावित होती है। इस असमानता को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। 60 वर्ष के बाद, न्यायपालिका सहित सभी शीर्ष पदों पर सेवा विस्तार केवल प्रदर्शन समीक्षा के आधार पर होना चाहिए, न कि स्वतः।

चन्द्र शेखर काण्डपाल, दिल्ली

सुरक्षित हो आनलाइन दुनिया

बच्चे जिस उम्र में खेलकूद, अध्ययन और सृजनात्मक गतिविधियों में समय बिताने चाहिए, वही समय अब स्क्रीन की चकाचौंध निगल रही है। हम आज बच्चों की आनलाइन दुनिया को सुरक्षित नहीं बनाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी का भावनात्मक और बौद्धिक विकास गंभीर संकट में पड़ सकता है।

सुरेश गोयल, हरियाणा

इंटरनेट मीडिया पर रोक

आस्ट्रेलिया द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध विश्वभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां तक कि भारत में भी माता-पिता, अभिभावक इस विषय पर सोच विचार कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया में 16 वर्ष की उम्र के बच्चों पर जिस तरह से पाबंदी लगाई गई है। भारत में इसका अध्ययन किया जाए तो माता-पिता या अभिभावक, सरकारी, निजी, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला या घरेलू महिला हर कोई अपने बच्चों को प्रारंभ से ही इस तरह से मोबाइल, टीवी या अन्य कार्यक्रम दिखाकर व्यस्त रहती है और अपना घरेलू कार्य करती रहती है। बच्चों को पहले से ही ऐसे माहौल में ढाल दिया जाता है, अगर अध्ययन करें तो इस बात का पता चलता है कि भारत में जो बच्चे मोबाइल अधिक देखते हैं, उनके स्वास्थ्य, मस्तिष्क तथा व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीमित अवधि तक मोबाइल दें या फिर दे ही नहीं। वहीं वयस्कों पर भी इंटरनेट मीडिया के दुष्प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह न केवल उनके जीवन के बड़े हिस्से को खा रहा है बल्कि सोशल मीडिया के नाम पर लोगों की सोशल लाइफ को समाप्त कर रहा है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि इंटरनेट मीडिया का वास्तव में हमें कितना लाभ हो रहा है। राष्ट्र सुरक्षा और अन्य हितों को लेकर भी सख्त नियम बनने जारूरी हैं।

मीना धानिया, सिरसपुर दिल्ली

पोस्ट

सिडनी के बोंडी बीच पर पहलगाम दोहरा दिया गया। बहाना गाजा का। नाइजीरिया में ईसाइयों पर जुल्म हो रहे हैं। ईराक में यजीदी ईसाइयों पर हुए, कश्मीर में हिंदुओं पर और बांग्लादेश में हो ही रहे हैं। दुनिया में कौन समुदाय है, जिस पर जुल्म नहीं हुए? दूसरे समुदाय तो जिहादी मारकाट करते नहीं फिरते।

शिव कांत@shivkant

मेसी को स्टेडियम में देखने का टिकट 4,500-20,000 रुपये तक है। सेल्फी के लिए 10-10 लाख रुपये का टिकट। इसका मतलब यही है कि या तो लोगों के पास बहुत पैसा हो गया है या फिर सुपरस्टार के लिए जुनून सिर चढ़ कर बोल रहा है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

कांग्रेस की रैली में पार्टी अध्यक्ष खरगे ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में वोट-चोरी हुई थी। जब मोदी पूर्ण बहुमत हासिल करने में नाकाम रहे, तब भी वे ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसके बजाय उनकी पार्टी ने तो नतीजों का ऐसा जश्न मनाया था कि मानो सत्ता में वापसी हो गई हो।

तवलीन सिंह@tavleen_singh

जनपथ

जाय पढ़ाई संस्कृत गूंजेंगे श्लोक,
शायद पाकिस्तान में बदल रहे कुछ लोग।
बदल रहे कुछ लोग पढ़ेंगे यदि कुछ अच्छा,
तो शायद आतंक छोड़ने की हो इच्छा!
बहुत दिनों के बाद खबर यह अच्छी आई,
बदले दानव लोक संस्कृत जाय पढ़ाई!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 150

****

दो दिसंबर की सुबह हजारों यात्री एयरपोर्ट पर थे। उनको अपनी मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन पता नहीं था कि वह कब पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी फ्लाइट रद हो गई थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लोगों को 10-10 घटें तक फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा। लाखों यात्रियों को बेबस होकर मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ा। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। पूरे देश में अफरातफरी का माहौल बन गया था। इसकी वजह यह थी कि देश में प्रत्येक 10 हवाई यात्रियों में से छह इंडिगो की फ्लाइट में यात्रा करते हैं और इंडिगो एयरलाइंस का कामकाज बाधित हो गया था। किसी सेक्टर में एक कंपनी या संस्था का एकाधिकार किस तरह के नतीजे दे सकता है, इंडिगो संकट इसकी एक बानगी है। देश के उड्डयन बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी करीब 65 प्रतिशत है, वहीं दूसरी बड़ी कंपनी एअर इंडिया की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत। यह एकाधिकार रातोंरात नहीं हुआ। सवाल है कि नियामक संस्थाओं ने समय पर इस खतरे को पहचान कर इसे दूर करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? देश के उड्ड्यन बाजार में एकाधिकार की स्थिति कैसे बनी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी पड़ताल अहम मुद्दा है...

एकाधिकार का दंश

क्या है एकाधिकार

एकाधिकार एक ऐसी बाज़ार स्थिति है, जहां किसी एक कंपनी का किसी वस्तु या सेवा पर पूरा नियंत्रण होता है, कोई करीबी विकल्प नहीं होता, जिससे कंपनी अपनी मर्जी से कीमतें तय कर सकती है। इसके नुकसानों में उपभोक्ताओं के लिए ऊंची कीमतें, घटिया गुणवत्ता, और नवाचार की कमी शामिल हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती, जिससे उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचता है और बाजार में अनुचित व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।

दो कंपनियों का प्रभुत्व

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का व्यस्त उड़ान शेड्यूल नवंबर में उस समय बिगड़ गया, जब पायलट और क्रू मेंबर्स को ज्यादा आराम देने वाला नया नियम लागू हुआ। दिसंबर के पहले हफ्ते में एयरलाइन पूरी तरह बिखर गई। एक दिन में ही 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद कर दी गईं। इससे 10 लाख से ज्यादा बुकिंग प्रभावित हुईं। लोग परेशान हुए और हालात बिगड़े तो सरकार ने एयरलाइन की कार्यप्रणाली की जांच का आदेश दिया। बड़ा सवाल यह है कि महज एक कंपनी की गड़बड़ी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर कैसे ठप हो सकता है? इसका जवाब बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी होने में छिपा है। दरअसल 2007 में शुरू हुई इंडिगो की जबरदस्त कामयाबी ने उसे घरेलू उड्यन बाजार का 64 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा दे दिया। वहीं एअर इंडिया के पास 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इंडिगो संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था में एकाधिकार के खतरों को सामने ला दिया है। यहां एयरलाइंस से लेकर टेलीकाम और यूपीआइ से लेकर ई- कामर्स तक में ज्यादातर बाजार हिस्सेदारी कुछ ही कंपनियों के पास है। हालांकि विशेषज्ञों और और नियामकों का कहना है कि किसी सेक्टर में एक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी ज्यादा होना ही अपने आप में समस्या नहीं है। हालांकि अगर प्रभुत्व वाली कंपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को बाजार से बाहर करवा देती है या उपभोक्ताओं का शोषण करती है तो इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यहां पर सरकार को दखल देना चाहिए।

एयरपोर्ट और ईंधन रिफाइनिंग पर दो कंपनियों का है कब्जा

इंडिगो का बुरा हफ्ता भारत की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या को उजागर करता है। यहां सबसे बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को बाहर कर रही हैं। हवाई क्षेत्र में इतनी कम प्रतिस्पर्धा और कुछ ही कंपनियों के हाथ में इतना ज्यादा नियंत्रण अब भारत में आम हो गया है। भारत के सबसे फायदेमंद एयरपोर्ट दो कंपनियां चलाती हैं और देश के 40 प्रतिशत ईंधन की रिफाइनिंग भी दो कंपनियां करती हैं। इनके अलावा दूरसंचार, ई-कामर्स, बंदरगाह और स्टील जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी कुछ ही बड़ी कंपनियां हावी हैं।

बाजार में दो कंपनियों का दबदबा

(हिस्सेदारी प्रतिशत में)

सेक्टर	पैरामीटर	कंपनियां		शीर्ष दो कंपनियों की हिस्सेदारी	शीर्ष तीन कंपनियों की हिस्सेदारी	शीर्ष पांच कंपनियों की हिस्सेदारी
डिपाजिटरी	सक्रिय ग्राहक खाते	सीडीएसएल	एनएसडीएल	100	-	-
एयरलाइंस (घरेलू)	यात्री, दूरी	इंडिगो	एयरइंडिया	91	96	100
यूपीआइ	लेनदेन का मूल्य	फोन पे	गूगल पे	84	90	94
टेलीकाम	मोबाइल ग्राहक	जियो	एयरटेल	75	92	100
एयरपोर्ट	यात्रियों की संख्या	अदाड़ी	जीएमआर	64	87	100
डीटीएच	ग्राहकों की संख्या	टाटा प्ले	एयरटेल	60	81	100

टेलीकाम मार्केट में भी तीन कंपनियों का ही वर्चस्व

आठ महीने पहले भारत की दो बड़ी दूरसंचार कंपनियों जियो और एयरटेल के पीछे तीसरी कंपनी वोडाफोन आइडिया थी, जो सरकार को दिए जाने वाले टैक्स के बोझ से दबी थी। मार्च में सरकार ने उस कर्ज का बड़ा हिस्सा अपनी हिस्सेदारी में बदल दिया और अब सरकार का कंपनी में 49 प्रतिशत हिस्सा है। आज की स्थिति देखकर साफ है कि भारत में कम से कम तीन नेशनल टेलीकाम कंपनियां बनी रहेंगी। हालांकि वोडाफोन आइडिया अभी भी बकाया शुल्क नहीं चुका पाई है।

प्रतिस्पर्धा आयोग के पास सीमित शक्तियां

भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस साल पहली बार पाया कि 8 बड़े सेक्टर्स में बड़ी कंपनियों का एकाधिकार है। लेकिन आयोग के पास सिर्फ संभावित विलय की जांच करने और उसे मंजूर या खारिज करने की ताकत है। कंपनियों के आकार में बढ़ोतरी रोकने या उड्डयन जैसे उद्योगों में एकाधिकार कम करने की ताकत उसके पास नहीं है। भारत में कभी प्रतिस्पर्धी बाजार का माडल नहीं रहा, इसीलिए इसके खिलाफ एक्शन को लेकर भी बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है।

नई कंपनियों को नहीं मिलता आसानी से कर्ज

नई कंपनियों के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्रेडिट यानी कर्ज न मिलना है। 2015 के आसपास एनपीए संकट सामने आने के बाद बैंक सिर्फ सबसे ताकतवर कंपनियों को ही कर्ज दे रहे हैं। बड़ा होना आपको सफल होने की ज्यादा संभावना देता है जैसा कई देशों में होता है। लेकिन भारत में बड़ी कंपनियों की कर्ज लेने की ताकत निर्णायक है। जागरण रिसर्च

प्रभुत्व का फायदा न उठाने दे सीसीआइ

केके शर्मा
पूर्व महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआइ को एक मार्केट वाच डिवीजन बनाना चाहिए, जो बाजार पर नजर रखे और ऐसे हालात ही पैदा न होने दे, जहां कोई कंपनी अपनी मजबूत बाजार स्थिति का दुरुपयोग कर सके। इसी तरह से भविष्य में इंडिगो संकट जैसे हालात को रोका जा सकता है।

पूरी दुनिया में देखा गया है कि जिन सेक्टरों में ज्यादा निवेश की जरूरत होती हैं, वहां दो तीन बड़ी कंपनियां ही होती हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में भी ऐसा हो रहा है। जैसे उड्डयन या टेलीकाम को ले लें। यहां किसी नए प्लेयर के लिए आना और खुद का बाजार में स्थापित करना आसान नहीं है क्योंकि यहां कारोबार शुरू करने के लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत है। अगर किसी सेक्टर में दो कंपनियां हैं और उनकी बाजार हिस्सेदारी 55:45 के अनुपात में है, तो यह बेहतर स्थिति है। इससे दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है और इससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होता है। वहीं अगर किसी सेक्टर में एक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है और दूसरी की 30 प्रतिशत तो यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। हाल में इंडिगो संकट में इस खतरनाक स्थिति को देखा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में भारत के उड्यन क्षेत्र में इंडिगो की हिस्सेदारी करीब 65 प्रतिशत है और एअर इंडिया की हिस्सेदारी काफी कम है। इस संकट के दौरान इंडिगो के व्यवहार को निश्चित रूप से बाजार में अपनी स्थिति के दुरुपयोग के बजाए बाजार की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से कंपनी का रवैया एकाधिवार वाला रहा है।

कंपनी के व्यवहार से साफ संकेत मिलता है कि उसे लग रहा था कि कोई उसका क्या कर सकता है क्योंकि उड्डयन सेक्टर में दो कंपनियों का ही प्रभुत्व है। 2009 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) के महानिदेशक के तौर पर मेरे कार्यकाल के दौरान उड्डयन क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों ने एटीएफ की कीमतों को लेकर सरकार को धमकी दी थी कि 15 दिन के बाद कोई भी जहाज नहीं उड़ेगा। उस दौरान सीसीआइ ने इस संबंध में खतरे को लेकर सरकार को अलर्ट किया था और इस की जांच के लिए एक नोट भी बनाया था। हालांकि, कुछ वजहों से यह मामला आगे नहीं बढ़ सका।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 बाजार में प्रभुत्व वाली स्थिति के लिए सिर्फ बाजार हिस्सेदारी के आधार पर कोई साफ संकेत नहीं देता है। इस अधिनियम के तहत प्रभुत्व वाली स्थिति ज्यादा बारीक है और अधिनियम के सेक्शन 19(4) में यह सिर्फ बाजार हिस्सेदारी पर नहीं, बल्कि 13 फैक्टर्स से तय होती है। हालांकि, इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 65 प्रतिशत के करीब होने और दूसरे प्लेयर एअर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी सिर्फ 25 प्रतिशत होना उड्डयन बाजार के लिए बुरी खबर है। एयर इंडिया का ज्यादातर विस्तार इंटरनेशनल रूट पर होने के कारण, घरेलू उड्डयन बाजार पूरी तरह से इंडिगो की ओर झुका हुआ है। आम तौर पर डुओपोली यानी दो कंपनियों के प्रभुत्व वाली में स्थिति में दोनों कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में 10-15 प्रतिशत से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। 40-55 प्रतिशत की डुओपोली में कंपनियां के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और कंपनियां एक दूसरे को नियंत्रित करती हैं। दूसरी ओर, अगर एक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है और दूसरे की बाजार हिस्सेदारी 15 प्रतिशत तो यह सिर्फ नाम की डुओपोली है, और इसमें एकाधिकार के लक्षण दिखने की संभावना है। यह आज के भारतीय उड्डयन बाजार की स्थिति के बहुत करीब है। हालांकि, किसी भी जांच में ऐसा घोषित नहीं किया गया है लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, इंडिगो न केवल प्रभुत्व वाली स्थिति में है, बाजार में असल में एक एकाधिकार वाली कंपनी है। इंडिगो संकट का सीधा कारण डीजीसीए द्वारा सख्ती बरतना है क्योंकि इंडिगो दो साल से जरूरी सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रही थी। इससे भी ज्यादा जरूरी यह देखना है कि स्थिति यहां तक कैसे पहुंची। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इंडिगो एकाधिकार वाली वाली कंपनी थी और उसे यह गलतफहमी थी कि वह 'इतनी बड़ी है कि उसे फेल नहीं होने दिया जा सकता'। अगर ऐसा नहीं होता तो वह मुनाफे के लिए सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करती और जरूरी संख्या में पायलटों की भर्ती करती। यह बात सेक्टर रेग्युलेटर डीजीसीए के अस्थायी रूप से पीछे हटने से भी कुछ हद तक सच साबित होती है। आम तौर पर नए पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग में छह महीने तक लग सकते हैं।

डीजीसीए द्वारा तय सुरक्षा नियमों का पालन न करना एक एकाधिकार वाली कंपनी के घमंड को दिखाता है, जिसे लगता है कि उस पर अनुशासन लागू करने से उड्डयन बाजार में बड़ी दिक्कतें आएंगी। इसलिए, यह दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग नहीं है, बल्कि यह ऐसे बाजार में जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रभुत्व वाली कंपनी के लगातार दबदबे वाली स्थिति का नतीजा है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) को मार्केट वाच डिवीजन बनाना चाहिए, जो ऐसी कंपनियों पर नजर रखे जो बाजार में अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर सकती हैं और ऐसे हालात पैदा होने से रोकने के लिए समय से कदम उठाए।

कंपनी की बाजार हिस्सेदारी ज्यादा होना खतरा नहीं

एमएस मणि
पार्टनर, डेलाइट

किसी सेक्टर में एक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी अधिक होना ही अपने आप में खराब बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि कंपनी अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग ही करेगी। यहां पर नियामकीय तंत्र को सतर्क रहना चाहिए कि कंपनी बाजार में प्रभुत्व का दुरुपयोग न कर पाए।

आम तौर पर किसी भी सेक्टर में चार पांच प्लेयर होने चाहिए। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा रहती है और इसका फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलता है लेकिन भारत में मौजूदा परिदृश्य की बात करें तो यहां हालात अलग नजर आते हैं। इसकी वजह यह है कि जिन सेक्टर में बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत है, वहां नए प्लेयर के लिए घुसना बहुत कठिन है।

जैसे अगर आप टेलीकाम सेक्टर को ले लें। इस सेक्टर में किसी प्लेयर को अगर काम शुरू करना है तो उसे लगभग 30,000 करोड़ रुपये चाहिए। पहले से टेलीकाम सेक्टर में जो प्लेयर हैं वह मुश्किल से पांच प्रतिशत मुनाफे पर काम कर रहे हैं। अब अगर किसी के पास 30,000 करोड़ रुपये हैं तो यह ऐसे सेक्टर में क्यों जोखिम लेगा जहां शुरुआती निवेश बहुत अधिक है और मुनाफा बहुत कम। सिर्फ निवेश की बात नहीं है एक नए प्लेयर के लिए बाजार में घुसना और खुद को स्थापित करना एक और चुनौती है। इसके बजाए वह 30,000 करोड़ कर्ज देकर आठ प्रतिशत ब्याज हासिल कर सकता है। किसी भी सेक्टर में चार पांच प्लेयर का होना अच्छी बात है लेकिन यह कई बार यह व्यावहारिक नहीं होता है। इसी तरह से एविएशन सेक्टर में अगर कोई नया प्लेयर आना चाहता है तो वह चार पांच विमान से काम शुरू नहीं कर सकता है। इसके लिए डीजीसीए ने जो न्यूनतम जरूरत तय की है, उसके तहत किसी नई कंपनी के पास सेक्टर में काम शुरू करने के लिए 12 विमान होने चाहिए। इसके अलावा दूसरे जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करना होगा। इसके लिए कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। इसके बाद बात आती है कि वह विमान कहां से लेगा। इस समय दुनिया में सिर्फ दो ही कंपनियां विमान बनाती हैं।

एक है अमेरिका की बोइंग और दूसरी फ्रांस की एयरबस। इन दोनों कंपनियों के पास पहले से अगले पांच वर्ष के लिए आर्डर बुक हैं। अगर कोई नई कंपनी इन कंपनियों को पूरा भुगतान करती है तो उसे विमान तीन वर्ष बाद मिलने शुरू होंगे। इसका मतलब है कि भारत के एविएशन सेक्टर में किसी नए प्लेयर को काम शुरू करना है तो उसे कम से कम तीन वर्ष इंतजार करना होगा। इसके बाद दूसरी चुनौतियां हैं कि उसे कितने रीजन और कितने रूट मिलेंगे। यहां चुनौती बाजार मांग की भी है। भारत में जहां पर वंदेभारत ट्रेन शुरू हुई हैं, उन रूट पर हवाई जहाज से यात्रा करने वाले ट्रेन पर शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रेन से यात्रा करना प्लेन की तुलना में सस्ता और आरामदायक है।

वहां आपको फ्लाइट टाइम से दो घंटे पहले नहीं पहुंचना है। ऐसी बहुत सी व्यावहारिक दिक्कते हैं। दुनिया के दूसरे देशों को देखें तो यूरोप में चार और अमेरिका में पांच एयरलाइन हैं। यूरोप और अमेरिका में हवाई यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह बहुत अधिक नहीं है। अगर इंडिगो संकट की बात करें तो यह साफ दिखता है कि कंपनी ने बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग किया है। इसके लिए नियामकीय तंत्र जिम्मेदार है। किसी कंपनी का बाजार में प्रभुत्व होना खराब बात नहीं है खराब बात उसका अपनी मजबूत स्थिति का बेजा इस्तेमाल करना है। इस पर नियामकीय तंत्र को ध्यान देना चाहिए।

आपकी आवाज

नियामक तंत्र के फेल होने के कारण ही इंडिगो एयरलाइंस में लापरवाही हुई, ऐसी लापरवाही तो बहुत से लोगों की जान पर भी भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो। प्राइवेट संस्थानों से उम्मीद होती है कि यह हमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए हम ज्यादा पैसा भी खर्च कर देते हैं, लेकिन हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस की लापरवाही ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इंडिगो के कारण यात्रियों को जो परेशानी हुई उसकी उचित और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजेश चौहान

उड्डयन क्षेत्र में इंडिगो के एकाधिकार और लापरवाही का नतीजा यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। कोई भी कंपनी अपने बेहतर सेवा, सुविधा और गुणवत्ता के बदौलत उस क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करती है परंतु एकाधिकार के बाद गुणवत्ता में गिरावट और मनमानी के कारण इस तरह की समस्याएं पैदा होती है। इंडिगो यात्रियों को सेवा और सुविधा दोनों देने में विफल रह है। यह समस्या अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक सबक बन सकती है जहां पर एक ही कंपनी का उस क्षेत्र में एकाधिकार हो। इससे सरकार को सीख जरूर लेनी चाहिए। देवानंद राय

संगठित समाज ही राष्ट्र को परम वैभव पर ले जा सकता : होसबाले

- गोष्ठी में सरकार्यवाह ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को बताया एक
- कहा- उपासना पद्धति अलग हो सकती, लेकिन मूल एक ही है

जन गोष्ठी के दौरान दत्तात्रेय होसबाले • फोटो: इंटरनेट मीडिया

जागरण संवाददाता, जोधपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने रविवार को कहा कि चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है और संगठित समाज ही राष्ट्र को परम वैभव पर ले जा सकता है। उन्होंने संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के तहत आयोजित जन गोष्ठी में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें एक हैं। उपासना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज और मूल एक ही है। यहां राष्ट्र की रक्षा ही धर्म की रक्षा है, क्योंकि धर्म केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है।

गोष्ठी में सरकार्यवाह ने कहा कि संघ इस प्राचीन राष्ट्र को आधुनिक काल में परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने संघ संस्थापक डा. केशव बलिराम हेडगेवार के विचारों को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि केवल व्यक्ति का अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्रबोध और समाज बोध होना भी आवश्यक है। व्यक्तिगत चरित्र से राष्ट्रीय चरित्र को लक्ष्य बनाकर ही संघ और शाखा की संकल्पना की गई है। गोष्ठी के दौरान जिज्ञासा समाधान सत्र का भी आयोजन किया गया। होसबाले ने समाज के समक्ष पंच परिवर्तन के विषयों सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य को रखते हुए इन्हें जीवन में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीवंत समाज में समस्याएं होती हैं, जिनके समाधान के लिए केवल सरकार पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक संगठित समाज का सहयोग आवश्यक है।

'मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, यह भाजपा में ही संभव'

जयशंकर बिहारी • जागरण

पटना: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, यह सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलने की जानकारी मिली तो सहसा विश्वास नहीं हुआ। यह भाजपा में ही संभव है, यहीं साधारण कार्यकर्ता को भी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है। पत्र जारी होने के डेढ़-दो घंटा पहले ही अपने बांकीपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में था, किसी को आभास नहीं था कि समारोह के बीच का ही कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहा है। उक्त बातें पथ निर्माण व नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अधिसूचना जारी होने के बाद दैनिक जागरण से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बताता है कि कार्यकर्ता जमीन पर काम करेंगे तो पार्टी उन्हें बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। अपनी प्राथमिकता के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें संगठन और कार्यकर्ता मजबूती व गति देने का काम करेंगे।

साक्षात्कार

नितिन नवीन • जागरण आर्काइव

बूथ से राष्ट्रीय स्तर तक संगठन को करेंगे मजबूत : नितिन नवीन ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व व पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो विश्वास जताया है, उसपर शत प्रतिशत खरा उतरने का पूरा प्रयास होगा। बूथ से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत कर आगामी चुनावों में जीत सुनिश्चित की जाएगी। शीर्ष नेतृत्व का पूर्व की तरह मार्गदर्शन लेते हुए कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी को हर राज्य में मजबूत किया जाएगा। बंगाल चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर कहा कि भाजपा हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती है। जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समावेशी और बिना भेदभाव के विकास सुनिश्चित करना है। यह पार्टी की मुख्य कार्यशैली बन गई है। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन पहले से मिलता आ रहा है। इनके मार्गदर्शन में आगे भी सांगठनिक व चुनावी रणनीति बनाकर कार्यकर्ताओं और आमजन की अपेक्षा को पूरा किया जाएगा।

भाजपा की कमान संभालने वाले पहले बिहारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: बिहार के नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे भाजपा की कमान संभालने वाले पहले बिहारी हैं। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी यह नियुक्ति चर्चा में है। वह कायस्थ समाज से हैं। बिहार में इस समाज की आबादी भले ही एक प्रतिशत से कम हो, लेकिन यह भाजपा का पारंपरिक और भरोसेमंद मतदाता वर्ग रहा है। यशवंत सिन्हा के बाद इस समाज के किसी नेता को इतने ऊंचे संगठनात्मक पद पर जिम्मेदारी मिलना भी राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

नितिन नवीन सोमवार को पटना से 10 बजे दिल्ली के आइजीआइ हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर पहुंचेंगे। उनका स्वागत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सभी मंत्री करेंगे।

नवीन की परिणाम देने वाले नेता की है छवि

- नितिन नवीन भाजपा की कमान संभालने वाले पहले बिहारी होंगे। 23 मई, 1980 को रांची (वर्तमान झारखंड) में जन्मे नितिन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार भाजपा के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे।
- पिता के निधन के बाद नितिन ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से राजनीति की कमान संभाली और वर्ष 2006 से लगातार पांच बार वहां से जीत दर्ज की।
- बिहार में पथ निर्माण मंत्री के रूप में उन्होंने सक्रिय, कामकाजी और परिणाम देने वाले मंत्री की छवि बनाई है। इससे पहले वह शहरी विकास एवं आवास विभाग और विधि विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
- 2008 में उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति सदस्य और युवा शाखा के सह-प्रभारी के रूप में कार्य किया।
- 2010-2013 तक वह युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 2016-19 तक उन्होंने बिहार में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला।
- 2019 में सिक्किम में भाजपा के चुनाव प्रभारी रहे। उसी साल जून में उन्हें सिक्किम राज्य भाजपा का संगठन प्रभारी बनाया गया।
- छत्तीसगढ़ में पिछले विस चुनाव से पहले उनको राज्य का प्रभारी बनाया गया। वहां बूथ स्तर का प्रबंधन, संगठन विस्तार व चुनावी तालमेल पर उनके फोकस का नतीजा निर्णायक जीत के रूप में सामने आया।

हिन्दुस्तान 1936 सत्य • सार्थक • सदैव

टीका और ऑटिज्म

टीकाकरण से बच्चों में ऑटिज्म होने संबंधी वर्षों पुराना विवाद अब थम सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि इस बाबत कोई वैज्ञानिक सुबूत नहीं है। इसके लिए वैक्सीन सुरक्षा पर डब्ल्यूएचओ की वैश्विक विशेषज्ञ समिति ने जनवरी, 2010 से लेकर अगस्त, 2025 तक प्रकाशित 31 शोध अध्ययनों सहित तमाम वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि गर्भावस्था व बचपन के दौरान लगने वाले टीके किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं हैं। दरअसल, यह पूरा विवाद साल 1998 में तब शुरू हुआ था, जब *लैंसेट* पत्रिका में छपे एक शोध अध्ययन में दावा किया गया कि एमएमआर टीका से ऑटिज्म होता है। उस अध्ययन में 12 मामलों का जिक्र किया गया था, हालांकि उसमें वैज्ञानिक पहलुओं का अभाव था, जिसके कारण बाद में पत्रिका ने अपना लेख वापस ले लिया। मगर तब तक तीर कमान से निकल चुका था। तमाम दावों-प्रतिदावों के बावजूद आम जनमानस में टीके और ऑटिज्म के रिश्ते पर बहस चलती रही। अब एक लंबे वैज्ञानिक अध्ययन के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिससे इस विवाद पर विराम लगने की उम्मीद है।

ऑटिज्म असल में एक मानसिक बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। इस वजह से मरीज बाहरी संसार से अलग अपनी दुनिया में खोया रहता है। ऑटिज्म से पीड़ित लोग, फिर चाहे वे बच्चे हों या बड़े, खुद को समाज से कटा हुआ मानते हैं, क्योंकि उनके सोचने-समझने या बातचीत का सलीका आम इंसानों से अलग होता है। हालांकि, कुछ लोग ऐसे मरीजों को मंदबुद्धि मानते हैं, लेकिन डॉक्टरों की नजर में यह महज मिथक है। उनके मुताबिक, ऐसे मरीजों को समाज में घुलने-मिलने में बेशक झिझक हो, लेकिन वे दिमागी रूप से कमजोर नहीं होते। तकनीकी शब्दावली में ऑटिज्म एक 'न्यूरो-डेवलपमेंटल डिसऑर्डर' है, जो आमतौर पर आनुवंशिक होता है, लेकिन प्रदूषण जैसे बाहरी कारक भी इसकी वजह बन सकते हैं। एम्स ने अपने एक अध्ययन में भारी धातुओं और मोबाइल पर अधिक वक्त बिताने (स्क्रीन टाइम ज्यादा होने) को भी इसका अहम कारण माना है। सलाह यही दी जाती है कि अगर बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, बोलने में झिझकता है या नजरें मिलाने से बचता है, तो उसे ऑटिज्म हो सकता है। घबराना, तेज आवाज से बेचैन होना, चिड़चिड़ापन या बेवजह का गुस्सा भी ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी सूरत में बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना ही श्रेयस्कर है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का खंडन जरूरी था, क्योंकि अनुमान यही है कि बीते पांच दशकों में नियमित टीकाकरण ने 15.4 करोड़ बच्चों की जान बचाई है।

यह सही है कि हर साल 2 अप्रैल को दुनिया भर में ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, लेकिन विडंबना है कि समाज में आज भी कई मिथक मौजूद हैं। पिछले दिनों तो अमेरिका में यह बहस शुरू हो गई थी कि गर्भावस्था के दौरान पेरासिटामोल का सेवन बच्चों में ऑटिज्म पैदा कर सकता है। यह तो भला हो विश्व स्वास्थ्य संगठन का कि उसने समय रहते इसका खंडन किया। आज दुनिया के हर 127 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे में, इससे जुड़ी तमाम गलतफहमियों को दूर करना निहायत जरूरी है। तब तो और, जब दुनिया के कई खित्तों में टीकाकरण के खिलाफ बेवजह की बहस चल रही हो। वास्तव में, विश्व स्वास्थ्य संगठन का टीके को लेकर नया खंडन इसी की कड़ी है, क्योंकि अनुमान यही है कि बीते पांच दशकों में नियमित टीकाकरण ने 15.4 करोड़ बच्चों की जान बचाई है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 15 दिसम्बर, 1950

खाद्य स्थिति का सामना

बम्बई में हो रहे खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में देहाती क्षेत्रों में अनाज की राशनिंग जारी रखी जाये अथवा नहीं, इस बारे में तीव्र मतभेद पैदा हो गया था। देश के जिन क्षेत्रों में अनाज की कमी है, उनकी आवश्यकताओं की पूति का भार केन्द्रीय सरकार पर है। इस वर्ष के दैवी प्रकोप के कारण केन्द्रीय सरकार का यह बोझ बहुत बढ़ गया है। चार राज्यों को छोड़कर इस समय देश में सर्वत्र अनाज की कमी महसूस की जा रही है। केन्द्रीय सरकार विदेशों से अनाज का आयात करके कमी वाले प्रदेशों को पूर्ति करती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति इस समय काफी विस्फोटक बन चली है और यदि तीसरा महायुद्ध हो, तो विदेशों से आयात करना काफी मुश्किल हो जायेगा। अनाज कहीं मिल भी गया तो उसे ढोने के लिए जहाज आसानी से सुलभ नहीं हो सकेंगे। अतः केन्द्रीय सरकार की स्वभावतः यह इच्छा है कि राज्यों को अन्न की पूर्ति करने का उसका दायित्व आने वाले समय में जितना घट जाये, उतना ही अच्छा होगा। इस दृष्टि से उसने राज्यों के सामने यह सुझाव रखा था कि वे देहाती क्षेत्रों में अनाज राशनिंग की जिम्मेदारी से अपने को मुक्त कर लें। कमी वाले राज्यों, खासकर बम्बई और मद्रास ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया।

अन्त में गोलमोल शब्दों में सम्मेलन ने यह तय किया है कि हरेक राज्य केन्द्र से परामर्श कर के ऐसा प्रबन्ध करे कि जिससे वह अगले वर्ष स्थिति का सामना कर सके। इससे यह स्पष्ट नहीं है कि देहाती क्षेत्रों में राशनिंग जारी रहेगी अथवा समाप्त कर दी जायेगी। अभी स्थिति यथापूर्व कायम रहने दी गई है। किन्तु केन्द्र को यह अधिकार तो रहेगा ही कि परिस्थिति बदल जाने पर वह राज्यों को आवश्यकतानुसार मौजूदा व्यवस्था में हेर-फेर करने का परामर्श अथवा आदेश दे सके। देश की खाद्य स्थिति इस में कोई शक नहीं है कि गंभीर है और उसका सफलतापूर्वक सामना करने के लिये केन्द्र और राज्यों के बीच पूरा सहयोग होना आवश्यक है। सरकार ने देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य अपने सामने रखा है और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिये वह एक निश्चित अवधि भी नियत कर चुकी है। उसका यह निश्चय है कि वह मार्च 1952 के बाद विदेश से अनाज का आयात नहीं करेगी। इस लक्ष्य के संबंध में लोगों में कुछ गलतफहमी पायी जाती है।

नई अमेरिकी सुरक्षा नीति में भारत कहां

जोरावर दौलत सिंह | इतिहासकार और रणनीतिकार

यहां स्कैन करें

अपने स्वार्थ में डूबे अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति में भारत अब भी अहम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस रणनीति में पाकिस्तान की स्थिति और मजबूत हुई है।

उन्नीसवीं सदी के जर्मन राजनेता ओटो वॉन बिस्मार्क ने एक बार कहा था, 'मूर्खों, शराबियों और अमेरिका पर ईश्वर की विशेष कृपा बरसती है।' इससे पता चलता है कि किस्मत ने अमेरिका को क्या दिया है। बड़े सागरों और प्रचुर संसाधनों से भरे महाद्वीप से घिरे होने के कारण अमेरिका थोड़े से भू-राजनीतिक प्रयासों से भी शांति और समृद्धि हासिल कर सकता था। उसके लिए दुनिया के हरेक कोने में अपनी ताकत दिखाना हमेशा से वैकल्पिक रहा है, अनिवार्य नहीं, पर उसकी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) में पश्चिमी गोलार्ध पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की वकालत की गई है और कहा गया है कि ''हम मुनरो सिद्धांत के लिए 'ट्रंप कोरोलरी' को लागू करेंगे''।

ऐसी सुरक्षा रणनीति क्यों बनाई गई है, इसके कारण स्पष्ट हैं। पहला, विश्व में अमेरिका की आगामी भूमिका को लेकर पश्चिमी जगत में भयंकर टकराव चल रहा है, शायद एक तरह का गृहयुद्ध भी। ये मतभेद मामूली नहीं हैं, बल्कि पश्चिमी समाज की राजनीतिक व्यवस्था और राष्ट्रीय पहचान के साथ-साथ विश्व स्तर पर उनकी रणनीतिक भागीदारी से जुड़े हैं। सत्ता-प्रतिष्ठानों के उस दबाव को ट्रंप प्रशासन ने खुले तौर पर चुनौती दी है, जिसके तहत वर्चस्व की विफल रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरह, वैश्विक परिदृश्य भी समान रूप से अहम हैं, क्योंकि इनसे शक्ति संतुलन में ऐसे बदलाव आए हैं, जिनकी कल्पना दो दशक पहले तक नहीं की जा सकती थी। गैर-पश्चिमी देशों और उनके प्रमुख शक्ति-केंद्रों का भरोसा अमेरिकी नेतृत्व से डिगा है। इससे नए सुरक्षा विमर्श पैदा हो रहे हैं। यह असामान्य परिस्थिति ट्रंप और उनके साथियों को पश्चिम की 'व्यापक रणनीति' (अपनी दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए सभी साधनों के इस्तेमाल) में अहम बना देती है।

कुल मिलाकर, अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पश्चिमी गोलार्ध में दबदबा बनाने की वकालत करती है और यूरोप व एशिया में रणनीतिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए अमेरिकी गठबंधन के अग्रिम पंक्ति के देशों पर जिम्मेदारियों का 'भार डालने' का प्रस्ताव करती है। चूंकि एनएसएस अमेरिकी गुट की मौजूदा प्रतिबद्धताओं पर मौलिक रूप से सवाल नहीं उठाती या नई सुरक्षा व्यवस्था की बात नहीं कहती (इसमें बहुध्रुवीयता का उल्लेख नहीं है), इसलिए इसे ऐसी भू-राजनीति के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें कोई महाशक्ति अपनी उपस्थिति, सैन्य प्रभाव व विदेश नीति से जुड़ी प्रतिबद्धताओं में तेजी से कमी करती है। इसे दुनिया भर में अमेरिका की प्रमुख स्थिति को कम खर्च करते हुए और शक्तिशाली देशों के साथ संघर्ष से बचते हुए संरक्षित करने की इच्छा के रूप में देखा जाना चाहिए।

यह सोच कुछ हद तक चालाकी भरा प्रतीत होती है और इस उलझन को दो अलग-अलग ढांचों के बीच अनसुलझे संघर्ष से समझा जा सकता है, जो हैं- विश्व व्यवस्था के प्रति 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' की सोच और व्यापक अंतरराष्ट्रीय भूमिका में निहित डीप स्टेट के हित। हालांकि, एनएसएस इस बात को गलत ठहराती है कि अमेरिका में व्यापक पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय प्रभुत्व की वैचारिक जड़ें मौजूद हैं।

एनएसएस साफ करती है कि रूस के साथ नाटो का टकराव विफल रहा और चीन को नियंत्रित करना अब व्यावहारिक नहीं है। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करना, युद्ध के अनपेक्षित विस्तार को रोकना, रूस के साथ रणनीतिक स्थिरता को फिर से कायम करना व नाटो के विस्तार को रोकने में ही अब अमेरिका के 'बड़े हित' हैं। चीन के बारे में यह कहती है कि उसके समुद्री विस्तार को रोकने का प्रयास इस तरह से किया जाए कि संघर्ष से बचा जा सके और 'पारस्परिक रूप से लाभकारी' आर्थिक निर्भरता बनी रहे। चीन को उन्नत एच200 सीरीज के चिप निर्यात करने संबंधी व्हाइट हाउस के फैसले को इसी रणनीति का हिस्सा मानना चाहिए। संघर्ष से बचने का एक अन्य उदाहरण चीन-जापान के बीच पैदा तनाव के दौरान बीजिंग को अमेरिका द्वारा दिया गया हालिया आश्वासन है।

यूरोप के बारे में एनएसएस में कहा गया है कि 'यूरोपीय देशों के भीतर यूरोप की मौजूदा दिशा के प्रति प्रतिरोध पैदा करना होगा'। अमेरिका चाहता है कि यूरोप 'अपने सभ्यतागत आत्मविश्वास को फिर से हासिल करे'। यह काफी हद तक ट्रंप द्वारा घरेलू स्तर पर किए गए पुनर्जागरण के प्रयास जैसा होगा। यदि ये घोषणाएं स्पष्ट नीतियों का रूप ले सकीं, जो यूरोपीय संघ में बची हुई वैश्विक व्यवस्थाओं को कमजोर करती हैं, तो इस सोच का यूरोप की भू-राजनीति और भविष्य में पश्चिमी देशों के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? भारत का संक्षिप्त उल्लेख आश्वस्तकारी संकेत देने के इरादे से किया गया है। फिर भी, संपूर्ण दस्तावेज के संदर्भ और इसके अंतर्निहित वैचारिक व भू-राजनीतिक आधार बताते हैं कि नई दिल्ली यदि पुराने प्रतिमानों पर कायम रही, तो उसे सचेत रहना होगा। एकध्रुवीयता के शीर्ष काल में अमेरिका ने भारत को लेकर जो कल्पना की थी, वह दौर अब बीत चुका है और विश्व स्तर पर बदलता शक्ति समीकरण वास्तविक व स्थायी है।

एनएसएस को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि भारत अब भी वाशिंगटन के रडार पर मौजूद है, बल्कि यह समझने के लिए इस पर गौर करना चाहिए कि अमेरिका पश्चिमी प्रशांत में चीन के प्रति अपने 'दुश्मन-दोस्त' रवैये में भारत को किन उद्देश्यों के लिए उपयोगी मानता है? निस्संदेह, भारत अब भी अमेरिका के लिए अहम है। हालांकि, इस साल मध्य-पूर्व में अमेरिकी नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था में पाकिस्तान के शामिल होने पर एनएसएस की चुप्पी यही बताती है कि यह उप-महाद्वीप अमेरिका-भारत रिश्ते में टकराव व अनिश्चय का क्षेत्र बन गया है। पाकिस्तान व उसकी सेना के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता, जो पिछली नीति का एक स्थायी कारक है, भू-राजनीतिक स्तर पर मजबूत हुई है, और यह विडंबना है कि इस नीति को अमेरिकी डीप स्टेट का समर्थन हासिल है। इस वजह से यह ऐसा दुर्लभ मसला भी है, जिस पर विभाजित अमेरिका में भी सहमति है।

यह राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति कहती है, 'अमेरिका द्वारा एटलस की तरह पूरी विश्व व्यवस्था को सहारा देने के दिन अब लद गए हैं'। लगता यही है कि बिना साफ तौर पर इसका समर्थन किए, अमेरिका ने बहुध्रुवीय विश्व की जरूरत को मान लिया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अब समूची मानवता की साझा सांस्कृतिक पूंजी दीपावली

परिचय दास | प्रोफेसर, नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय, नालंदा

यहां स्कैन करें

दीपों की रात अब केवल हमारे आंगन की सीमित उजास नहीं रही; वह विश्व-संस्कृति की साझा स्मृति बनकर फैल गई है। अयोध्या में दीपावली के पंक्तिबद्ध दीये भगवान राम के स्वागत में मंगल वातावरण रचते रहे हैं। दीपावली, जिसके दीये पीढ़ियों से हमारे घरों में जलते रहे, अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल होकर वैश्विक परंपराओं की विशाल पंक्ति में अपना स्थान पा चुकी है।

दीपावली की परंपरा केवल प्रकाश की नहीं है; यह अपने भीतर स्मृतियों का एक बहता हुआ कुंभ है। घर-आंगन की सफाई, रंगोली की मौन भाषा, घी के दीयों की लौ, सामुदायिक मेल-जोल, त्योहार की खरीदारी, छोटे-छोटे व्यावसायिक केंद्रों का जीवंत हो उठना- इन सबका सम्मिलित नाद दीपावली कहलाता है। यही वे तत्व हैं, जो इसे विश्व-धरोहर के रूप में विशिष्ट बनाते हैं, क्योंकि यह उत्सव न सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता, परंपरा के हस्तांतरण और रचनात्मक लोक-शिल्प का जीवित दस्तावेज भी है। यूनेस्को द्वारा इसके चयन का अर्थ है कि अब यह उत्सव समूची मानवता की साझा सांस्कृतिक पूंजी है। दीपावली का समावेश हमारे सांस्कृतिक वैभव को और अधिक समृद्ध करेगा।

वैश्विक विरासत का दर्जा मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम दीपावली की सांस्कृतिक आत्मा को सुरक्षित रखें।

इसके पहले यूनेस्को ने भारत की सबसे पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों में से एक, उत्तर भारत में *रामायण* पर आधारित नाट्य-प्रदर्शन रामलीला को 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत करार दिया था। उसी साल उसने वैदिक मंत्रों के मौखिक जप को भी इस सूची में शामिल किया। साल 2010 में यूनेस्को ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल व झारखंड में प्रचलित युद्ध-आकर्षक लोकनृत्य-परंपरा छऊ और राजस्थान के कालबेलिया समुदाय द्वारा प्रस्तुत नाग-नृत्य-आधारित लोक-परंपरा कालबेलिया नृत्य को सांस्कृतिक विरासत की मान्यता दी; बाद के वर्षों में केरल की लोक धार्मिक नाट्य-परंपरा मुडियेट्टु; योग, कुंभ-मेला, दुर्गा पूजा, भोजपुरी गीत परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया। कर्नाटक व केरल में नृत्य-पूजा का अनुष्ठान थेय्यम और गुजरात का गरबा अभी यूनेस्को की आधिकारिक सूची में शामिल नहीं हैं; मगर ये प्रस्तावित परंपराएं हैं।

भारत यूनेस्को द्वारा घोषित 42 विश्व विरासत स्थलों का एक गौरवशाली देश है। अजंता-एलोरा की गुफाओं से लेकर कुतुब मीनार, हम्पी, खजुराहो, जयपुर, ताजमहल और सुंदरवन जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों तक यह सूची भारतीय सौंदर्य, वास्तुकला और विविध पर्यावरण का जीवंत सूचकांक बनकर खड़ी है। इन धरोहरों में साल 2016 में जुड़ा श्री नालंदा महाविहार प्राचीन भारत का सबसे बड़ा, व्यवस्थित और अंतरराष्ट्रीय स्वरूप वाला विश्वविद्यालय था। नालंदा केवल ईंट-पत्थरों का अवशेष नहीं, यह वह प्रकाश-स्तंभ था, जहां से ज्ञान की रोशनी बटोरने विश्व के कोने-कोने से विद्यार्थी आते थे।

यूनेस्को की मान्यता का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। शोध बताते हैं, वैश्विक विरासत की सूची में किसी स्थल या परंपरा के शामिल किए जाने से पर्यटन, वैश्विक रुचि व संस्कृति-आधारित आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। भारत में 2023 में लगभग एक करोड़, 90 लाख विदेशी पर्यटक आए व पर्यटन क्षेत्र ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान किया। यूनेस्को की मान्यता अपने साथ दायित्व भी लाती है। सुरक्षा, संरक्षण, सुदृढ़ प्रबंधन और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रामाणिक प्रस्तुतिकरण का दायित्व। दीपावली को अब जब वैश्विक विरासत का दर्जा मिल गया है, तब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम इस त्योहार की सांस्कृतिक आत्मा को सुरक्षित रख सकें, कारोबारी चमक-दमक के बीच उसकी गरिमा खोने न दें।

दीपावली का वैश्विक होना तभी सार्थक होगा, जब इसके कारण मिट्टी के दीये बनाने वाले कुम्हारों, रंगोली रंगने वाली स्त्रियों, लोक गीत गाने वाले समुदायों, हस्तशिल्पकारों और छोटे बाजारों को नए अवसर मिलेंगे और उन्हें नया सम्मान मिलेगा। यह चयन एक निमंत्रण है- अपने भीतर के दीप को पहचानने और विश्व के सामने अपनी सांस्कृतिक भूमि की उजास को नए आयामों में प्रस्तुत करने का। यह क्षण हमें स्मरण कराता है कि संस्कृति सिर्फ 'दिखाने' की चीज नहीं, जीने की प्रक्रिया है, जिसे सुरक्षित रखना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

विशेषज्ञ की कीमत

बात 1920 के आस-पास की है। प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड के रिवर रूज प्लांट में एक विशाल जेनरेटर अचानक बंद हो गया। फोर्ड की अपनी इंजीनियरिंग टीम भी समस्या पकड़ नहीं पाई। तब बुलाया गया चार्ल्स स्टाइनमेट्ज को। वह उस समय अमेरिका के जीनियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। स्टाइनमेट्ज केवल एक नोटबुक, पेन और एक फोल्डिंग खाट लेकर पहुंचे। दो दिन दो रात तक उन्होंने मशीन की हर आवाज, हर कंपन को महसूस किया और वह जटिल गणनाएं करते रहे। फिर वह सीढ़ी लेकर जेनरेटर के ऊपर चढ़े, एक खास जगह पर निशान लगाया और टीम को ठीक उस जगह से 16 तारों की कुंडली खोलने का निर्देश दिया। वे तार एक-दूसरे में गुथ गए थे। बस, इतना करते ही जेनरेटर फिर से चल पड़ा, एकदम सही तरीके से!

कुछ दिनों बाद हेनरी फोर्ड को स्टाइनमेट्ज का बिल मिला- दस हजार डॉलर। उन दिनों दस हजार डॉलर, यानी आज के दस करोड़ डॉलर के बराबर थे। हेनरी फोर्ड चौंक गए और उन्होंने तफसील के साथ बिल मांगा, क्योंकि स्टाइनमेट्ज की टीम ने सिर्फ दस मिनट के अंदर गुथे हुए तार खोल दिए थे। फोर्ड ने सोचा, ऐसा कौन सा बड़ा काम था?

स्टाइनमेट्ज ने नया बिल भेजा- चॉक का निशान लगाने के लिए : 1 डॉलर। सही जगह पर निशान लगाने का ज्ञान : 9,999 डॉलर। फोर्ड स्वयं एक जीनियस थे, वह स्टाइनमेट्ज का भाव समझ गए और बिना एक शब्द कहे, पूरा भुगतान कर दिया। यह छोटा सा वाकया एक किंवदंती बन गया है। यह आज भी इस बात की मिसाल है कि विशेषज्ञता की कोई निश्चित कीमत नहीं लगाई जा सकती। वस्तुतः यह आदमी की प्रतिभा का कमाल है, जिसे रुपये से तौला नहीं जा सकता।

इस कहानी को ओशो ने कई बार सुनाया है। विशेषज्ञ वह है, जो छोटे से छोटे विषय के बारे में अधिक से अधिक जानता है। कोई भी काम सफलतापूर्वक कर देने के बाद बिल्कुल सरल लगता है। ऐसा लगता है कि यह काम तो एक बच्चा भी कर सकता है। हम भी कर लेते, लेकिन असली बुद्धिमानी वह है, जो दिखाई नहीं देती। शारीरिक श्रम तो दिखाई देता है, इसलिए मोटे काम करने वालों को लगता है कि कंपनी के संचालक क्या काम करते हैं! सिर्फ बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन वही काम जिम्मेदारी का होता है। जो सूक्ष्म है, वही असली कीमती है।

कोई भी काम सफलतापूर्वक कर देने के बाद बिल्कुल सरल लगता है। ऐसा लगता है कि यह तो एक बच्चा भी कर सकता है, लेकिन असली बुद्धिमानी वह है, जो दिखाई नहीं देती।

मंजिल पर पहुंचने के बाद बहुतों को लगता है कि क्या जरूरत थी किसी के सहारे की? अपना ही खजाना था, अपने को ही पाना था। मगर जब तक नहीं पहुंचते, तब तक अज्ञान का अंधेरा ऐसा घना होता है कि किसी का मार्गदर्शन न मिले, तो भटकना सुनिश्चित लगता है। इसलिए विशेषज्ञ को मुंहमांगी फीस देनी चाहिए।

अमृत साधना

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति

सदियों पुरानी हमारी हस्तशिल्प की परंपरा आज भी जीवंत है, तो इसके पीछे है हमारे शिल्पकारों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही प्रतिबद्धता। हस्तशिल्प को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र कमजोर वर्गों के लोगों को संबल प्रदान करता रहा है।

अनुलोम-विलोम

बांग्लादेश चुनाव

बांग्लादेश में चुनाव एक सकारात्मक कदम

बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने गुरुवार को आम चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया। लंबे समय से संकट में फंसे बांग्लादेश से यह सकारात्मक समाचार आया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरुद्दीन ने तारीखों की घोषणा की। प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना को हटाने के बाद देश में यह पहला आम चुनाव हो रहा है। बांग्लादेश में साल 2025 में 12 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद अब चुनाव की तारीखों का एलान किया गया है। आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही वह रास्ता है, जिससे अंततः संकटों पर विजय पाई जा सकती है।

इसके साथ ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के कार्यकाल को बढ़ाने की अटकलों पर भी विराम लग गया है। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही चुनाव की मांग की जा रही थी। फिलहाल, आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग हिस्सा नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में, मुख्य मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-बांग्लादेश के बीच होने की संभावना है। हालांकि बेगम जिया भी जेल में बंद थीं और इस समय अपना इलाज कराने लंदन में हैं।

चुनाव आयोग के मुताबिक, मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, सिर्फ कार्यक्रम तय करना ही बाकी था। इससे पहले, बांग्लादेश में जनवरी 2024 में चुनाव हुए थे, जिसमें शेख हसीना ने चौथी बार सत्ता में वापसी की थी। हालांकि, शेख हसीना के प्रतिद्वंद्वियों ने उन चुनावों का बहिष्कार किया था और उन्होंने प्रशासन पर भारी धांधली के आरोप लगाए थे। अब 17.3 करोड़ की आबादी वाला यह देश बदले हुए राजनीतिक माहौल में मतदान करने जा रहा है।

बांग्लादेश में भी भारत के लोकसभा चुनाव जैसे ही चुनाव होते हैं। यहां संसद सदस्यों का चुनाव भारत की तरह ही फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली के जरिये होता है। मतलब जिस उम्मीदवार को एक वोट भी ज्यादा मिलेगा, उसी की जीत होगी। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के सांसद अपने नेता का चुनाव करते हैं और वही प्रधानमंत्री बनता है। अवामी लीग एक चुनाव आधारित पार्टी है। इसमें लोगों के सामने खड़े होने की ताकत है। अपनी स्थापना के बाद से बांग्लादेश अवामी लीग ने 13 चुनावों में से 9 में जीत हासिल की है और सरकार बनाई है।

संगीता ठाकुर, गृहिणी

देश को गहरे संकट में धकेलने की योजना

बांग्लादेश में अभी चुनाव का एलान नहीं होना चाहिए था। यह सही समय नहीं है। शेख हसीना की पार्टी का उचित कहना है कि मोहम्मद यूनुस पूरे बांग्लादेश को गहरे संकट में धकेलने की योजना बना रहे हैं। बांग्लादेश अवामी लीग ने घोषित चुनाव कार्यक्रम को खारिज कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि देश में जो माहौल है, उसमें चुनाव संभव ही नहीं है।

वैसे, बांग्लादेश की दोनों मुख्य पार्टियों की नेता लंबे समय से देश से बाहर हैं। शेख हसीना तो छात्र आंदोलन के बाद से भारत की शरण में हैं, जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की नेता खालिदा जिया इलाज के लिए इस समय लंदन में हैं। ऐसे में, बांग्लादेश का यह चुनाव केवल आंखों में धूल झोंकना ही साबित होगा। आखिर लोकतांत्रिक नेताओं और उनकी पार्टियों की भागीदारी के बिना कैसा चुनाव कराना चाहती है वहां की अंतरिम सरकार? मुख्य पार्टी अवामी लीग पर तो प्रतिबंध ही लगा दिया गया है।

ऐसी परिस्थिति में ठीक ही बांग्लादेश अवामी लीग ने घोषित चुनाव शेड्यूल को खारिज करते हुए कहा है कि इसमें देश के ज्यादातर लोगों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है। पार्टी ने इसे अवैध सरकार के अवैध चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम करार दिया है। शेख हसीना की पार्टी ने कहा है कि देश में अभी जो माहौल है, उसमे स्वतंत्र, निष्पक्ष और जन-प्रतिनिधिक चुनाव संभव नहीं है। एक विस्तृत बयान जारी करते हुए इस पार्टी ने कहा है कि 'अवैध, कब्जा करने वाले, हत्यारे-फासीवादी यूनुस गुट के अवैध चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव के कार्यक्रम की बारीकी से समीक्षा की गई है। अब यह साफ है कि मौजूदा कब्जा करने वाली अथॉरिटी पूरी तरह से एकतरफा है और उसकी निगरानी में एक ऐसा निष्पक्ष और सामान्य माहौल सुनिश्चित करना नामुमकिन है, जहां पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों की इच्छा दिखाई दे सके।

पार्टियों और ज्यादातर आबादी को बाहर रखते हुए चुनाव कराने की कोशिश करना, देश को गहरे संकट में धकेलने की एक साजिश है। मौजूदा संकट को बढ़ने से रोकने के लिए बांग्लादेश अवामी लीग पर लगाई गई सभी पाबंदियां हटाई जानी चाहिए, बंगबंधु की बेटी शेख हसीना, अन्य नेताओं और हर तरह के लोगों के खिलाफ सभी मनगढ़ंत केस वापस लेने चाहिए, सभी राजनीतिक कैदियों को बिना शर्त रिहा करना चाहिए और मौजूदा व्यवस्था की जगह एक तटस्थ केयरटेकर सरकार बनानी चाहिए, ताकि जन-भागीदारी वाला चुनाव हो सके। इसके बिना चुनाव सिर्फ दिखावा है।

नीलेश मिश्र गोपी, टिप्पणीकार

लचीली सोच का लीजिए लाभ

सोच का लचीला होना, आपकी कमजोरी या ढीलापन नहीं है। दिक्कत तब होती है,जब आप दूसरों को नहीं सुनते, अड़े रहते हैं या फिर बदलाव के साथ खुद को ढाल नहीं पाते। लचीलापन एक जरूरी कौशल है, जिसका अभ्यास रोज के छोटे-बड़े हर पल को सुख, शांति और खुशी से भर सकता है।

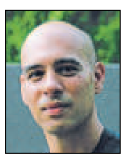

लिओ बॉबटा
लेखक, सिंप्लिसिटी ब्लॉगर। कैलिफोर्निया में रहते हैं। सादगी से जीना पसंद हैं।

मेरे अनुभव में, हम जितने अधिक संकीर्ण होते हैं, उतने ही कम खुश रहते हैं। वहीं जितने अधिक लचीले होते हैं, उतनी ही हमारी खुशी की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि, यह कोई गारंटी नहीं है। सोच के लचीला होने से ही आपको अनंत सुख नहीं मिल जाएगा, लेकिन यह तय है कि खुले दिमाग से सोच पाने की क्षमता हमारे लिए शांति, संतोष और खुशी के अवसर जरूर पैदा करती है।

अपने भीतर की संकीर्णता और अड़ियल रवैये को हम कई तरह से अपने छोटे-बड़े व्यवहार में महसूस कर सकते हैं। कुछ आम उदाहरण हैं-

■ लोगों के प्रति असहिष्णु होना ■ हमेशा सही होने की जरूरत ■ दूसरों को अपने तरीके से चलाने की कोशिश ■ निश्चितता और नियंत्रण की जरूरत ■ दूसरों को अपने से अलग राय रखने की अनुमति न देना ■ नई जानकारी और बदलावों के साथ खुद को अपडेट न करना ■ योजनाओं में बदलाव से नाखुश होना ■ अपने बारे में स्थिर विचार रखना (मैं ऐसा ही हूं या मैं कभी नहीं कर सकता, जैसी सोच)।

ऐसे हजारों उदाहरण हो सकते हैं, जिनके जरिये हम अपनी संकीर्णता की पहचान कर सकते हैं। एक सप्ताह तक अपने विचारों और व्यवहार पर बारीकी से गौर करें और उन बातों को लिखें, जहां आप अधिक बेहतर ढंग से व्यवहार कर सकते थे।

अब सवाल है कि सोच का लचीला न होना हमारे तनाव, हताशा, चिंता और परेशानियों को कैसे बढ़ा देता है? आइए इसे समझें :

बदलाव होने पर तनाव या हताशा

जीवन स्थिर नहीं है। यह लगातार बदलता रहता है। बहुत कुछ अनिश्चित है। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से होने के बाद भी उलटफेर हो सकता है। सब कुछ हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता।

ऐसे में अगर हमारी सोच सीमित है, हम अड़े रहे हैं, तो बदलाव हमें खतरा लगता है, जिससे तनाव और हताशा पैदा होती है।

संबंधों में दूरी आना

अगर हम हमेशा सही होने पर अड़े रहें, दूसरों की न सुनें या हमारे ढंग से काम न करने पर लोगों से नाराज रहें, दूसरों के बारे में गलत राय बनाते रहें, तो इससे हमारे रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। दूसरे लोग हमारे साथ होने पर खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं और हमसे दूरी रखने लगते हैं।

सही फैसले न ले पाना

हम कोई निर्णय नहीं ले पाते। हम सब कुछ सही करने या बिल्कुल सही जवाब खोजने की कोशिश में अटके रह जाते हैं। पूर्णता की चिंता हमें रोक देती है। हम हर स्थिति को, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते कि भले सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो, जीवन फिर भी अनिश्चित और अप्रत्याशित ही रहेगा।

अपने पुराने मानकों पर ही चीजों को पूरा करने की मानसिकता के कारण हम पीछे रह जाते हैं। बदलाव के अनुसार खुद को बदल नहीं पाते। इससे स्वयं से असंतोष पैदा होता है। इसी तरह जब दूसरे हमारे मानकों पर काम नहीं कर पाते तो हम उनसे निराश हो जाते हैं।

अटके रहना, बढ़ न पाना

हम अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं, भले ही वे काम न कर रही हों। संकीर्ण सोच हमें नया सीखने या विकास के लिए खुला नहीं रहने देती। हम अपने 'मैं ऐसा ही हूं' वाले विचारों में जकड़ जाते हैं। यह अड़ियल रवैया समस्या सुलझाने की क्षमता कम कर देता है, क्योंकि हम नए समाधान देख नहीं पाते। हमारी कुंद सोच अनिश्चितताओं को खुले मन से स्वीकार करने से रोकती है और हम दुखी रहते हैं।

कैसे बढ़ाएं लचीलापन

यह एक सरल इरादे से शुरू होता है : लचीला बनने का इरादा। 'लचीले बनें, खुश रहें' यह वाक्य हमें इसी इरादे की याद दिलाता है। इसके बाद, हमें यह नोटिस करना होगा कि कब हमारे संकीर्ण विचार तनाव या हताशा पैदा कर रहे हैं। यदि आप अपने आप से, किसी दूसरे व्यक्ति से या योजनाओं में बदलाव से परेशान हैं तो बस पहले यह नोटिस करें कि आप निराश महसूस कर रहे हैं। फिर दूसरों या खुद को दोष देने के बजाय, यह देखना शुरू करें कि कौन से विचार इसमें योगदान दे रहे हैं। अब देखें कि यह कुंद सोच बेचैनी, कंपन, तनाव या घबराहट किस रूप में महसूस हो रही है। इसके बाद निम्न उपाय अपनाएं-

1 गहरी सांसें लें। हर सांस को आते-जाते देखें। अपनी हताशा को शांत करें। हर सांस के साथ शरीर के तनाव को ढीला करें।

2 खुद से पूछें, मैं इस क्षण में कैसे अधिक लचीला हो सकता हूं? आप खुद को याद दिला सकते हैं कि जीवन अनिश्चित और अनियंत्रित है- और यही इसकी सुंदरता का हिस्सा है। आप चीजों को जैसे हैं, वैसे स्वीकार करने की कोशिश कर सकते हैं। जब मैं ऐसा करता हूं, तो सामने वाले व्यक्ति या परिस्थिति में सुंदरता दिखने लगती है।

3 खुद से पूछें, 'मैं बिना सब कुछ नियंत्रित किए, इस क्षण को लचीले ढंग से कैसे संभाल सकता हूं?' मेरे लिए इसका मतलब है- अगला छोटा कदम लेना, बिना यह उम्मीद रखे कि सब कुछ परफेक्ट हो।

एक उदाहरण
मान लीजिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति से परेशान हूं, जो बहुत शिकायत कर रहा है। मैं नोटिस करता हूं कि मैं उसकी शिकायतों से निराश हूं और मेरा शरीर तनावग्रस्त हो गया है। फिर मैं सांस लेता हूं, अपने शरीर के तनाव को ढीला करता हूं। अब मैं उस व्यक्ति को उनकी वर्तमान अवस्था सहित- उसकी शिकायतों सहित देखता और स्वीकार करता हूं। मैं सराहता हूं कि वे परवाह करते हैं। मैं देख पाता हूं कि वे तनाव में हैं और मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं।

और अंत में, मैं अगला छोटा कदम लेता हूं। शायद मैं उनसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहूं या सहानुभूति के साथ उनकी बात सुनूं, लेकिन मुझे उन्हें नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। हर परिस्थिति में कुछ किया ही जाए यह जरूरी नहीं। यदि आप ऊपर दिए गए शुरुआती कदम उठाएंगे, तो आप अधिक खुला, शांत और लचीला होकर बेहतर निर्णय ले पाएंगे।

-zenhabits.net

काम की बात

अपनी सामाजिक सेहत बढ़ाएं

हम भले कहें कि हमें किसी की जरूरत नहीं है या हमें अकेले रहना पसंद है, पर समय के साथ यह आजादी बोझ बन जाती है। अपने समाज और परिवेश से जुड़ना हमारी सेहत के लिए जरूरी है। विशेषज्ञ इसे सामाजिक सेहत कहते हैं।

अपने बड़ों को अक्सर यह कहते सुना है- सब जाने का आना है। आज हम किसी के यहां जाएंगे, तो कल कोई हमारे यहां आएगा।' यह बात याद आ रही है, क्योंकि दुनियाभर में वैज्ञानिक सोशल हेल्थ में आ रही गिरावट पर चेता रहे हैं। नए तौर-तरीकों व तकनीक के बीच कुछ लोग व्यस्त हैं। कुछ अपने में ही मस्त हैं और कुछ अकेले रहने को मजबूर। विशेषज्ञों के अनुसार लोगों का अपने समाज और परिवेश से घुलना-मिलना कम हो रहा है, जो सेहत व संबंधों से जुड़ी कई समस्याएं पैदा कर रहा है।

ऐसे बनें सोशल

■ **नए रिश्तों के बीज बोएं :** विभिन्न सामाजिक मंचों से जुड़कर नए संबंध बनाएं। हर सप्ताह कम से कम चार-पांच नए लोगों से जुड़ें।
■ **पुराने करीबियों को न छोड़ें :** अपनों को यह अहसास कराएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं। उनके साथ अच्छा समय बिताएं। लोगों से सीधे मिलें या सप्ताह में कम से कम दो बार दूसरे लोगों से दस मिनट फोन पर बात करें।
■ **दूरी भी रखें :** जीवन में कड़वाहट बढ़ाने वाले, आपको गलत राय देने वालों से दूर हो जाएं।
■ **मदद करें, मदद लें :** दूसरों से मदद मांगने और उन्हें अपना सहयोग देने से पीछे न हटें। दूसरों के कमजोर पलों में उन्हें अच्छा महसूस कराएं। दूसरों से नरमी से पेश आएं।
■ **सीमाओं का ध्यान रखें :** दूसरों के समय और सुविधा का ध्यान रखें। उनकी मदद का गलत फायदा न उठाएं।

लंबी उम्र से भी है संबंध

यूएस सर्जन जर्नल में छपे एक लेख में शोधक स्टीवन क्रेन के अनुसार, 'ज्यादातर लोग लंबी उम्र के लिए व्यायाम और अच्छे खानपान पर जोर देते हैं। पर सेहत का एक और स्तंभ है-सोशल हेल्थ। लंबे समय तक अपने आसपास से हमारे खराब संबंध अकेलापन, निराशा, उदासी, बेचैनी और गुस्से के अहसास को बढ़ा देते हैं।' विभिन्न शोधों के अनुसार अकेलापन हृदय रोगों के खतरे को 29 %, डिमेंशिया 50 %, डिप्रेशन 77 %, असमय मृत्यु 29 % और डायबिटीज 49 % तक बढ़ा सकता है।

युवा भी चपेट में

जिन लोगों के दूसरों के साथ अच्छे संबंध होते हैं, वे अपनी समस्याएं बेहतर ढंग से सुलझा पाते हैं। डॉ. क्रेन कहते हैं, 'युवा अपने काम और मनोरंजन के लिए जितना फोन और डिवाइसेस से जुड़े हैं, उतना लोगों से नहीं। इस्तेमाल की सीमा न होने के कारण युवा खुद को फोन व डिजिटल उपकरणों में खपा रहे हैं। दूसरों से घुलने-मिलने और असल रिश्तों में बढ़ती दूरियों को दूर करने के लिए उनके पास समय और ऊर्जा ही नहीं है।'

मनोविज्ञानी भी मानते हैं कि बहस या विवाद को बातचीत से कैसे सुलझाना है, युवाओं में इस कौशल की कमी हो रही है। किसी सामाजिक कार्यक्रम व पार्टी में होने पर दूसरों से बातचीत की पहल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नतीजा, वे सबके बीच होने पर भी अपने फोन में ही व्यस्त रहते हैं। सवाल है कि सामाजिक सेहत को कैसे सुधारा जाए? यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया और जेनवेल प्रोजक्ट के शोधकों का मानना है, हर सप्ताह पांच लोगों से जुड़ें। इसमें परिवार व दोस्त ही नहीं, पड़ोसी, अजनबी व सहकर्मियों को भी शामिल करें। एक अन्य शोध के अनुसार, जीवन में कम से कम तीन करीबी दोस्त बनाएं, ऐसा करना हमारी खुशी व संतुष्टि को बढ़ाता है। शोध तो यहां तक कहते हैं कि सप्ताह में दो से पांच बार दस मिनट फोन पर बात कर लेना भी अकेलेपन, निराशा व बेचैनी के अहसास को कम कर सकता है। अंत में याद रखें, आज आप दूसरों तक हाथ बढ़ाएंगे, तो कल आपके पास भी कई हाथों का साथ होगा।

-पूनम जैन

तनाव के पलों में मन शांत रखना सीखिए

मुश्किल घड़ी में हम कैसा व्यवहार करेंगे, यह तनाव के बारे में हम क्या सोचते हैं, इस पर निर्भर करता है। आपदा को अवसर समझने वाली सोच तनाव के दौरान हमारे काम और सेहत दोनों पर अच्छा असर डालती है। तनावपूर्ण स्थितियों में अपने नजरिये को कैसे दुरुस्त रखें, आइए जानें

विविध

■ **अपने तनाव को पहचानें :** खुद से सवाल पूछें कि मौजूदा मुसीबत को आप किस तरह देखते हैं? क्या आप इसे बोझ, खतरा या ऐसे काम की तरह देखते हैं, जिससे आप बचना चाहते हैं? या फिर इसे एक चुनौती या विकास का अवसर मानते हैं?

अपनी मानसिक स्थिति की पहचान करना बदलाव की तरफ आपका पहला कदम होगा।

■ **तनाव को अर्थपूर्ण बनाएं :** अपनी बीती तनावपूर्ण स्थितियों पर विचार करें और सोचें कि उस दौरान क्या हुआ था? जैसे, क्या तनाव बढ़ने के कारण आप अपने काम को ज्यादा फोकस के साथ कर रहे थे? क्या विवाद और कलह की स्थिति में बातचीत को बनाए रखते हुए अपनी जरूरत को सामने रख पाए थे? या फिर आर्थिक तंगी होने पर भी आपने बजट और निवेश के बेहतर विकल्पों का चुनाव किया था? नौकरी में दिक्कत आने पर अपनी खूबियों और उद्देश्यों पर विचार किया था?

इस तरह सोचने पर आप तनाव को अपनी तरक्की के पलों से जोड़कर देख पाते हैं।

■ **अपने लक्ष्य के बारे में सोचें :** तनाव के दौरान शरीर में हो रही कंपन, घबराहट पर सोचने की बजाय अपना ध्यान अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएं। इस पर विचार करें कि आपने क्या सीखा, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं ?

इस अभ्यास से आप सीखते हैं कि आपको किस बात की चिंता करनी है, किसे छोड़ देना है।

■ **अपनी प्रतिक्रिया को सहज बनाएं :** खुद को याद दिलाते रहें कि तनाव के दौरान भी आप संतुलित प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस तरह जो आपके लिए जरूरी है, उस पर आप पकड़ बनाए रख पाएंगे। आपको अपनी भावनाएं दबाने की जरूरत नहीं है। बस चिंता करने की बजाय अपने शरीर, अपनी ऊर्जा और मजबूत पक्षों पर पकड़ बनाए रखें।

तनाव के दौरान की सहज प्रतिक्रिया, आपको बड़े नुकसान से बचाती है।

■ **सकारात्मक चीजों पर ध्यान :** जब तनाव बढ़ जाए, तो यह आदत डालें कि यह तनाव किस तरह मदद कर रहा है। आपकी ऊर्जा, एकाग्रता, प्रेरणा और उत्साह पर इसका अच्छा असर पड़ रहा है।

इस तरह तनाव से जुड़ा आपका डर कम होगा, आप बेहतर काम कर पाएंगे।

एकदा

कीमत

एक जाने-माने वक्ता ने खचाखच भरे हॉल में हाथ में पांच सौ का नोट लहराते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों से पूछा, 'ये पांच सौ का नोट कौन लेना चाहता है?'

लोगों ने हाथ उठना शुरू किया। इसके बाद वक्ता ने कहा, 'मैं इस नोट को आपमें से किसी एक को दूंगा, पर उससे पहले मुझे कुछ कर लेने दीजिए। उसने नोट को मोड़ना, मसलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उस मुड़े-तुड़े नोट को दिखाकर फिर पूछा, 'अब कौन है, जो इस नोट को लेना चाहता है? लोगों के हाथ फिर से उठने शुरू हो गए। उसके बाद उसने नोट को वहां पड़ी मिट्टी में डालकर मसलना शुरू कर दिया। अब नोट बिल्कुल गंदा हो गया था। उसमें सिलवटें ही सिलवटें थी। वक्ता ने फिर से नोट उठाया और कहा, 'क्या अभी भी कोई है, जो इसे लेना चाहता है?

इस बार भी हाथ उठने शुरू हो गए। इसके बाद वक्ता ने कहना शुरू किया, 'आप लोगों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया पर फिर भी आप इसे लेना चाहते थे, क्योंकि ये सब होने के बावजूद भी नोट की कीमत घटी नहीं। उसका मूल्य अभी भी 500 है। जीवन में हम कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं, हमारे लिए हुए निर्णय हमें मिट्टी में मिला देते हैं। हमें लगता है कि हमारी कीमत ही नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके साथ चाहे जो हुआ हो या भविष्य में जो हो जाए, आपका मूल्य कम नहीं होता। इस बात को कभी मत भूलिए। बीते हुए कल की निराशा से आने वाले कल को बर्बाद मत करने दीजिए। याद रखें, आपके पास जो सबसे कीमती चीज है, वो है आपका जीवन।'

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, परंतु कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

वृष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परंतु स्थान परिवर्तन हो सकता है।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। संतान की सेहत का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें।

सिंह : मन परेशान हो सकता है। आत्म संयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। नौकरी में अफसरों से व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।

कन्या : मन परेशान हो सकता है। वाणी में मधुरता रहेगी। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भाग-दौड़ अधिक रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

तुला : मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी, लेकिन बातचीत में संतुलन बनाए रखें। किसी पारिवारिक कारोबार की फिर से शुरुआत हो सकती है। बेकार की बहस में न पड़ें।

वृश्चिक : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। मानसिक शांति बनाए रखने के प्रयास करें। बातचीत में संतुलित रहें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। सेहत का ध्यान रखें।

धनु : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। कारोबार में बदलाव की संभावना बन रही है। भागदौड़ अधिक रहेगी।

मकर : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। कारोबार का विस्तार हो सकता है, परंतु किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

कुंभ : मन परेशान हो सकता है। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

मीन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, पर मन परेशान भी हो सकता है। संतान की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कारादि में सफलता मिलेगी।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

15 दिसंबर, सोमवार, **शक संवत्**: 24 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग**: 01 पौष मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम**: 23 जमादि-उल्सानी, 1447, **विक्रमी संवत्**: पौष कृष्ण एकादशी रात्रि 09.21 बजे तक पश्चात द्वादशी तिथि, चित्रा नक्षत्र प्रातः 11.09 मिनट तक पश्चात स्वाती नक्षत्र, बव करण। चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 9 बजे तक राहुकालम्। सफला एकादशी व्रत। पौष संक्रांति।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हनुमानजी की शक्ति का वास्तु अनुसार किस प्रकार उपयोग करें। -हेमा झा, बेगूसराय

■ यदि बीमारी नहीं जा रही है, तो संजीवनी बूटी वाला हनुमानजी का चित्र घर में उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। धन की समस्या की समस्या हो, तो सीताराम के साथ हनुमानजी का चित्र पूर्व की दीवार पर लगाएं। यदि प्रॉपर्टी का कोई विवाद या समस्या हो, तो वर मुद्रा वाले हनुमानजी का चित्र उत्तर दिशा में लगाएं। यदि परेशानियां ज्यादा हों, तो गदाधारी हनुमानजी का चित्र पूर्व दिशा में लगाएं। यदि नौकरी नहीं मिल रही हो या फिर व्यवसाय में समस्या हो, तो रामायण पढ़ते हुए हनुमानजी का चित्र लगाएं। यदि विदेश यात्रा में समस्या हो, तो झंडे वाले हनुमानजी का चित्र उत्तर पश्चिम दिशा में लगाएं।

वर्ग पहेली : 8179

बाएं से दाएं
3. अन्यायी; अत्याचारी; जालिम (5)
6. कंपकंपा देने वाली ठंडी हवा; बर्फानी हवा; अत्यंत शीतल हवा (2,3)
7. नाश करने वाला; मारने वाला; समाप्त करने वाला; हटाने वाला (3)
8. चमड़े की रगड़ से हुआ घाव (4)
9. सरकना; टलना; दूर होना; पीछे होना; विस्थापित होना (3)
10. थक जाना; पराजित होना; विफल होना (3)
11. जो बहुत अधिक तर हो गया हो; बहुत अधिक भीगा हुआ; बहुत अधिक सना हुआ (4)
12. अनुचित इच्छा; लोभ (3)
15. देखभाल; देखरेख; पालन पोषण; साज संभाल (2,3)
16. ख्याति प्राप्त करना; प्रसिद्धि पाना; दोष मढ़ना; हस्तांतरण करना (2,3)

ऊपर से नीचे
1. उपकरण; कल; यंत्र (3)
2. बिक्री करना; व्यापार करना; सामान बेचना (2,3)
3. आशीर्वाद देना; आश्वासन देना (2,2,2,3)
4. साल का बारहवां भाग; मास; माह (3)
5. बचाव करना; रखवाली करना; सुरक्षित रखना (2,3)
9. आक्रमण होना; चढ़ाई होना; लड़ाई होना (3,2)
10. आशीर्वाद देना; सहायता करना; सहारा देना (2,3)
13. ज्योति; आभा; कांति; दमक; प्रकाश (3)
14. सभागार; स्थान; बड़ा मकान; जगत (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8178

■	1 दु	2 ब	क	ना	■	3 आ	■	4 दि
5 अ	■	हु	■	■	6 स	म	त	ल
7 प	छ	ता	वा	■	■	द	■	में
मा	■	य	■	8 द	■	■	9 बा	घ
नि	■	10 त	मा	श	बी	11 न	■	र
12 त	ना	■	■	क	■	म	■	क
क	■	13 प	■	■	14 ही	न	हा	र
15 र	सा	त	ल	■	■	शी	■	ना
ना	■	ला	■	16 ब	द	ल	ना	■

सुडोकू : 8161

* आसान

8			1				9	
	9		8	4			7	3
	7				2	4		
4		8	7					
	1						8	
					1	9		5
		6	5				1	
7	5			3	6		2	
	8				4			6

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8160

1	3	6	4	5	2	9	8	7
9	4	7	1	3	8	2	5	6
2	5	8	9	6	7	3	4	1
5	8	2	6	1	9	7	3	4
4	1	3	7	2	5	6	9	8
6	7	9	8	4	3	1	2	5
7	6	5	2	9	4	8	1	3
3	2	1	5	8	6	4	7	9
8	9	4	3	7	1	5	6	2

एक मतदाता हमेशा जानता है कि उसे अपने वोट से कितना लाभ होगा। - जुप्का वितानोवा

कोलकाता में मेसी के दौरे के दौरान कुप्रबंधन के लिए भले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांग ली हो, लेकिन आयोजकों और नीति नियंताओं को खुद से पूछना चाहिए कि जब इतने बड़े कद का खिलाड़ी आ रहा हो, तो क्या तैयारियों का स्तर भी ऊंचा नहीं होना चाहिए था।

कोलकाता में कुप्रबंधन

फुटबॉल के महानायक लियोनल मेसी की भारत यात्रा का आगाज कोलकाता में हुआ, लेकिन यहां के साल्ट लेक स्टेडियम में एक उत्साहपूर्ण शुरुआत जिस तरह से पहले अफरा-तफरी और फिर अराजकता में बदली, उसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। मेसी को लेकर दीवानगी इससे ही समझी जा सकती है कि तकरीबन 60 हजार लोग सुपरस्टार खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए अलसुबह से स्टेडियम में जमे हुए थे। आखिरकार सुबह के करीब साढ़े ग्यारह बजे जब अर्जेंटीना के विश्वकप विजेता कप्तान मेसी ने मैदान पर कदम रखा, तब भी दर्शक उन्हें नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उन्हें विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व कुछ अन्य ने सेल्फी के लिए घेर रखा था। कुछ ही मिनटों बाद सुरक्षा का हवाला देते हुए मेसी को वहां से निकाल लिया गया। हजारों रुपये के टिकट लेने के बावजूद जब प्रशंसकों को मेसी की एक स्पष्ट झलक तक नहीं मिली, तो उनके धैर्य को जवाब देना ही था। मेसी की मात्र 22 मिनट की संक्षिप्त उपस्थिति और कुप्रबंधन ने हालात को बेकाबू बना दिया और कुछ ही देर में नाराज दर्शक कुर्सियां उखाड़कर मैदान में उतर आए। यह घटना न केवल खेल आयोजनों की कमियों को उजागर करती है, बल्कि हमारे समाज में वीआईपी संस्कृति और आम जनता की भावनाओं के बीच की खाई को भी रेखांकित करती है। कोलकाता में ऐसा होना तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे अक्सर देश की फुटबॉल राजधानी कहा जाता है और जहां के लोगों में इस खेल के प्रति कहीं अधिक जुनून पाया जाता है। पेले और मेराडोना जैसे महान फुटबॉल खिलाड़ी कोलकाता आ चुके हैं, खुद मेसी भी 2011 में यहां एक मैत्री मैच खेलने के लिए आए थे। कोलकाता खुद में वे सभी यादें समेटे हुए है, लेकिन कहना होगा कि इस बार आयोजकों की लापरवाही ने खेल के प्रशंसकों की भावनाओं का अपमान किया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कुप्रबंधन के लिए माफी मांगी है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक

समिति के गठन की घोषणा भी की है। लेकिन आयोजकों और नीति नियंताओं को खुद से पूछना चाहिए कि जब इतने बड़े कद का खिलाड़ी आ रहा हो, तो क्या तैयारियों का स्तर भी ऊंचा नहीं होना चाहिए था। प्रशंसक ही किसी खेल की आत्मा होते हैं, और जब उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो उनके उत्साह को अराजकता में बदलने में देर नहीं लगती। हाल ही में भारत को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है और वह 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की उम्मीद भी कर रहा है। ऐसे में, कोलकाता में जो हुआ, उससे सबक लिया ही जाना चाहिए।

वामपंथी दुर्ग में भाजपा की दस्तक

केरल के स्थानीय निकाय के चुनावी नतीजे जहां सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन एलडीएफ के लिए खतरे के संकेत हैं, वहीं तिरुवनंतपुरम में भाजपा की शानदार जीत पार्टी का मनोबल बढ़ाने वाली है। भाजपा की यह जीत मोदी सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं की वजह से हुई है।

केरल में हुए नगर निगम चुनावों के नतीजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों के करीब जाने, मतदाताओं की समस्याओं को समझने, शिकायतों का समाधान करने और गरीब समर्थक योजनाओं का प्रतिफल हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केरल में जमीनी स्तर (बूथ प्रमुख) पर लगातार काम किया। केरल, जिसे भगवान का अपना देश कहा जाता है, के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे वहां के लोगों के मिजाज को दर्शाते हैं, यानी वामपंथी पार्टी के मुख्यमंत्री पी विजयन को 2026 के विधानसभा चुनावों में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

आर राजगोपालन
वरिष्ठ पत्रकार

वामपंथी पार्टी को सबसे बड़ा झटका तिरुवनंतपुरम से लगा, जहां भाजपा के नेतृत्व वाला राजग गठबंधन निगम के चुनाव में आगे निकल गया, जिस पर भाकपा का 45 वर्षों से राज था। केरल में पिछले दस वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा के 125 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक हिंदू विरोधी उग्रवादी संगठन है, आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या करता था। इसका सीधा कारण यह था कि आरएसएस ईसाई चर्चों के करीब आ रहा था। केरल के स्थानीय निकाय के चुनाव में तीन प्रमुख धर्मों ने भी अहम भूमिका निभाई। नगर निगम चुनावों में, हिंदू भाजपा के साथ थे, ईसाई कांग्रेस के साथ गए, जबकि मुसलमानों ने पूरी तरह से भाकपा का साथ दिया।

अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर के निर्माण ने भाजपा को इसमें मदद पहुंचाई। लेकिन भाकपा हर रोज भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाती थी। गाजा-इस्राइल युद्ध के दौरान भाकपा ने मोदी सरकार पर इस्राइल के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने फलस्तीन संबंधी नीतियों के पक्ष में प्रचार किया। सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी फलस्तीन के पक्ष में लिखे बैग के साथ संसद पहुंचीं और इस्राइल विरोधी नारे लगाए। हालांकि कांग्रेस गुटबाजी में फंसी

हुई थी। एक गुट दूसरे पर आरोप लगा रहा था। इसके अलावा, राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा और भारत जोड़ो यात्रा का भी असर था।

नरेंद्र मोदी सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार ने दस साल तक ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया। प्रधानमंत्री का मासिक संबोधन 'मन की बात', अमित शाह की केरल के कोने-कोने में बार-बार यात्रा, 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक, नतीजों के आधार पर भाजपा को जमीनी स्तर से फिर से खड़ा करना, पोलिंग बूथ एजेंट ढूंढना-इन सबने भाजपा की जीत में प्रमुख भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की हार के नकारात्मक पहलुओं के कई कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से सबरीमाला मंदिर से सोने की कथित चोरी स्थानीय निकाय चुनावों में एक बड़ा मुद्दा था, जिसका इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों (यूडीएफ और भाजपा) ने सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) में नियुक्त लोगों को निशाना बनाने के लिए किया।

सोना चोरी के अलावा, हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में एलडीएफ के पिछड़ने के कई अन्य कारण भी हैं-एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इन्सानों और जानवरों के बीच बढ़ते टकराव का है। केरल की 941 ग्राम पंचायतों में से एक चौथाई को वन्यजीवों के हमलों का सामना करना पड़ा है, जिसे वामपंथी सरकार प्रभावी ढंग से हल नहीं कर पाई है। उच्च महंगाई दर और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों ने लोगों में असंतोष पैदा किया, खासकर कम आय वाले कामकाजी परिवारों में। दूसरी तरफ, भाकपा ने मुस्लिम-बहुल इलाकों में अपना समर्थन खो दिया, क्योंकि यह धारणा बनी कि उसने हिंदुत्व एजेंडे के खिलाफ अपना रुख नरम कर लिया है, साथ ही समुदाय से जुड़े कुछ विवादों पर उसकी चुप्पी को भी इसका कारण माना गया।

इन चुनावों में केंद्रीय केरल में ईसाई जनाधार बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की तरफ वापस चला गया। एलडीएफ ने कल्याण और विकास के क्षेत्र में अपनी दस साल की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया, जो पिछले चुनावों की तरह ज्यादा असरदार साबित नहीं हुआ। इसके उलट, यूडीएफ ने ज्यादा सामंजस्यपूर्ण प्रचार किया, जो कचरा प्रबंधन, भ्रष्टाचार के आरोप और नागरिक सेवाओं जैसे स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित था। पंडालम जैसी कुछ खास नगर पालिकाओं में, एलडीएफ के अंदरूनी झगड़ों ने भी उनकी हार में योगदान दिया। स्थानीय कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) को राज्य भर में स्थानीय निकायों में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी, और कहा कि यह अगले केरल विधानसभा चुनावों से पहले एक मजबूत संकेत है। उन्होंने लिखा- 'केरल के स्थानीय स्व-शासन चुनावों में क्या शानदार नतीजे आए! जनादेश साफ है, और राज्य की लोकतांत्रिक भावना साफ झलक रही है।'

ये नतीजे वाकई कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत हैं, जो पिछले 10 वर्षों से विपक्ष में है। पार्टी को चुनाव से पहले कई झटके लगे थे, जिसमें यौन शोषण की शिकायतों और अंदरूनी कलह के कारण पलक्कड़ के विधायक का पार्टी से निष्कासन भी शामिल था। इसके बावजूद, पार्टी ने अपने प्रचार में सबरीमाला सोने की चोरी के मामले पर ध्यान केंद्रित किया।

इन नतीजों ने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन को भी जश्न मनाने का मौका दिया, जो तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 101 में से 50 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। निगम से जीते दो निर्दलीय अब प्रशासन का भविष्य तय करेंगे, क्योंकि निगम परिषद बनाने के लिए 51 विधायकों की जरूरत है। इसके साथ ही, भाजपा ने 24 ग्राम पंचायतों में भी जीत हासिल की।

इस चुनाव में 'पिनरई विरोधी' भावना और सत्ता का 'अहंकार' साफ तौर पर देखा गया। पिनरई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। भाकपा ने हाल ही में राज्य विधानसभा में तीसरे कार्यकाल के लिए सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया था, जो लगता है कि मतदाताओं को पसंद नहीं आया, कम से कम स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे तो यही दर्शाते हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

कार्ल जंग

जिस चीज से आपको डर लगता है, वही आपको बढ़ने, खुद को समझने और अपने जीवन के गहरे सत्य को जानने का अवसर देती है, और उसका सामना करना आपका काम है, जो व्यक्तित्व विकास की ओर ले जाता है।

वेदना के बिना चेतना का जन्म नहीं होता

जब आप बचपन में ऐसी किसी क्रिया में डूब जाते थे कि समय पलों में गुजर जाता था, वह मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि आनंद, स्वाभाविक जिज्ञासा और पूरी तरह जीने की लालसा की वजह से था। बचपन की मासूमियत, लगन और आत्मा की आवाज में ही आपके सांसारिक कार्यों की कुंजी छिपी है। जहां आपका भय है, वहीं आपका कार्य है। इसका सीधा-सा मतलब है कि जिस चीज से आपको डर लगता है, वही चीज आपको बढ़ने, खुद को समझने और अपने जीवन के गहरे सत्य को जानने का अवसर देती है, और उस डर का सामना करना ही आपका असली काम है, जो व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है। वेदना के बिना चेतना का जन्म नहीं होता।

व्यक्तित्व का असली विकास और आत्म-मिलन वहीं से शुरू होता है, जब हम अपने अचेतन हिस्सों और अपने डर से पर्दा हटाते हैं। यदि आप अपने भीतर की आवाज सुनें, बचपन की उस मासूमियत, उस आनंद, उस भय-रहित जिज्ञासा को फिर से जगाकर अपने जीवन की दिशा बनाएं, तो आपकी यात्रा न केवल अर्थपूर्ण होगी, बल्कि आपकी आत्मा समृद्ध और सच्ची होगी। जब आप किसी भी कार्य को वैसे ही करते हैं, जैसे बचपन में एकाग्र भाव से करते थे, बिना परिणाम की चिंता, बिना दूसरों की राय के, तो आपके कर्म, आपकी राह, आपकी 'सांसारिक गतिविधियां स्वाभाविक हो जाएंगी। फिर संघर्ष, डर, असफलता भी उस सफर का हिस्सा बन जाएंगे, वे आपको कमजोर नहीं करेंगे, बल्कि आपकी चेतना को और गहरा बनाएंगे। हर वह पल, जब आप पूरी तरह 'वर्तमान' में होते थे, तो वह आपकी आत्मा से जुड़ा होता था और तब समय का एहसास नहीं होता था। वही आपकी असली दिशा है। एक बार जब आपने उस दिशा को पहचान लिया, अपने बाल-सुलभ उत्साह, मासूमियत, जिज्ञासा और सच्ची लगन को, तो आपकी जिंदगी की राह खुद ही बन जाएगी। फिर आप किसी बाहरी मान्यता, किसी बाहरी 'सफलता' या 'स्वीकृति' के पिंजरे में नहीं बंधेंगे, क्योंकि आपकी दिशा, आपकी मंजिल, आपकी आत्मा की सच्ची पुकार होगी। जीवन का सच्चा जागरण है, अपने भीतर के सत्य के साथ चलना, और उसी के अनुरूप अपने संसार को अर्थ देना। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, प्रवाह की अवस्था में प्रवेश करना अधिक कठिन हो जाता है। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हम अधिक दायित्व लेते हैं, तो बचपन की उन गतिविधियों से नाता तोड़ना आसान होता है, जो कभी हमें पूरी तरह से अपने में समाहित कर लेती थीं। हालांकि, हम ठोस प्रयास से किसी भी उम्र में प्रवाह प्राप्त कर सकते हैं। अपने बचपन की खुशी पर विचार करें और उसी खुशी से वर्तमान गतिविधियों में जुट जाएं। चुनौतियों का पीछा करें, लक्ष्य निर्धारित करें और प्रवाह के शाश्वत आनंद का अनुभव करें। प्रत्येक वयस्क में एक बच्चा छिपा होता है, एक शाश्वत बच्चा, कुछ ऐसा जो हमेशा बनता रहता है, कभी पूरा नहीं होता है, और निरंतर देखभाल, ध्यान और शिक्षा की मांग करता है। यह व्यक्तित्व का वह हिस्सा है, जो हरदम विकसित होना और संपूर्ण होना चाहता है। अपने जीवन काल में इस बचपन को हमेशा जीवित रखने का प्रयास करें।

मन को खुला रखें

सूत्र

हरेक इन्सान अपनी वर्तमान स्थिति से और बेहतर स्थिति में जाना चाहता है, लेकिन यह ऊर्जा अधिकांश लोगों में उम्र के साथ बढ़ने के बजाय कम होने लगती है। हमारा मन भटकता रहता है। मन का भार अधिक हो जाता है। और हम कुछ करने से पहले नकारात्मक सोच के नीचे दब जाते हैं। हम किसी लक्ष्य तक खुले मन से ही पहुंच सकते हैं।

दूसरा पहलू

जिराफ अपनी लंबी गर्दन की मदद से बेहतर जीवन जी पाते हैं। लेकिन उन्हें लंबी गर्दन होने की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है।

जिराफ की लंबी गर्दन की अजीब पहेली

जिराफ अपनी लंबी गर्दन की मदद से ऊंचे बबूल के पेड़ों पर मौजूद पत्तों तक पहुंच सकते हैं, जबकि अन्य जानवर नीचे भोजन को लेकर आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। संभवतः इसी कारण जिराफ पूरे वर्ष प्रजनन कर पाते हैं और सूखा पड़ने पर भी अन्य जानवरों की तुलना में बेहतर जीवन जीते हैं। लेकिन जिराफ को लंबी गर्दन होने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जिराफ के दिल को सिर तक ऊपर खून पहुंचाने के लिए काफी दबाव बनाना पड़ता है। एक वयस्क जिराफ का रक्तचाप आमतौर पर 200 एमएम एचजी से ज्यादा होता है, जो अधिकांश स्तनधारियों से दोगुना है। आराम करते हुए जिराफ का दिल आराम करते हुए इन्सान की तुलना में अधिक ऊर्जा इस्तेमाल करता है, और सच तो यह है कि उसी आकार के किसी भी दूसरे स्तनपायी जानवर के दिल से वह अधिक ऊर्जा खर्च करता है। हालांकि, जैसा कि हमने *जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी* में दिखाया है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ अपनी लड़ाई में जिराफ के दिल के मददगार उसकी लंबी-लंबी टांगें हैं। हमने अध्ययन में एक जिराफ के खून पंप करने में लगने वाली ऊर्जा का पता लगाया, और इसकी तुलना एक ऐसे काल्पनिक जानवर से की, जिसकी गर्दन ऊंचे पेड़ तक पहुंचने लायक हो, मगर पैर छोटे हों। ऐसे काल्पनिक जानवर में एक आम अफ्रीकी एलांड का शरीर और एक जिराफ की गर्दन थी, जिसे हमने 'एलाफ' नाम दिया। हमने अध्ययन में पाया कि 'एलाफ' अपनी कुल ऊर्जा का लगभग 21 प्रतिशत सिर्फ दिल को चलाने में खर्च करेगा, जबकि जिराफ 16 प्रतिशत और इन्सान केवल 6.7 प्रतिशत ऊर्जा खर्च करते हैं।

रोजर एस. सेमोर

आंकड़ों से पता चलता है कि सभी स्तनधारियों में जिराफ के पानी के गड्ढे से बिना पानी पिए चले जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।

जिराफ के दिल को सिर तक ऊपर खून पहुंचाने के लिए काफी दबाव बनाना पड़ता है। एक वयस्क जिराफ का रक्तचाप आमतौर पर 200 एमएम एचजी से ज्यादा होता है, जो अधिकांश स्तनधारियों से दोगुना है।

अपने लंबे पैरों की मदद से जिराफ अपने दिल को सिर के थोड़ा करीब लाकर खाने से मिली ऊर्जा का लगभग पांच प्रतिशत बचा लेता है। एक साल में यह ऊर्जा बचत 1.5 टन से भी अधिक भोजन के बराबर होती है, जो अफ्रीकी सवाना जैसे कठिन माहौल में, जिंदगी और मौत के बीच का फर्क पैदा कर सकती है। लंबे पैरों से जिराफ के दिल का काम आसान हो जाता है, जबकि लंबी गर्दन से उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन लंबे पैरों की भी उसे कीमत चुकानी पड़ती है। जिराफ को पानी पीते समय अपने आगे के पैर फैलाने पड़ते हैं, जिससे अगर कोई शिकारी आ जाए, तो उसे उठने और भागने में मुश्किल होती है और वह धीमा हो जाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि सभी स्तनधारियों में जिराफ के पानी के गड्ढे से बिना पानी पिए चले जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दिल की ऊर्जा लागत गर्दन की ऊंचाई के सीधे अनुपात में बढ़ती है, इसलिए इसकी एक सीमा होनी चाहिए। दरअसल, इतिहास में कोई भी स्थलीय जानवर वयस्क नर जिराफ से ज्यादा ऊंचा नहीं हो सका। -साथ में एडवर्ड स्नेलिंग (द कन्वर्सेशन से)

आंकड़े

कच्चे तेल का भंडार

वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े खनिज भंडारों में से एक है। हाल ही में अमेरिका के कैरेबियन द्वीप में सैन्य तैनाती को वेनेजुएला ने 'संसाधनों पर डकैती' बताया।

वेनेजुएला	303
सऊदी अरब	267
ईरान	209
इराक	145
यूएई	113

आंकड़े कच्चे तेल भंडार के अरब बैरल में हैं। | स्रोत : OPEC

राजा महिष्मान के चार पुत्रों में लुंभक सबसे दुष्ट था। उसके कर्मों की वजह से उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। आखिर में उसका हृदय परिवर्तित हुआ।

भगवान विष्णु की कृपा

आज सफला एकादशी है, यह भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, चंपावती के राजा महिष्मान के चार पुत्र थे, जिनमें से लुंभक सबसे दुष्ट था। वह जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति में लिप्त था और अपने पिता के धन को बर्बाद करता था। उसके पाप कर्मों से राज्य की प्रजा दुखी थी, इसलिए राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। जंगल में रहते हुए लुंभक फल-फूल खाकर जीवनयापन करने लगा।

एक बार, जब वह जंगल में था, तो अनजाने में ही सफला एकादशी के दिन उपवास कर लिया। वह रात में कुछ खाने की तलाश में था और जागता रहा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से उसका हृदय परिवर्तित हुआ और अंततः उसे राज्य तथा सम्मान, दोनों की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है।

अंतर्यात्रा
संकलित

व्रती उपवास रखते हैं, *विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ* तथा 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करते हैं। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत से दरिद्रता, दुख और पापों का नाश होता है तथा जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए इसे सफला अर्थात सफल करने वाली एकादशी कहा गया है।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 15 दिसंबर, 1952

ईरान अमेरिका से कोई आशा न करे: हुसैन मक्की

ईरान अमरीका से कोई आशा न करे, हुसैन मक्की का कथन

कबाइली क्षेत्र में पाकिस्ता[न] के विरुद्ध बगावत शुरू

ईरान के राजनेता और इतिहासकार हुसैन मक्की ने कहा कि अमेरिका से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'विश्वबैंक के अधिकारियों ने बताया कि जब तक ईरान ब्रिटेन से तेल समझौता नहीं करेगा, तब तक बैंक और अमेरिका कोई सहायता नहीं करेंगे।'

इस बदरंग कुसंस्कृति से मुक्ति कब

सार्वजनिक स्वच्छता की अनदेखी बीमारियों को बढ़ाती है। ज्यादातर बीमारियां इधर-उधर थूकने से ही फैलती हैं।

सुभाष चंद्र कुशवाहा | मुद्दा

भारत में पान-मसाला, गुटखा, खैनी और तंबाकू चबाना बहुत आम है। खासकर हिंदी प्रदेशों में सड़कों या सार्वजनिक स्थानों को थूककर बदरंग करने की कुसंस्कृति हर कहीं देखी जा सकती है। कार चलाते हुए या बस में सफर करते समय सड़कों पर थूकने की घटनाएं रोज देखने को मिलती हैं। पार्कों, कार्यालयों और स्टेशनों के कोनों को भी हम नहीं बख्शते। सार्वजनिक स्वच्छता की ऐसी अनदेखी बीमारियों को बढ़ाती है। टीबी जैसी बीमारी, जो अपने देश की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किए हुए है, मुख्यतः इधर-उधर थूकने से ही फैलती है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में लगभग 21.4 फीसदी वयस्क (15 वर्ष से ऊपर) धुआंरहित तंबाकू का उपयोग करते हैं, जिनमें 29.6 फीसदी पुरुष और 12.8 फीसदी महिलाएं शामिल हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि करोड़ों लोग नित्य पान-मसाला या गुटखा चबाते होंगे और इसका सीधा असर सार्वजनिक

थूक/कुल्ले के रूप में होता होगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से, धुआंरहित तंबाकू के कारण भारत में हर साल लगभग 13.5 लाख मौतें होती हैं। तंबाकू/एसएलटी के कारण होने वाले रोगों (मुख, गले, मुंह के कैंसर, मुंह-गर्दन की समस्याएं, सांस व हृदय आदि रोग) का सामाजिक व आर्थिक बोझ भारी है। साफ है कि सिर्फ निजी स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, सार्वजनिक स्वच्छता तथा सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी यह समस्या जटिल है।

थूक की लार संबंधित व्यक्ति के हाथों व जूतों से दूसरों तक फैल सकती है; सार्वजनिक स्थानों पर थूक, कुल्ला आदि संक्रमण (जैसे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस), खासकर बच्चों या बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तंबाकू/एसएलटी से होने वाली बीमारियों के इलाज में स्वास्थ्य-व्यय, अस्पतालों पर भार, रोजगार व आर्थिक उत्पादन में गिरावट आदि का भारी असर पड़ता है। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों की सफाई व रखरखाव का खर्च, जो नगर निगम, स्थानीय प्रशासन या सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ता है, बढ़ जाता है।

भारत में धुआंरहित तंबाकू के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूक, कुल्ला आदि पर नियंत्रण हेतु कुछ कानून बने भी हैं, जैसे 'सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रॉडक्ट्स एक्ट 2003' तंबाकू के सार्वजनिक-प्रचार, बेचने और कई प्रतिबंधों को तय करता है। इसके बावजूद, थूकना/कुल्ला करना बेरोक-टोक जारी है। कानून को प्रभावी बनाने के लिए आम जनता को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के साथ-साथ निगरानी व दंड को लागू करने का काम नहीं हुआ है। लखनऊ नगर निगम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस रूल्स, 2021 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार है, लेकिन इससे पहले जगह-जगह प्रचार-प्रसार की जरूरत है। मीडिया की खबरों के मुताबिक, न तो कोई जागरूकता फैलाई जा रही है और न जुर्माना वसूली हेतु कोई काम हुआ है। इस वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सार्वजनिक स्थानों पर पान/गुटखा चबाकर थूकने वालों पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है, मगर पान-गुटखा बनाने वाली कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा रहा है। हमें समाज में नागरिक जागरूकता तथा स्वच्छता की आदत बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारी से काम करना होगा। जो लोग पान-मसाला/गुटखा खाते हैं, उन्हें 'कुल्ला या थूकने के लिए' सिंगल-यूज ढक्कन वाले डस्टबिन/स्पिटबिन उपलब्ध कराने चाहिए।

सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ सफाई पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। स्थानीय प्रशासन, नगर निगमों को चाहिए कि वे जागरूकता और जुर्माना—दोनों के लिए सक्रिय हों। सीसीटीवी निगरानी टीम बढ़ाएं। सिर्फ थूकने पर नहीं, तंबाकू/एसएलटी उत्पादों के सेवन, बिक्री, विज्ञापन आदि पर भी कड़े प्रतिबंध हों। साथ ही, तंबाकू छोड़ने के लिए हेल्पलाइन, जागरूकता, स्वास्थ्य-शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएं।

पान-मसाला, गुटखा आदि खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना हमारे स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक सभ्यता और नागरिक शिष्टाचार पर एक गंभीर चोट है। हमारे सार्वजनिक पार्क, सड़कों, मंदिरों, ऑफिसों, स्टेशनों आदि की सफाई, सुंदरता और स्वास्थ्य-सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम नहीं बदलेंगे, जगह-जगह थूकते रहेंगे, तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, स्वच्छता, स्वास्थ्य व मुसाफिरों का अनुभव सब प्रभावित होगा।

बेहतर होगा कि हम जागरूक हों, सिविक सेंस दिखाएं और अपनी सार्वजनिक जगहों को स्वच्छ, सुरक्षित और गौरवपूर्ण बनाएं। सरकारों, प्रशासन और नागरिकों—हर स्तर पर सहयोग जरूरी है। तंबाकू/एसएलटी-संबंधित नीतियां, जागरूकता, कड़े जुर्माने और सार्वजनिक सुविधाएं—इनका संयोजन ही इस समस्या का स्थायी समाधान है।

अमर उजाला
नई दिल्ली । सोमवार । 15 दिसंबर 2025
amarujala.com

एजुकेशन & कॅरिअर

शांत मन ही एक बेहतर दिन की शुरुआत कर सकता है।

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

बिहार तकनीकी सेवा आयोग

जूनियर इंजीनियर के पदों पर उम्मीदवार करें आवेदन

2809 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 12 जनवरी, 2026
वेतनमान : रुपये 9,300 से लेकर रुपये 34,800 तक निर्धारित
यहां आवेदन करें : btsc.pariksha.nic.in

भारतीय वायु सेना में रिक्तियां ■ 340 पद

वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (एएफसीएटी)
आवेदन की अंतिम तिथि
19 दिसंबर, 2025
योग्यताएं
बारहवीं, स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
afcat.edcil.co.in

इंडिया ऑप्टेल में नौकरी के मौके ■ 149 पद

प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि
27 दिसंबर, 2025
योग्यताएं
न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 32 वर्ष
यहां आवेदन करें
ddpdoo.gov.in

डीआरडीओ सीईपीटीएएम ■ 764 पद

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट व टेक्नीशियन के पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 01 जनवरी, 2026
वेतनमान : रुपये 35,400 से लेकर रुपये 1,12,400 तक निर्धारित
यहां आवेदन करें : drdo.gov.in

बिहार विधान परिषद में रिक्तियां ■ 64 पद

डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर व अन्य पदों पर करें अप्लाई
आवेदन की अंतिम तिथि
26 दिसंबर, 2025
योग्यताएं
बारहवीं, स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
vidhanparishad.bihar.gov.in

दिल्ली छावनी बोर्ड में करें आवेदन ■ 25 पद

सीनियर रेजिडेंट, नेत्र-विशेषज्ञ व अन्य पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि
22 दिसंबर, 2025
पात्रताएं
एमडी, एमएस व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें
delhi.cantt.gov.in

यहां भी रोजगार की संभावनाएं ...

- सैनिक स्कूल, नालंदा : टीजीटी व मेस प्रबंधक के पद पर आवेदन आमंत्रित।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 26 दिसंबर, 2025
- sainikschoolnalanda.edu.in
- हिंदुस्तान/संभार सॉल्ट्स लिमिटेड, राजस्थान : सलाहकार का पद रिक्त।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 27 दिसंबर, 2025
- indiansalt.com

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

मतभेद स्वाभाविक हैं

कार्यस्थल पर अलग-अलग सोच का होना स्वाभाविक है। इन्हीं में सांगठनिक समस्याओं के समाधान के सूत्र छिपे होते हैं

मेगन गेरहार्ट
प्रोफेसर
मियामी यूनिवर्सिटी

कार्यस्थल में अलगाव या अकेलापन एक आम समस्या है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित हो सकता है। इसका एक असरदार तरीका है पीढ़ियों के बीच की दूरी को पाटना। जब अलग-अलग उम्र के लोग आपस में जुड़ते हैं, जैसे एक-दूसरे को मार्गदर्शन देना या साथ में प्रोजेक्ट पर काम करना, तो इसके कई फायदे होते हैं। सबसे पहले, इससे टीम में विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं, जो नए और बेहतर समाधान ढूंढने में मदद करते हैं। साथ ही, सहयोग और आपसी समझ बढ़ती है, जिससे कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अकेलापन कम महसूस होता है। इस तरह, पीढ़ियों के बीच सक्रिय जुड़ाव न केवल टीम की रचनात्मकता बढ़ाता है, बल्कि संगठन में अलगाव की समस्या से निपटने में भी मदद करता है।

■ सीखने का माहौल है बनता

कामकाजी माहौल में युवा और वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ काम करने से दोनों को फायदा होता है। युवा कर्मचारी डिजिटल कौशल और नए रुझानों की जानकारी देते हैं, जबकि वरिष्ठ कर्मचारी अनुभव और कॅरिअर मार्गदर्शन साझा करते हैं। इससे टीमवर्क बढ़ता है, सीखने का माहौल बनता है और सभी की क्षमताओं का बेहतर उपयोग होता है।

■ विशेष गतिविधियां शामिल करें

टीम और संगठन में अलग-अलग उम्र के लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियां बहुत उपयोगी होती हैं। टीम-बिल्डिंग, सामुदायिक प्रोजेक्ट्स या सामाजिक कार्यक्रम कर्मचारियों को साथ लाते हैं, जिससे वे एक-दूसरे को बेहतर समझते हैं और सहयोग बढ़ता है। ऐसे आयोजन पेशेवर संबंधों के साथ-साथ टीम में अपनापन और विश्वास भी मजबूत करते हैं, जिससे कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक बनता है।

■ खुला संवाद रखें

काम के माहौल में आत्म-जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। जब कर्मचारी अपने सोच, व्यवहार और नजरिये को समझते हैं, तो वे पूर्वाग्रहों को चुनौती देकर गलतफहमियां कम कर सकते हैं। साझा लक्ष्यों पर ध्यान देने से संवाद और सहयोग बेहतर होता है, सभी एक दिशा में काम करते हैं और टीम में विश्वास व सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित होती है, जो संगठन की सफलता में मदद करती है।

■ विविधता का विचार

टीम में विविधता शामिल करना बेहद फायदेमंद होता है। जब किसी प्रोजेक्ट टीम में अलग उम्र, पृष्ठभूमि और अनुभव वाले लोग साथ आते हैं, तो वे अपने अनोखे दृष्टिकोण और कौशल साझा करते हैं। इससे रचनात्मकता, नवाचार और बेहतर समाधान विकसित होते हैं। विविध टीमों में सीखने और सहयोग की भावना बढ़ती है, जिससे काम की गुणवत्ता और परियोजना के परिणाम और बेहतर बनते हैं।

-द कन्वर्सेशन

खुद को परखें

1. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) किस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है?
   (a) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
   (b) दूरसंचार विभाग
   (c) अंतरिक्ष विभाग
   (d) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
2. हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला शील्डटेल सांप किस क्षेत्र में पाया जाता है?
   (a) भारत और बांग्लादेश
   (b) भारत और श्रीलंका
   (c) नेपाल और भूटान
   (d) बांग्लादेश और म्यांमार
3. संपान पोर्टल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
   (a) वित्त मंत्रालय
   (b) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
   (c) संचार मंत्रालय
   (d) गृह मंत्रालय

उत्तर-1.c, 2.b, 3.c

ग्रीन क्लाइमेट फंड इंटर्नशिप-2026

इंटर्नशिप प्रोग्राम

ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) इंटर्नशिप-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह जलवायु परिवर्तन में रुचि रखने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अवसर है। इंटर्नशिप की अवधि छह महीने है। आवेदन के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम में नामांकित हो या हाल ही में ऐसे किसी कार्यक्रम से स्नातक हुआ हो। साथ ही, अंग्रेजी भाषा पर उत्कृष्ट पकड़ तथा एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक और एक्सेस जैसे मानक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उपयोग में दक्षता आवश्यक है। चयनित इंटर्न्स को 1,600 डॉलर का मासिक स्टाइपेंड व अन्य लाभ प्राप्त होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि पद के अनुसार 03 व 04 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक लिंक tinyurl.com/4j893vr2 पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इंटरनेशनल एक्सलिब्रिस कॉम्पिटिशन वार्ना-2026

आवेदन आमंत्रित

जॉर्डन पेटकोव आर्ट फाउंडेशन की ओर से इंटरनेशनल एक्सलिब्रिस कॉम्पिटिशन वार्ना-2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए दुनियाभर के कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

■ पात्रताएं

इस कॉम्पिटिशन में आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रत्येक प्रतिभागी अधिकतम पांच अलग-अलग छवियां भेज सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक की तीन हस्ताक्षरित प्रतियां होनी चाहिए। साथ ही, ये कृतियां 2024 से 2026 के बीच बनाई गई होनी चाहिए।

■ पुरस्कार

इस कॉम्पिटिशन के ग्रैंड प्राइज के लिए 1,000 यूरो, एक्सलिब्रिस प्राइज के लिए 600 यूरो, यंग आर्टिस्ट प्राइज के लिए 400 यूरो और दो अन्य विजेताओं को प्रत्येक 500 यूरो प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, विजेताओं को ऑनर सर्टिफिकेट, ऑनरेबल मेंशन और अन्य लाभ भी दिए जाएंगे।

■ यहां आवेदन करें

प्रतिभागी आधिकारिक लिंक tinyurl.com/4kt7pmys पर जाकर 01 जुलाई, 2026 तक इस कॉम्पिटिशन में भाग ले सकते हैं।

एग्जाम अलर्ट — हफ्ते की परीक्षाएं

दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा-2025

- **परीक्षा की तिथि :** 18 दिसंबर, 2025 से 06 जनवरी, 2026
- इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान/समसामयिक मामले, रीजनिंग, संख्यात्मक क्षमता और कंप्यूटर जागरूकता से 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे निर्धारित की गई है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** ssc.gov.in

बिहार एसएचएस नेत्र सहायक परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 20 दिसंबर, 2025
- इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, नॉलेज एप्लीकेशन/तर्क, संख्यात्मक क्षमता से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की कुल अवधि दो घंटे होगी।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** tinyurl.com/ym6w5874

सामान्य ज्ञान — सुपरनोवा

- **क्या है**
  सुपरनोवा एक विशाल तारे का शक्तिशाली विस्फोट है।
- **चर्चा में क्यों**
  गामा-किरण विस्फोट से खगोलविदों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के शुरुआती समय का एक दुर्लभ सुपरनोवा खोजा।
- **इनके बनने के दो तरीके हैं**
  एक तारा दो तरीकों से सुपरनोवा बन सकता है-पहला, तारा अपने पास वाले तारे से पदार्थ खींचता है और अनियंत्रित परमाणु प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और दूसरा, तारे का ईंधन खत्म हो जाता है और वह अपने गुरुत्वाकर्षण से ढह जाता है। सुपरनोवा में कुछ ही सेकंड में इतनी ऊर्जा निकलती है, जितनी हमारा सूर्य अरबों सालों में नहीं निकाल पाता।
- **यह कितने आम हैं?**
  सुपरनोवा अंतरिक्ष के सबसे बड़े विस्फोट हैं। ये इतने चमकीले होते हैं कि कुछ समय के लिए अपनी पूरी आकाशगंगा की सारी रोशनी से भी ज्यादा चमकते हैं। ये ब्रह्मांड में भारी तत्व बनाने का मुख्य स्रोत हैं। आकाशगंगा में हर सदी में दो से तीन सुपरनोवा होते हैं, और ब्रह्मांड में सैकड़ों सालाना देखे जा सकते हैं।

रोशनी यहां है

इस बार : द्वारकेश चंद्रशेखरन
क्यों : राष्ट्रीय विकलांगजन पुरस्कार (श्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी) प्राप्त किया

लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारकेश ने अनुशासन को जीवन, सेना को लक्ष्य और देश को धर्म बनाया। हादसे में आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन हौसला नहीं टूटा। एआई, खेल और शिक्षा के सहारे आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह साबित किया कि असली रोशनी इन्सान के भीतर होती है।

असली रोशनी इन्सान के भीतर होती है

आज से छत्तीस वर्ष पहले साल 1989 में तमिलनाडु में एक बालक ने जन्म लिया। समय के साथ उसकी सोच और लक्ष्य, दोनों स्पष्ट होते गए। वह लड़का धरती को केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि जीवन का आधार मानता था। जब उसने जाना कि तमिल भाषा में नाडु का अर्थ ही भूमि होता है, तब उसके भीतर अपनी मिट्टी के प्रति एक अनोखा प्रेम जाग उठा-एक ऐसा प्रेम, जिसने धीरे-धीरे देशभक्ति का रूप ले लिया। कॉलेज पहुंचा, तो उसकी नजरें केवल एक डिग्री पर नहीं थीं, बल्कि वह अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। जीवन में एकता और अनुशासन को आधार बनाकर उसने एनसीसी जॉइन की। वहीं से उसकी यात्रा ने दिशा पकड़ी। वर्ष 2009 में वह लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर अपने सपने के पहले पड़ाव पर पहुंचा। पर 2014 में एक दुर्घटना ने उसकी दोनों आंखों की रोशनी छीन ली। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी इसी दृढ़ता ने उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया, जिससे उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आज वह भारत के सशस्त्र बलों के पहले ऐसे अधिकारी हैं, जिन्होंने पूरी तरह से दृष्टिहीन होने के बावजूद सेना में अपनी सेवा जारी रखी। सिर्फ इतना ही नहीं, सैन्य सेवा के साथ वह पैरालंपिक खेलों में भी चमकते सितारे बन गए। उनकी अटूट इच्छाशक्ति और साहस को सम्मान देते हुए, हाल ही में उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारकेश चंद्रशेखरन। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय भी उनके असाधारण प्रदर्शन को सम्मानित कर चुका है। द्वारकेश चंद्रशेखरन हिम्मत और पक्के इरादों की मिसाल हैं, और उनकी शानदार यात्रा सभी, खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा है।

बचपन का ख्वाब

लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारकेश चंद्रशेखरन की शुरुआती यात्रा साहस, अनुशासन और बचपन से ही सेना में अधिकारी बनने के सपने से जुड़ी रही है। वे तमिलनाडु से हैं, लेकिन पढ़ाई और सेवा के दौरान पुणे से भी उनका गहरा जुड़ाव रहा। स्कूल के समय उन्होंने एनसीसी जॉइन की और 2004 में तमिलनाडु निदेशालय की ओर से 'बेस्ट एनसीसी कैडेट' चुने गए, जिससे उनके सैन्य कॅरिअर की मजबूत नींव पड़ी। इसके बाद टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत प्रशिक्षण लेकर उन्होंने 2009 में भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया और सैन्य खुफिया कोर में एक युवा, ऊर्जावान अधिकारी के रूप में सेवा शुरू की।

एक हादसे ने बदली जिंदगी

लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारकेश चंद्रशेखरन के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2014 में हुए एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। पुणे में हुए इस हादसे में उन्होंने अपनी दोनों आंखों की रोशनी गंवा दी। वह आठ महीनों तक अस्पताल में रहे। इस घटना में सेना के दूसरे जवान भी मारे गए। आमतौर पर अगर किसी जवान के साथ ऐसी कोई घटना होती है, तो सेना में कॅरिअर खत्म ही माना जाता है, लेकिन द्वारकेश ने लेफ्टिनेंट के पद पर सक्रिय रूप से सेवा जारी रखने का साहसी फैसला लिया। उन्होंने धीरे-धीरे और थोड़ा-थोड़ा करके अपनी जिंदगी को फिर से बुना।

सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई

दृष्टि खोने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई और खेल को अपनाकर जीवन को नई दिशा दी। 2018 में खड़की (किरकी) में तैनाती के दौरान उन्होंने पैरा-स्पोर्ट्स की शुरुआत की और पुणे में तैराकी व शूटिंग में भाग लेना शुरू किया। 2021 की राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में पहला पदक जीतने के बाद वे लगातार राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता रहे। वे तैराकी और निशानेबाजी दोनों में नेशनल चैंपियन हैं, पैरा शूटिंग में विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं और 10 मीटर एयर राइफल में विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। खेलों के साथ उन्होंने यूजीसी-नेट सहित कई परीक्षाएं पास कीं और सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की।

एआई बना गेमचेंजर

दृष्टि खोने के बाद द्वारकेश चंद्रशेखरन के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजमर्रा के काम, पढ़ाई और सैन्य जिम्मेदारियों को निभाने की थी। लेकिन उन्होंने तकनीक को बाधा नहीं, बल्कि सहायक बनाया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित जावा स्क्रीन रीडर, वॉयस कमांड सिस्टम, टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच-टू-टेक्स्ट टूल्स का इस्तेमाल सीखकर अपनी कार्यक्षमता को बनाए रखा। वह एआई की मदद से दस्तावेज पढ़ने-लिखने और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने लगे। यही नहीं, उन्होंने एआई-आधारित स्पोर्ट्स एनालिसिस और डाटा टूल्स का उपयोग करके पैरा शूटिंग और तैराकी में भी अपनी तकनीक को बेहतर किया। एआई ने उन्हें यह साबित कराया कि तकनीक सही हाथों में हो, तो वह किसी भी शारीरिक सीमा को पीछे छोड़ सकती है।

युवाओं को सीख

- परिस्थितियां आपको नहीं, आपका दृष्टिकोण आपको परिभाषित करता है।
- अंधकार तब तक ही ताकतवर होता है, जब तक इन्सान अपने भीतर के उजाले को पहचान नहीं लेता।
- शरीर की सीमाएं मंजिल तय नहीं करतीं, इरादों की मजबूती तय करती है कि इन्सान इतिहास रचेगा या बहाने।

आज का दिन

15 दिसंबर, 2008

मुंबई आतंकी हमले के बाद आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) के गठन का प्रस्ताव रखा था। आज के ही दिन प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी।

- **1907 :** ब्राजील के वास्तुकार ऑस्कर नीमेयर का जन्म हुआ था।
- **1997 :** जेनेट रोसेनबर्ग जगन गुयाना की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थीं।
- **2001 :** इटली की पीसा की झुकी मीनार को मरम्मत के बाद फिर से खोला गया था।
- **2011 :** अमेरिका ने इराक में युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी।

व्रत त्योहार

आज : पौष कृष्ण पक्ष एकादशी।
कल : हेमंत ऋतु, सूर्य दक्षिणायने, दक्षिण गोले।
राहुकाल : दिन में 15.00 से 16.30 तक।

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 25 मार्गशीर्ष मास शक 1947, पौष मास 02 प्रविष्टे, 24 जमादिउस्सानी हिजरी 1447, पौष कृष्ण पक्ष द्वादशी 23.57 तक उपरांत त्रयोदशी, स्वाती नक्षत्र 14.09 तक उपरांत विशाखा नक्षत्र, अतिगंड योग 13.22 तक उपरांत सुकर्मा योग, कौलव करण 10.38 तक उपरांत तैतिल करण, चंद्रमा तुला राशि में दिन रात।

■ सूर्योदय : 07.10
■ सूर्यास्त : 17.22
(भारतीय मानक समयानुसार)

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : स्वबुद्धि कौशल से किसी समस्या से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में कार्यालय की राजनीति से दूरी बनाए रखें।

वृष : आत्मबल बनाए रखें। नौकरी में सम्मान बना रहेगा। विरोधी पक्ष से सावधानी बरतें। व्यवसाय में धन लाभ होगा।

मिथुन : किसी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पूर्व निवेशित धन मिल सकता है। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी।

कर्क : सकारात्मक सोच बनाए रखें। बनते कार्यों में अवरोध आएंगे। नौकरी में कार्य भार बढ़ सकता है।

सिंह : दिनमान अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक यात्रा हो सकती है। अटका धन मिलेगा। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा।

कन्या : भाग्य सहायक रहेगा। अटकी योजना में गति आएगी। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें। विरोधी से सचेत रहें।

तुला : मानसिक उत्तेजना से बचें। सरकारी क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। नौकरी में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

वृश्चिक : अतिउत्साह से बचें। आर्थिक मामलों में सचेत रहें। अचानक व्यय हो सकता है। सेहत नरम रहेगी।

धनु : सामाजिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। अर्थ प्राप्ति संभव है। यात्रा से बचें।

मकर : नौकरी में सम्मान बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र में अटके कार्य पूर्ण होंगे। बॉन्ड, बीमा से अर्थ प्राप्ति संभव है।

कुंभ : मानसिक उथल-पुथल बनी रहेगी। नौकरी में कार्य भार बढ़ सकता है। अटका कार्य बनेगा।

मीन : व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। स्वजनों से मन-मुटाव रहेगा। नए कार्य में पूंजी निवेश से बचें।

जन्मदिन

आशिका भाटिया, अभिनेत्री

इस वर्ष आत्मबल प्रबल रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा को नया आकार मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आर्थिक दृष्टि से वर्ष महत्वपूर्ण है। जमीन-जायदाद में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। व्यवसायिक लाभ एवं विस्तार से उत्साहित रहेंगे। आरोग्य सुख अनुकूल रहेगा।

सुडोकू

			1	9		6	3	2
		1			4			
6	3		2				1	
							5	
1		2				3		6
	8							
	4				2		7	3
			4			8		
5	2	3		7	8			

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

4	5	8	1	9	7	6	3	2
2	9	1	6	3	4	5	8	7
6	3	7	2	8	5	4	1	9
9	6	4	3	2	1	7	5	8
1	7	2	8	5	9	3	4	6
3	8	5	7	4	6	2	9	1
8	4	6	5	1	2	9	7	3
7	1	9	4	6	3	8	2	5
5	2	3	9	7	8	1	6	4

डेली हेल्थ कैप्सूल

दूध में घी मिलाकर सेवन करने के फायदे

दूध में घी मिलाकर सेवन करने से शारीरिक सेहत के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है।

दूध में घी को मिलाकर पीने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ बेहतर बनता है। घी में मौजूद ब्यूटिरिक एसिड पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। गरम दूध पाचन एंजाइम्स को उत्तेजित करता है, जिससे खाना आसानी से पच जाता है। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। घी में मौजूद विटामिन के2 कैल्शियम

को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। इस दूध का नियमित सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम कम होता है। घी में मौजूद विटामिन ए, डी और ई शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। इससे बीमारियों से बचाव होता है। घी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है। यह याददाश्त और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही तनाव, चिंता और अवसाद भी कम करता है। साथ ही घी जोड़ों को चिकनाई देता है, जिससे गठिया और दर्द में आराम मिलता है। गर्भावस्था में यह दूध ऊर्जा देता है, भ्रूण के मस्तिष्क और हड्डियों के विकास में मदद करता है, पाचन सुधारता है, कब्ज से राहत दिलाता है और मां की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

भले ही घी शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देता है, लेकिन इसमें कैलोरी और फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह वजन या हृदय रोग जैसी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है।

-डॉ. नम्रता भट्ट
आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 15 दिसंबर 2025

यदि राष्ट्र को आगे बढ़ना है, तो नेतृत्व की जिम्मेदारी युवाओं को संभालनी होगी।

- ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

युवा हाथों में कमान

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार BJP संसदीय बोर्ड ने नितिन नबीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष से ऐसा लग सकता है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन जिस तरह से इस फैसले की घोषणा हुई और पार्टी के अंदर जिस बड़े पैमाने पर उसका स्वागत हुआ, उससे साफ है कि यह सुविचारित फैसला है। अगर कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने नहीं आया तो पार्टी के अंदर चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा।

नए BJP अध्यक्ष

सरप्राइज एलीमेंट । पार्टी के अंदर और बाहर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन नितिन नबीन की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। इस लिहाज से देखें तो पार्टी ने इस चयन से फिर चौंकाया है। हालांकि BJP में नितिन नबीन कम उम्र में ही परफॉर्मेंस की बदौलत नाम बना चुके हैं। पांच बार के विधायक नितिन बिहार में मंत्री की भूमिका के अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव समेत संगठन में अलग-अलग जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं।

नई पीढ़ी को जिम्मा । जिस पद के लिए BJP के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में रहे हों, उसके लिए नितिन नबीन जैसे युवा नेता का चयन बताता है कि पार्टी भविष्य को देखते हुए नया नेतृत्व तैयार कर रही है। इस लिहाज से पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में सीएम के चयन पर नजर डालें तो यह सोच और स्पष्ट होकर उभरती है।

संघ से सामंजस्य । BJP अध्यक्ष का पद ऐसा है, जिससे संघ के साथ सामंजस्य का सवाल अपने आप जुड़ जाता है। नए अध्यक्ष के चयन में हो रही देरी को लेकर भी चर्चा थी कि इसके पीछे संघ के साथ सहमति न बन पाना वजह है। लेकिन कुछ समय पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट किया था कि इससे संघ का कोई लेना-देना नहीं है।

आगामी चुनौतियां । नितिन ने भले ही अब तक प्रशासनिक और सांगठनिक कौशल का प्रदर्शन किया हो, लेकिन नई भूमिका में उनके सामने कई चुनौतियां हैं। बिहार चुनावों में BJP और उसके सहयोगियों को मिली शानदार जीत के बाद पश्चिम बंगाल समेत आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन दोहराने का दबाव और बढ़ गया है। नए अध्यक्ष इस कठिन चुनौती से गुजर कर ही इस फैसले की सार्थकता साबित कर पाएंगे।

नश्तर

एयरपोर्ट पर जिन्न

फ्लाइट कब जाएगी, जाएगी भी या नहीं... इसी ऊहापोह में एयरपोर्ट पर भटक रहा था कि पैर से कुछ टकराया। पुराना चिराग था। घिसने पर जिन्न निकला, 'बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं?' मैंने कहा, 'तुम जिन्न हो या कस्टमर केयर के कर्मचारी? पूछो, क्या हुक्म है मेरे आका?' वो बोला, 'इसी झंझट में तो फंसा हूं...उसने पूछा। मैंने कहा, 'उड़ने वाले कालीन से मुझे मुंबई छोड़ आओ।' वह बोला, 'कालीन किराए पर गया है।' 'क्यों?' जिन्न ने ऐसे निपटा दी, 'आपदा में अवसर।' मुझे तेज गुस्सा आया। एयरपोर्ट पर हम थोड़ी देर साथ बैठे रहे।

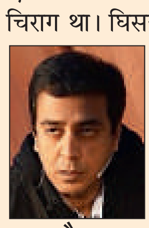

सौरभ श्रीवास्तव

मेरा गुस्सा कुछ शांत हुआ। जिन्न बोला, 'मैं तुम्हारे चिराग घिसने से नहीं निकला। मैं काफी समय से यहीं टहल रहा था। तुम्हें चिराग लिए देखा तो सामने आ गया। एयरपोर्ट पर लगातार अनाउंसमेंट सुनने के कारण मैं अपनी लाइन भूल गया था।' मैंने पूछा, 'चिराग से बाहर क्यों टहल रहे थे?' 'हमारी दुनिया में भी SIR चल रहा है। मेरा नाम गायब है। भगा दिया गया हूं।' मैंने कहा, जो मुद्दा में भौंवें उचकाई। जिन्न बोला, 'मैंने अपने यहां के सबसे बड़े नेता से पूछा था कि मैं वोट नहीं डाल सकता, पर हूं तो देश का नागरिक ही और नागरिक को वोट देने का अधिकार है। बड़े नेता ने कहा- तुम सवाल बहुत पूछते हो इसलिए निकल जाओ इस देश से। तब से मैं भटक रहा हूं। तुम लोगों के विमान नहीं उड़ रहे तो थोड़े पैसे भी कमा लिए, पर उसमें भी नुकसान ही हुआ।' मैंने पूछा, 'कैसे?' 'जादुई कालीन से कमाई रुपये में हुई, पर वह गिरता ही जा रहा है।' मुझे समझ आ गया। यह जिन्न घुमा-फिराकर हमारे हालात पर तंज कस रहा है। मन में आया कि जिन्न को वापस चिराग में बंद कर दूं। मैंने फिर चिराग घिसा। जिन्न ने हुक्म पूछा। मैंने कहा, 'अपने चिराग में वापस जाओ।' जिन्न ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, 'तुम ठहरे आम आदमी, तुम्हारी बात सरकारी बाबू नहीं सुनता तो मैं क्यों सुनूं?' तब से जिन्न बाहर है और लोग उसे वापस भेजने की कोशिश में जुटे हैं।

एकदा

संकलन : रिंकल शर्मा

संकल्प से सफलता

कैथरीन जॉनसन उन विरल व्यक्तित्वों में से थीं, जिनकी प्रतिभा ने न केवल विज्ञान की दिशा बदली, बल्कि सामाजिक पूर्वाग्रहों को भी चुनौती दी। 26 अगस्त 1918 को अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में जन्मी कैथरीन में बचपन से ही गणित की विलक्षण क्षमता थी। चार भाई-बहनों में सबसे छोटी कैथरीन पांचवीं कक्षा में ही हाईस्कूल स्तर के कठिन प्रश्न हल कर लेती थीं। ऐसे समय में, जब अश्वेत समुदाय के लिए उच्च शिक्षा लगभग सपना थी, उनके माता-पिता ने हर कठिनाई झेलते हुए उनकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने हाईस्कूल पूरा किया और आगे चलकर गणित व फ्रेंच में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1953 में कैथरीन को NACA में अवसर मिला, जो बाद में NASA बना। वहां उन्हें नस्लीय और लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ा- अलग शौचालय, अलग कॉफी पॉट और अहम बैठकों से दूरी। लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया। 1962 में अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन का यह कथन कि 'जब तक कैथरीन गणनाएं जांच नहीं लेतीं, मैं उड़ान नहीं भरूंगा', उनकी विश्वसनीयता का प्रमाण था। कैथरीन जॉनसन का जीवन बताता है कि आत्मविश्वास, ज्ञान और दृढ़ संकल्प से इतिहास रचा जा सकता है।

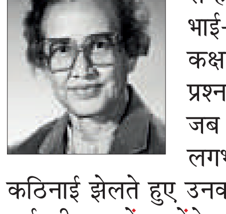

वायु प्रदूषण बस हवा से जुड़ी समस्या नहीं, सरकारी और सार्वजनिक जवाबदेही भी

मुंबई का भी हो रहा दिल्ली वाला हाल

दिल्ली-NCR में शनिवार को कई जगह AQI 450 के ऊपर चला गया, तो सीजन में पहली बार GRAP-4 लागू करना पड़ा। राजधानी के लिए बीता माह भी प्रदूषण के लिहाज से बेहद चिंताजनक रहा था। नवंबर के 24 दिनों में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 300 के ऊपर रहा यानी बहुत खराब और 3 दिन तो यह 400 के ऊपर चला गया मतलब गंभीर। दिल्ली-NCR के साथ-साथ इस बार चिंता मुंबई ने भी बढ़ाई है। नवंबर के मुकाबले अभी हालात भले कुछ सुधरे लग रहे हों, पर AQI कई जगहों पर 150 के आसपास है यानी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह।

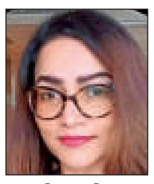

प्रतिमा सिंह

कमजोर सुरक्षा । मुंबई की समुद्री और तटीय हवा ने लंबे समय तक शहर के आसमान को साफ बनाए रखने में मदद की, लेकिन अब यह प्राकृतिक सुरक्षा धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में मुंबई में धूल और सूक्ष्म कणों से होने वाला प्रदूषण बढ़ा है। कई बार AQI 'खराब' स्तर तक पहुंच रहा है। अब यह मानना सही नहीं रह गया कि उत्तर भारत के शहरों की तुलना में मुंबई वायु प्रदूषण से सुरक्षित है। अगर समय रहते ठोस नीतियों और सख्त प्रशासनिक कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और खराब हो सकती है।

प्रदूषण के कारण । मुंबई की हवा खराब होने के तीन बड़े कारण हैं- वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण व तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल। शहर में गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, ट्रैफिक जाम आम हो गया है और सार्वजनिक परिवहन की लास्ट-माइल कनेक्टिविटी कमजोर है। इसके अलावा नवी मुंबई और तलोजा जैसे इलाकों में छोटे और मध्यम उद्योग भी हवा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहां अब भी पुरानी तकनीक और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों का इस्तेमाल होता है।

Adobe Stock

नियमों में सख्ती हो

- दिल्ली-NCR की तरह मुंबई में भी बिगड़े हालात
- मजबूत अथॉरिटी या टास्क फोर्स की जरूरत
- कानूनी जवाबदेही हो, नियम कठोर बनाए जाएं

निर्माण की कीमत । मुंबई के लिए सबसे गंभीर लेकिन कम समझा गया खतरा धूल प्रदूषण है, जो बड़े निर्माण और पुनर्विकास कार्यों से पैदा हो रहा है। मेट्रो, कोस्टल रोड, ट्रांस-हार्बर लिंक और अन्य बड़ी परियोजनाओं के कारण शहर में लगातार खुदाई और निर्माण चल रहा है। धूल नियंत्रण के ठोस इंतजाम न होने से PM10 स्तर तेजी से बढ़ रहा है और आसपास के इलाके प्रदूषण के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं।

तालमेल की जरूरत । सर्दियों में हालात और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वाला प्रदूषण भी इसमें जुड़ जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में पराली जलाने से उठने वाला धुआं और धूल जब हवा के साथ मुंबई पहुंचते हैं, तो हालात बदतर हो जाते हैं। राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और साझा एयरशेड प्रबंधन नहीं हुआ, तो यह मौसमी समस्या और गंभीर होगी। धूल प्रदूषण रोकने के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र की नगर पालिकाओं ने सड़क सफाई, पानी का छिड़काव, एंटी-स्मॉग गन और निर्माण सामग्री को ढक कर ले जाने जैसे कदम शुरू किए हैं। इनका पालन अक्सर ढंग से नहीं हो पाता।

सख्त नीति । मुंबई को तुरंत एक सख्त धूल नियंत्रण नीति की जरूरत है, जिसे सिटी बाइलॉज में शामिल किया जाए और इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। इसके लिए नगर निगम, परिवहन, PWD, पुलिस और अन्य विभागों को मिलकर काम करना होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत समिति मौजूद है, पर समर्पित धूल न्यूनीकरण सेल को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

जवाबदेही का मुद्दा । वायु प्रदूषण केवल हवा से जुड़ी समस्या नहीं है, यह शासन और सार्वजनिक जवाबदेही का मुद्दा है। मुंबई को एक ऐसी मजबूत अथॉरिटी या टास्क फोर्स की जरूरत है, जो सभी विभागों को एक साथ जोड़कर काम करे। इसमें राज्य सरकार, नगर निगम, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और नागरिक समूह शामिल हों।

विकास बनाम सेहत । दंड कठोर किए जाएं और AQI खराब होते ही निर्माण कार्य पर रोक, कचरा व पत्तियां जलाने पर प्रतिबंध और उद्योगों की कड़ी निगरानी जैसे नियम सख्ती से लागू हों। सवाल विकास बनाम साफ हवा का नहीं, बल्कि ऐसे विकास का है जो लोगों की सेहत को नुकसान न पहुंचाए। सही योजना, कड़ाई से अमल और तकनीक से जल्दी सुधार संभव है। साफ हवा का मतलब है स्वस्थ लोग, इलाज का कम खर्च और रहने के लिए बेहतर शहर।

(लेखिका iFOREST में एयर पल्यूशन की डायरेक्टर हैं)

नई दुनिया का रास्ता दिखाता QR कोड

भारत में हर दिन करोड़ों लोग अपने फोन से एक छोटे से कोड को स्कैन करते हैं और पलभर में उनकी दुनिया बदल जाती है। जैसे असली दुनिया पीछे छूट जाए और स्क्रीन पर सब कुछ उनके सामने खुल जाए। QR कोड उन तकनीक में से एक है, जिसने दबे पांव हमारे जीवन में एंट्री मारी और फिर उसे हमेशा के लिए बदल दिया। आज यह सभी जगह है - मेन्यू कार्ड पर, दुकान के काउंटर पर, किसी पुरानी दीवार पर। अब यह कोड नहीं, जीने का तरीका है।

दिखने में QR कोड थोड़ा डराने वाला लगता है - मानो किसी एलियन प्रजाति ने कोई पजल छोड़ा हो हमारे लिए। यह जियोमेट्री में बात करता है, लेकिन हम इसे समझ नहीं सकते। यह एक रहस्य की तरह है, जो कहता है कि तुम मुझे पढ़ नहीं सकते, पर इस्तेमाल कर सकते हो। रोचक बात है कि QR कोड का मकसद इंसानों से संवाद करना है भी नहीं, इसे तो मशीनों से बात करनी है और उसमें यह परफेक्ट है।

QR कोड का रहस्य इसे इस्तेमाल करते ही गायब हो जाता है। जैसे ही हम अपना फोन इसके सामने रखते हैं, जटिलता खत्म हो जाती है। कोड बदल जाता है किसी मेन्यू, फॉर्म, वॉलेट या किसी विंडो में। भारत में QR कोड को अपनाना काफी रोचक है। आखिरकार यह देश ऐसी सभ्यता का है, जिसने हमेशा प्रतीकों का इस्तेमाल किया। स्वास्तिक, रंगोली, तोरण - ये महज सजावट तो नहीं। QR कोड अब इसी परिवार का नया सदस्य है।

AI Image

जीवन आनंद

संतोष देसाई

कोड ने सिर्फ पेमेंट आसान करने से कहीं ज्यादा काम किया है। इसने हर जगह को एक तरह का दरवाजा बना दिया है और स्थिर चीजों में जान डाल दी है। यात्रा का मतलब बदल गया है। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, चीजें खुद पास आती हैं। जिस तरह से हाइपरलिंक ने टेक्स्ट को पोर्टल बना दिया, वैसे ही QR कोड ने असली दुनिया को पोर्टल बना दिया है।

यहीं से शुरू होता है सच्चा बदलाव। बरसों हम इस हकीकत के साथ जिए कि दो दुनिया हैं। एक को हम छू सकते हैं। दूसरी दुनिया अमूर्त है, पर तेज। डिजिटल वर्ल्ड हमारे लिए कोई और ही लोक था, जिसमें स्क्रीन के जरिये दाखिल हुआ जा सकता था। लेकिन, QR कोड ने दोनों दुनिया का अंतर मिटा दिया। यह हमें कहीं जाने के लिए नहीं कहता, बल्कि डिजिटल दुनिया को हमारे सामने ला खड़ा करता है।

QR कोड ने सारे फर्क मिटा दिए हैं। अब कोई लग्जरी स्टोर हो या छोटी-सी गुमटी - सब एक ही डिजिटल इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नॉलजी अब स्टेटस की पहचान नहीं, रोजमर्रा की चीज हो चुकी है। लेकिन, QR कोड की ताकत का प्रतीकात्मक महत्व भी है। हम जिसे समझ नहीं पाते, उस पर भी भरोसा कर रहे हैं। और यह सीख भी है इसमें कि बहुत खास चीजें साधारण में भी समा सकती हैं।

कांटे की बात

हनुका फेस्टिवल के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों को सिडनी के बोंडी बीच पर निशाना बनाया गया। ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों पर किया गया यह हमला हरेक ऑस्ट्रेलियाई पर हमला है। यह टेररिस्ट अटैक है।

एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री

डेटा WINDOW

और भी ख़तरनाक होने वाला है अमर प्लास्टिक

प्लास्टिक अमर है, क्योंकि वातावरण में इसके टूटने की गति बहुत धीमी है। यह टूटकर भी खत्म नहीं होता, माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है। इसे लेकर ICF इंटरनैशनल और प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट की नई स्टडी और डराने वाली है।

- **280** मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा हर साल निकलेगा 2040 तक।
- **58%** बढ़ोत्तरी की आशंका है ग्रीन हाउस गैसों में प्लास्टिक की वजह से।
- **75%** स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ेंगी, जो गंदगी की वजह से फैलती हैं।
- **8.3** अरब टन प्लास्टिक अभी तक दुनिया में बन चुका है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में यह नंबर 3 पर है।

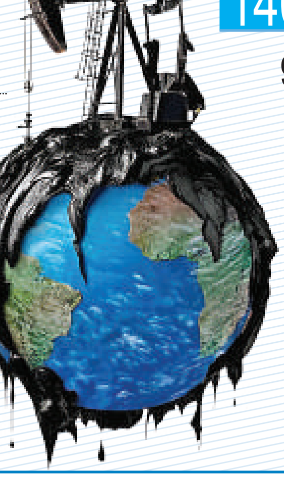

140 अरब डॉलर हर साल चाहिए होंगे इसके कलेक्शन-डिस्पोजल के लिए।

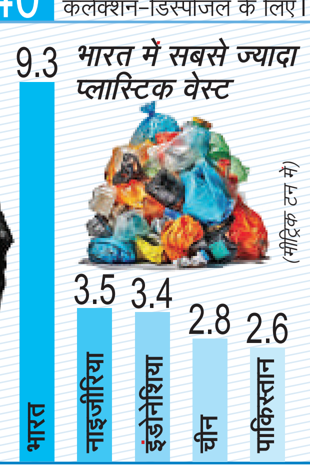

20% लगभग प्लास्टिक कचरा कलेक्ट नहीं हो पाता भारत में।

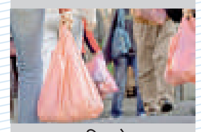

11 किलो प्लास्टिक औसतन हर साल एक भारतीय इस्तेमाल करता है।

टेक्सटाइल सेक्टर को मिले कई नए बाज़ार

भारत का टेक्सटाइल सेक्टर केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आजीविका, परंपरा और तकनीकी प्रगति की धड़कन है। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के टेक्सटाइल सेक्टर ने जिस व्यापक दृष्टि, दृढ़ नीतिगत संकल्प और दूरगामी सुधारों को देखा है, उसने इस क्षेत्र को नए आत्मविश्वास, नए अवसर और वैश्विक पहचान दी है।

गिरिराज सिंह

किसान-केंद्रित परिवर्तन । टेक्सटाइल वैल्यू-चेन की शुरुआत खेत से होती है, इसलिए, सरकार ने सबसे पहले किसानों को बाजार की अनिश्चितता, बिचौलियों के दबाव और दामों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित करने पर फोकस किया। परिणाम यह हुआ कि 2004-2014 के बीच जहां सरकारी एजेंसियों ने कुल 173 लाख कॉटन बेल्स की खरीद की थी, वहीं 2014-2024 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 473 लाख बेल्स पर पहुंच गया। यानी लगभग 173% की अभूतपूर्व वृद्धि। कपास के MSP में बढ़ोतरी ने किसानों की आमदनी और सुरक्षा दोनों को मजबूत किया है। 2013-14 में जहां कॉटन का MSP 3,700 रुपये प्रति क्विंटल था, वहीं 2025-26 में इसे बढ़ाकर 7,710 रुपये किया गया है।

क्वॉलिटी और न्यू-एज फाइबर । भारत केवल उत्पादन बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं बढ़ सकता। उच्च गुणवत्ता और आधुनिक फाइबर टेक्नॉलजी अनिवार्य है। इसी सोच से सरकार ने 2,500 करोड़ का मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिविटी शुरू किया। इसमें बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती, आधुनिक तकनीक और गुणवत्ता नियंत्रण मजबूत हो रहा है। साथ ही फ्लैक्स, रैमी, सिसल और मिल्कवीड जैसे न्यू ऐज फाइबर को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये अधिक आमदनी के अवसर देते हैं।

इंपोर्ट ड्यूटी में राहत । कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से मिल्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दामों पर कॉटन मिलने लगा। पहले यह राहत 30 सितंबर तक थी, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इसे 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया। इससे यार्न और फैब्रिक की उत्पादन लागत कम हुई, छोटे उद्योगों (SMEs) को स्थिरता मिली और रॉ कॉटन की बेहतर उपलब्धता से हैंडलूम-पावरलूम तक पूरी सप्लाई चेन को राहत मिली।

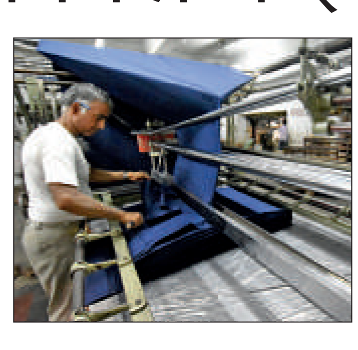

PLI योजना । PLI योजना ने टेक्सटाइल सेक्टर में नई ऊर्जा भरी है। आवेदन पोर्टल को अब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है, और अब तक 27 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे नई फैक्ट्रियां, नई टेक्नॉलजी और लाखों रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। 74 स्वीकृत कंपनियों में से 42 टेक्निकल टेक्सटाइल्स में काम कर रहे हैं।

जीएसटी में कमी । टेक्सटाइल इंडस्ट्री लंबे समय से इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या से जूझ रही थी। Next Gen GST सुधारों ने इस समस्या को दूर कर दिया है। साथ ही 2,500 तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर GST 5% किए जाने से आम जनता को सस्ते कपड़े मिलेंगे और छोटे शहरों-गांवों में भी मांग बढ़ेगी।

नए बाजारों की पहचान । नई रणनीति के तहत देश के 40 नए बाजार पहचाने गए, जहां भारत की मौजूदगी कम थी लेकिन संभावनाएं विशाल थीं। आज भारत 27 देशों के साथ FTA के जरिए नए बाज़ारों में मजबूत प्रवेश कर चुका है। सिर्फ एक साल में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 111 देशों में बढ़े, जिनमें से 38 देशों में 50% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

टेक्सटाइल का नया हब । भारत का टेक्सटाइल सेक्टर अब उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि देश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक नेतृत्व की नींव बन चुका है। भारत को ऐसे टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है जो आधुनिक, भरोसेमंद, नवाचार-प्रधान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप है। आने वाले वर्षों में यह सेक्टर न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि दुनिया को भी Made in India की नई पहचान देगा।

(लेखक केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं)

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

चंचल है मन, इस पर लगाइए चेतन सत्ता की लगाम

आशुतोष महाराज जी

जीवन में सलाह-मशवरा निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन असली समस्या तब सामने आती है जब इन्हें व्यवहार में उतारने की बारी आती है। हमें बार-बार बताया जाता है कि क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं, कैसा व्यवहार उचित है और किससे बचना चाहिए। नियम, सूत्र और निर्देश सहज रूप से उपलब्ध हो जाते हैं, पर वे धीरे-धीरे भी हमारी व्यक्तित्व का अंग नहीं बन पाते। इसी कारण वास्तविक परिवर्तन दूर की चीज लगने लगता है।

इसका मूल कारण मन की स्वाभाविक फितरत है। मन को जिस विचार से रोका जाता है, वह उसी ओर अधिक आकर्षित होने लगता है। सिग्मंड फ्रायड के एक प्रचलित प्रसंग के अनुसार, एक रात उनका बेटा देर तक घर नहीं लौटा। फ्रायड ने पड़ोसियों और मित्रों के घर खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने पत्नी से पूछा, 'क्या आज उसे कहीं जाने से मना किया था?' पत्नी ने उत्तर दिया, 'हां, उसे एक खास जगह जाने से रोका था।' फ्रायड ने तुरंत कहा, 'वह वहीं मिलेगा।' और सचमुच, बेटा उसी स्थान पर मिला। मन अपने ही स्तर से स्वयं को नहीं बदल सकता। परिवर्तन के लिए भीतर एक ऐसी चेतन सत्ता की आवश्यकता होती है, जो मन से अलग, अधिक सूक्ष्म और अधिक शक्तिशाली हो।

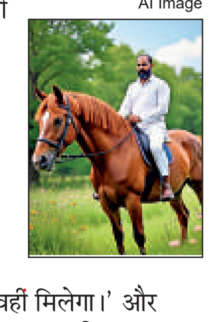

AI Image

इसी संदर्भ में गीता में श्रीकृष्ण, अर्जुन के सामने आत्मा का रहस्य बताते हैं, 'इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से भी परे आत्मा है।' वह अर्जुन से कहते हैं कि उस श्रेष्ठ और बलवान आत्मा को जानकर आत्मज्ञान से मनोविकार रूपी दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त करो। श्रीकृष्ण ने इसे केवल सिद्धांत के रूप में नहीं रखा, बल्कि अर्जुन को आत्मदर्शन कराया।

आज के समय में भी समाधान यही है- मन को आत्म-प्रकाश दिया जाए। जब मन आत्मा के प्रकाश में स्नान करता है, तभी उसके भीतर छिपे भय, विकार और पीड़ाएं वास्तव में समाप्त हो जाते हैं।

जनता जंक्शन

इरफ़ान

www.edit.nbt.in

कानून का दुरुपयोग न हो

यह पत्र 12 दिसंबर के संपादकीय 'दुरुपयोग का डर' से संबंधित है। कर्नाटक विधानसभा में लाया गया हेट स्पीच और हेट क्राइम बिल वास्तव में एक बहुत अच्छा कदम है और इसकी जरूरत भी महसूस की जा रही थी। लेकिन देश का राजनीतिक वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। देश की दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और BJP एक-दूसरे को दुश्मन की तरह देखती हैं। फिर भी, अगर नीति और नीयत ठीक हो, तो यह कदम स्वागत योग्य है। चूंकि यह हाल पूरे देश में है, इसलिए ऐसा कानून भी पूरे देश में होना चाहिए। हां यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई सरकार इसका दुरुपयोग न करे।

इन्द्र सिंह धिगान, किंग्सवे कैंप

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

वर्तमानातील प्रश्नांचे काय?

'इतिहासाचे विकृतीकरण, भविष्याविषयी तुच्छता' हा 'समोरच्या बाकावरून'मधील पी. चिदम्बरम यांचा लेख (१४ डिसेंबर) वाचला. पंतप्रधान मोदींनी 'वंदे मातरम्'वरील चर्चेला सुरुवात करून या गीतातील कडवी कशी वगळली गेली आणि नेहरू त्यास कसे जबाबदार होते तसेच त्यामुळेच देशाची फाळणी झाली या गोष्टी सांगितल्या तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांचीच री ओढली परंतु विरोधी पक्षाने, काँग्रेसने ही इतिहासाची मोडतोड योग्य पद्धतीने मोडून काढली. 'वंदे मातरम्'ची कडवी वगळण्याचा निर्णय नेहरूंनी एकट्याने नाही तर काँग्रेस कार्यकारिणीने घेतला होता ही गोष्ट काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पुराव्यासह स्पष्ट केले. आपल्या राज्याचे राज्यगीत म्हणून 'जय जय महाराष्ट्र माझा' हे गीत ठरवले गेले आहे आणि प्रत्येक सरकारी समारंभात हे गीत वाजवण्यात यावे असा सरकारी आदेश आहे परंतु त्या गीताचीदेखील काही कडवी वगळण्यात आलेली आहेत ही गोष्ट सत्ताधारी भाजप आणि मंत्रीगण विसरून गेले? पुढे मागे यावर विधानसभेत चर्चा घडली तर त्या वेळी सत्ताधारी भाजप काय उत्तर देणार?

याच वेळी इंडिगो कंपनीची उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना झालेला त्रास, दिल्लीतील आणि देशातील इतर शहरांमधील भयानक प्रदूषण, गोव्यात समुद्राच्या काठी हॉटेलला लागलेली भयानक आग आणि हॉटेलच्या मालकांचे इंडिगोच्याच विमानाने पळून जाणे, महागाई, बेरोजगारी असे महत्त्वाचे विषय असताना, इतिहासातील गीतावर चर्चा कितपत महत्त्वाची होती हा खरा प्रश्न आहे.

■ **शुभदा गोवर्धन,** ठाणे

सरकारचा अंकुश हवाच

सरकारी नियम हे दुर्लक्षित करण्यासाठीच असतात असं नेहमीच गृहीत धरणाऱ्या इंडिगोचे काय झाले हे जगाने बघितले. हवाई वाहतूक क्षेत्राचा जवळजवळ ६५ टक्के हिस्सा असल्यामुळे इंडिगोच्या या मनमानी वृत्तीमुळे बारा लाखांपेक्षा जास्त प्रवाशांना सुमारे १६०० फ्लाइट्स रद्द झाल्यामुळे कमालीचा मनस्ताप, आर्थिक भुर्दंड आणि गैरसोयीचा त्रास सहन करावा लागला. भारतीय नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र नियामक संस्थेच्या (ऊ्रउअ) नवीन नियमावली २०२४ (ाउ्ळछ) प्रमाणे आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची तत्परता न दाखविल्यामुळे आणि मक्तेदारीची हवा डोक्यात शिरल्यामुळे सरकारला वेठीस धरण्याचे दुःसाहस करून इंडिगोने ही परिस्थिती ओढवून घेतली आहे.

फेब्रुवारी, २०२६ पर्यंत FDTL साठी स्थगिती मिळालेल्या इंडिगोच्या या मनमानी वृत्तीला वेसण घालण्यासाठी कठोर शासन हे झालेच पाहिजे. इंडिगोच्या या सावळ्या गोंधळात मात्र एअर इंडिया, आकसा एअर, स्पाइसजेट यांची उड्डाणं मात्र व्यवस्थित सुरू होती. कारण नियमावलीप्रमाणे त्यांनी विमाने, पायलट, इतर कर्मचारी संख्या, वाढणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येच्या तुलनेत, वाढवली. या घटनेतून बोध घेत सरकारने तिकीट दरामध्ये केलेली अवास्तव वाढ वेळीच रोखण्याची तत्परता दाखविणे गरजेचे आहे. माफक दरात लोकांना सुविधायुक्त आणि सुरक्षित प्रवास घडेल याची जबाबदारी सर्व विमान कंपन्यांवर टाकावी आणि खासगीकरण झाले तरी सरकारचा अंकुश कायम राहील अशी व्यवस्था करावी!

■ **हेमंतकुमार मेस्त्री,** मनोर

आक्षेप आहे तो असंवेदनशीलतेवर

इंडिगो विमानसेवेचे वेळापत्रक बिघडल्यामुळे देशभरातील प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर काही राजकीय नेत्यांचा चार्टर्ड विमानाने प्रवास करतानाचा फोटो समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आणि त्यावरून प्रतिक्रिया उमटल्या. खासगी विमानांचा वापर ही कोणत्याही एका पक्षापुरती बाब नाही. वेळेचे बंधन, सुरक्षितता आणि कामाचे स्वरूप पाहता सर्वपक्षीय नेते असा प्रवास करतात, हे वास्तव आहे. त्यामुळे केवळ प्रवासाच्या प्रकारावरून टीका करणे उचित ठरणार नाही. मात्र ज्या वेळी सार्वजनिक व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे हजारो प्रवासी अडचणीत सापडले होते, त्या वेळी अशा प्रवासाचे फोटो समाजमाध्यमांवर प्रसारित होणे टाळता आले असते. प्रवासावर नव्हे, तर त्या क्षणी नेत्यांनी दाखवलेल्या असंवेदनशीलतेवर आक्षेप घेतला जात आहे. सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्यांनी परिस्थितीचा विचार करणे अपेक्षित आहे.

■ **दीपक काशिराम गुंडये,** वरळी

नाव बदलण्यात केवळ असूया...

'नाव बदलण्यात मोदी सरकार पटाईत' हे वृत्त वाचले (लोकसत्ता १४ डिसेंबर). महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) नाव बदलून, योजनेचे नाव 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' असे केल्याचे समोर आले आहे. कोणतेही सबळ कारण नसताना केवळ असूया आणि काँग्रेस द्वेषापोटी केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारने लोकाभिमुख, प्रसिद्ध आणि प्रचलित नावे बदलण्याचा जणू सपाटाच लावला आहे! महात्मा गांधींना 'महात्मा गांधी' या नावानेच जग ओळखते! 'पूज्य बापूजी' हे नाव नसून राष्ट्रपित्याचे देशवासीयांचे आदरार्थी संबोधन आहे, याची संबंधितांना जाण असावी! गांधी, नेहरू, काँग्रेस या नावांमुळे भाजपला जळजळ आणि मळमळ का व्हावी?

■ **श्रीकांत जाधव,** अतीत, सातारा

ज्येष्ठ म्हणजे 'मुकी बिचारी'...

केंद्र सरकारने मेडिक्लेमवर जीएसटी वेव्हड ऑफ केल्याचे फार गाजावाजा केला. पण त्यांच्या बहुतांश योजनांप्रमाणे हीपण एक अर्धवट माहिती आहे. केंद्र सरकारने हे सांगितले नाही की बँक मार्फत जर मेडिक्लेम ग्रुप बुकिंगमध्ये असेल, तर त्यावर जीएसटी वेव्हड ऑफ नाही. आणि आता बँकांनी ग्रुप इन्शुरन्स देणे बंद केले आहे. म्हणजे आमची डिस्काउंटेड पॉलिसी आता रिटेल झाली.

माझ्या एका कंपनीच्या ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीचा सात लाखांचा प्रीमियम २७,७८३ (प्रीमियम २३,५४५ जीएसटी ४,३३८) होता, तो या वर्षी रिटेलमध्ये गेल्यावर जीएसटीशिवाय अंदाजे ४३,५०० झाला आहे. ही आहे 'जीएसटी वेव्हड ऑफ' ची गंमत.

सरकारच्या 'आयुष्मान कार्ड'ला सरकारी हॉस्पिटलमध्येसुद्धा हिंग लावून कोणी विचारत नाही. मग खासगी हॉस्पिटलला विचारायलाच नको. आणि आता हे मेडिक्लेमचे ग्रुप कॅन्सलेशन. बँका नाही म्हणाल्या तर सरकार त्यांना ही योजना राबविण्याची सक्ती करू शकत नाही? सरकार बँकांना उद्योगपतींची अब्जोंची कर्जे माफ करायला भाग पाडते, तर या बाबतीत काही का करू शकत नाही? सरकारने वरिष्ठ नागरिकांना जगू द्यायचे नाही, असं ठरवले आहे का? रेल्वेची सवलत काढून घेतली. (मंत्र्यांना 'हेलिकॉप्टर्स, जेट'साठी मात्र सरकारकडे पैसे आहेत). ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे 'मुकी बिचारी' झाली आहेत.

■ **आशा पाटील,** पाचपाखाडी, ठाणे

उपमुख्यमंत्र्यांच्या रेवड्या

नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री व नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईबाबत जाहीर केलेल्या विविध योजना व सवलतींच्या खैराती या महापालिकेच्या निवडणुका जिंकण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या आहेत हे उघड आहे. त्यांच्या कल्पनेतील 'हौसिंग स्टॉक' निर्माण झालाच तर गरजू राहतील बाजूला, पक्षाचे मंत्री, खासदार व आमदार त्या घरांवर प्रथम डल्ला मारतील अशी परिस्थिती आहे. 'सर्वांसाठी घरे', 'मुंबईबाहेर फेकल्या गेलेल्या मराठी माणसांना परत आणू' इत्यादी घोषणा या निव्वळ निवडणूक जुमला आहेत. वाढत्या पुनर्विकास प्रकल्पांबरोबर रस्ता रुंदीकरण, पाणी, मलनिस्सारण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इत्यादी पायाभूत सुविधा कशा पुरवणार याचा विचार नाही. एकंदरीत या योजना व सवलती म्हणजे एकनाथ शिंदेंच्या रेवड्या आहेत.

■ **बकुल बोरकर,** विलेपार्ले, मुंबई

लग्नसंस्था अधिक बळकट व्हावी

'निसटता स्वर्गातल्या गाठी' (१३ डिसेंबर) हा संपादकीय लेख वाचला. लग्नबंधनातून परंपरेच्या नावाखाली सहनशीलतेचं ओझं भारतीय स्त्रीच्या खांद्यावर टाकलं जातं. लग्नानंतर जुळवून घे हा मुलींना दिला जाणारा सल्ला अनेकदा मुलींना अन्याय सहन करत राहण्यास कारणीभूत ठरतो हे वास्तव नाकारता येण्यासारखं नसलं तरी हल्ली शहरात राहणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या उच्चवर्गातल्या काही मुलींचा 'लिव्ह इन'मध्ये राहण्याकडे वाढलेला कल हा आधार, सुरक्षितता आणि भावनिक स्थैर्य देणाऱ्या भारतीय लग्नसंस्थेला सरसकट योग्य पर्याय असू शकणार नाही. लग्नसंस्थेत काही दोष नक्कीच आहेत हे मान्य करत ते सुधारण्यासाठी योग्य पावले उचलून, समाजस्वास्थ्य टिकवून ठेवणारी भारतीय लग्नसंस्था भविष्यात अधिक बळकट करायला हवी.

■ **आशीष थळे,** अलिबाग (थळेपाडा)

जिहाद नव्हे, लोकशाही हाच पर्याय!

अलीकडेच भोपाळ येथे जमियत ए उलमा ए हिंदच्या बैठकीत मौलाना महमूद मदनी यांनी मुस्लिमांवरील अत्याचार, सरकारी पक्षपात आणि न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर टीका करताना 'जिहाद'ची दिलेली हाक नव्या प्रश्नांना जन्म देणारी ठरते. लोकशाही आणि संविधानाचा मार्ग उपलब्ध असताना धर्माची वाट चोखाळण्याचा विचार कशाला?

हुमायून मुरसल
सामाजिक कार्यकर्ते
humayunmursal@gmail. com

मौलाना महमूद मदनी यांनी भोपाळ येथे 'जमियत ए उलमा ए हिंद'च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये बोलताना, दहशतवाद, निरपराध मुस्लीम तरुणांना होणारा तुरुंगवास, ग्यानव्यापी मस्जिद, मथुरा मस्जिद प्रकरण, वक्फ कायदा, लव जिहाद, घरवापसी, वंदे मातरम्, लिंचिंग, मस्जिद, मदरसे आणि गोरगरीब मुस्लिमांची घरे उद्ध्वस्त करणारा बुलडोझर न्याय अशा अनेक कारणांनी आणि प्रकारांनी भारतात सुरू असलेल्या मुस्लिमांवरील अत्याचारांना वाचा फोडली. हे अत्याचार सरकारी पाठिंब्याने सुरू आहेत. अत्याचार करणाऱ्यांना एकतर्फी खुली सूट तर, मुस्लिमांची मुस्कटदाबी सुरू आहे. माध्यमे पक्षपाती आणि भडकवणारी बनली आहे. सर्वोच्च न्यायालय सरकारी दबावाखाली काम करत आहे. असा आरोप त्यांनी भाषणात केला. राज्यघटनेचे रक्षण करत असेल तरच सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च म्हणवण्यास पात्र आहे. अन्यथा, सर्वोच्च न्यायालयाला नैतिकदृष्ट्या सर्वोच्च म्हणवण्याचा हक्क नाही. या वक्तव्यावर माध्यमांमध्ये गदारोळ उठला. जिहाद आणि इस्लाम अभिन्न आहेत. जिहाद इस्लामिक पवित्र कर्तव्य आहे. जिहादचा कोणी दहशतवादासाठी वापर केला असेल, पण जिहाद हा न्याय आणि मानवता प्रस्थापनेसाठीचा इस्लामी संघर्ष आहे. असे सांगून त्यांनी 'जब जब जुल्म होगा, तब तब जिहाद होगा' याचा पुनरुच्चार केला. धार्मिकबाबतीत सरकारने हस्तक्षेप करू नये. अन्यथा आम्ही लढू, अगदी जीवनाच्या अंतिम श्वासापर्यंत लढू! हे वक्तव्य भडकावू आणि मुस्लिमांना चिथावणी देणारे आहे. असा त्यांच्यावर आरोप होत आहे.

देवबंद मदरसा हा इजिप्तमधील अल अझहरनंतरचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मदरसा आहे. जमात ए उलेमा ए हिंद ही मुख्यतः देवबंद मदरशात शिकलेल्या धर्मगुरूंची राष्ट्रीय संघटना आहे. अलीकडे याचे अर्शद मदनी आणि महमूद मदनी असे दोन गट बनले आहेत. या संघटनेच्या शीर्षस्थानी बहुतेक स्कॉलर धर्मगुरू असतात. तळात सुन्नी मस्जिदचा धर्मगुरू या संघटनेशी जोडलेले असतात. खिलाफत चळवळीच्या काळात १९१९ मध्ये या संघटनेची स्थापना झाली. ही संघटना भारतीय स्वातंत्र्य लढयात सहभागी होती. तिने पाकिस्तान निर्मितीला विरोध आणि अखंड भारताचा पुरस्कार केला होता. स्वातंत्र्यानंतर या संघटनेने मुस्लिमांची धार्मिक अस्मिता, ओळख पक्की करण्यावर भर दिला. धर्म आणि धार्मिक कायद्याचे शिक्षण देणे, इस्लामचा प्रचार करणे, इस्लामिक तत्त्वांनुसार (हलाल आणि हराम इ.) आणि धर्मकायद्यांना (शरिया) अनुसरून मुस्लीम काटेकोरपणे धर्माचरण करतील यावर लक्ष केंद्रित केले. भारतातील मदरसा चळवळ आणि तबलिक चळवळीच्या उभारणीत त्यांचा मोठा वाटा आहे. धर्म परंपरा आणि धार्मिक कायदा (शरिया), धर्म संस्था (मस्जिद, वक्फ, मदरसा,) यांचे प्राणप्रिय विषय आहेत. ते स्वतःला धार्मिक अधिसत्तेचे वाहक आणि धर्मसंस्थांचे रक्षक मानतात. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डवर त्यांची पकड आहे. आजही, देवबंदी धर्मगुरूंची राजकीय आघाडी म्हणून ही संघटना काम करते. जनमनावर त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम स्त्रीला पोटगी देण्याचा निर्णय दिला, याविरुद्ध काहूर माजवून मुस्लीम स्त्रियांसाठी नवा कायदा करायला यांनीच काँग्रेसला भाग पाडले होते. काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत भेटीवर आले असता, त्यांनी देवबंदला जाऊन धर्मगुरूंची भेट घेतली. यावरून त्यांचा राजकीय प्रभाव लक्षात येऊ शकतो. ओवेसी मुस्लीम समाजावर आपला राजकीय प्रभाव वाढवत आहेत. त्यामुळे या संघटनेचा ओवेसींच्या राजकारणाला विरोध आहे.

स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत भारतीय मुस्लिमांना आधुनिक, पुरोगामी विचार देणारा बुद्धिवादी नेता भेटला नाही. मुस्लीम समाजामध्ये व्यापक राजकीय आणि सामाजिक परिवर्तनाची कोणतीही चळवळ निर्माण झाली नाही. ती जागा धर्मगुरूंनी आणि धार्मिक संघटनांनी भरून काढली. जनाधार नसलेले फुटकळ आणि संधीसाधू मुस्लीम राजकीय नेते स्वाभाविकपणे धार्मिक नेत्यांच्या ओंजळीने पाणी पितात. मुस्लीम विचारवंत पुस्तकबंद आणि समाजापासून पूर्णतः तुटलेले आहेत. मुस्लीम समाज धार्मिक जनचळवळ आणि साचेबद्ध धर्मविचारात बंदिस्त झाला आहे. मुस्लिमांचा विचार, रोजची दिनचर्या, बोलाचालीची भाषा धर्मगुरूंनी प्रभावित आहे. धर्म सर्वप्रथम, सर्व काही धर्मासाठी इतक्या टोकाला विचार पोचला आहे. इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य या सर्वांचा अर्थ मुस्लीम समाज धर्मग्रंथ आणि धर्मशास्त्राच्या साहाय्याने समजावून घेतो आहे. त्यामुळे वास्तविक जीवनाशी त्याचे नाते तुटले आहे. वास्तव आणि श्रद्धा यामध्ये मुस्लीम व्यक्तिमत्त्व भंग पावले आहे. त्यामुळे आजच्या राजकीय परिस्थितीला त्याला सापेक्षपणे समजावून घेणे खूप कठीण आहे.

मौलाना महमूद मदनी राजकीय वास्तव आणि अत्याचार मार्मिकपणे मांडतात. त्यात अतिशयोक्त नाही. पण तेसुद्धा वर्तमानाचे विश्लेषण धर्मविचारांनी करत असल्याने, समस्येचे उत्तर धर्मातच शोधतात. त्यांना हल्ला मुख्यतः मस्जिद, मदरसा आणि शरियावर होताना दिसतो. आता 'धर्म' हीच मुसलमानांची ओळख आणि 'धर्माचरण' हेच जीवनसार्थक बनवले गेले आहे. त्यामुळे मदनी यांना, सरकारला धार्मिक हस्तक्षेपासून दूर ठेवण्यात, मुस्लिमांच्या मुक्तीचा कार्यक्रम दिसतो. त्यांचा हा तर्क अगदी बरोबर आहे. त्यांच्या दृष्टीने जीवन जगणे असेल किंवा अन्यायाविरुद्धचा लढा असेल, त्याचे समाधान इस्लाममध्ये दिसणे स्वाभाविक आहे. म्हणून ते म्हणतात, जिहाद एक मुकद्दस दिनी फराईज है, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा!

भारताच्या राज्यघटनेने प्रत्येकाला मूलभूत मानवी हक्क आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिले आहे. संघटन करण्याचा आणि सरकारविरुद्ध असंतोष व्यक्त करण्याचा, सरकार बदलण्याचा हक्क दिला आहे. ही राजकीय आणि वैचारिक लढाई आहे. देशात फॅसिझम माजला तर त्याचा त्रास प्रत्येक भारतीयाला होईल. लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे प्रत्येकाचे राजकीय कर्तव्य आहे. देशात लोकशाही आणि मूलभूत अधिकार शिल्लक राहिले तरच अल्पसंख्य सुखाने जगू शकतील. बहुसंख्य समाजाला सोबत घेऊन हा राजकीय संघर्ष करावा लागेल. या लढाईत आदिवासी, भटकेविमुक्त, स्त्रिया, दलित, बहुजन कष्टकरी सोबत असतील तरच ही लढाई शक्य आहे. मुस्लिमांना यांच्यासोबत राहून आपले कर्तव्य पूर्ण करावे लागेल. जर, जुल्म के खिलाफ जिहाद होणार असेल तर सोबत कोण येणार? जिहाद कितीही पवित्र कार्य असेल किंवा यात इस्लामिक महान तत्त्व सामावले असेल, जर वंदे मातरम् म्हणण्यात आपला धर्म आडवा येतो, अशी श्रद्धा असेल तर हिंदूंनी जिहादमध्ये सहभागी होण्याची अपेक्षा कशी करायची? बरे अन्यायविरुद्ध लढाई एकट्या मुस्लिमांच्या बळावर होणार आहे का? याचा साधा विचार करायला नको का? भारतात स्वातंत्र्यसंघर्ष आणि समाजपरिवर्तनाचे लढे झाले आहेत. त्यात काही वेळा चुका झाल्या. त्या इतिहास काळातील मर्यादांमुळे. पण नव्या युगात सामाजिक समतेचा संघर्ष धार्मिक चौकटीत करायचा का? भाजप-संघ आणि उलेमा हिंद राजकारणात परस्पर विरोधात दिसले तरी एकाच वैचारिक नावेतून प्रवास करत नाहीत काय?

११ व्या आणि १२ व्या या दोन शतकांतील जिहाद आणि होली वॉरचा इतिहास उपलब्ध आहे. आज इस्राय़ल आणि अरब संघर्ष गाझाच्या निमित्ताने ताजा आहे. भारतात १७५७ ते १८५७ च्या काळात ब्रिटिशांच्या विरोधात जिहाद फसल्याचा इतिहास आहे. आजवर धर्मवेडात लाखोंनी प्राण गमावले आहेत. प्रचंड संहार मानवाने अनुभवला आहे. धर्म खरोखरच प्रेमाचा संदेश आणि प्रेरणा देतो का? देत असेल तर त्याला त्यापुरते मर्यादित ठेवायला हवे. राजकीय अन्याय संपविण्यासाठी, धर्मयुद्ध उपयोगाचे नाही. कोणतीही हिंसक क्रांतीदेखील उपयोगाची नाही.

खरेतर, सर्व समाजाची मानसिक बंदिस्तता (सायकॉलॉजिकल कंडिशनिंग) संपवून मानसिक मुक्तीकडे (सायकॉलॉजिकल लिबरेशन) नेणारा विचार रुजविण्याची गरज आहे. धर्मांधता आणि अतिरेकी राष्ट्रवादी माथेफिरूपणापासून मुक्ततेसाठी लहानपणापासून वैज्ञानिक दृष्टी (सायन्टिफिक टेंपरामेंट) आणि चिकित्सक जाणिवेचा (क्रिटिकल कॉन्शिअसनेस) विचार रुजविण्याची गरज आहे. प्रत्येक आईबापाला आपली मुले सार्वाधिक प्रिय असतात. त्यामुळे आपल्या मुलांची सुरक्षा, मानसिक, भावनिक समृद्धी आणि भविष्यकाळातील सुखी समाधानी जीवनासाठी प्रत्येकाने हा दृष्टिकोन अंगीकारला पाहिजे. धर्माच्या पलीकडे जाऊन हा बौद्धिक विकासच आपल्या मुलांना भावी नरसंहारापासून वाचविणार आहे.

मुस्लीम समाजाने वैज्ञानिक समाज बनून ज्ञानाधारित उद्योग उभारणीकडे लक्ष द्यावे. त्यासाठी संशोधन संस्था आणि उच्च विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या शैक्षणिक संस्था उभ्या कराव्यात. बौद्धिक आणि मानसिक उन्नतीवर भर द्यावा. अन्यथा दोन्ही समाजांमध्ये धर्माच्या नावाखाली होणाऱ्या संघर्षात सामान्यांचा बळी देण्याची तयारी जोरात सुरू आहे. त्यात बळी जायचे का, याचा निर्णय दोन्ही समाजांतील जनतेने करायचा आहे!

'तत्त्व-विवेक' हे शरद बाविस्कर यांचे सदर या व पुढील आठवड्यात सोमवारऐवजी बुधवारच्या अंकात असेल.

कुतूहल

चुंबकानुचलित जीवाणू!

काही जीवाणू पृथ्वीच्या चुंबकीय शक्तीला संवेदनशील असतात. ही संवेदना त्यांना दिशा धुंडाळण्याला उपयोगी पडते. यासाठी ते वेगवेगळे चुंबकीय संवेदक (मॅग्नेटिक रिसेप्टर) वापरतात.

१९६३ मध्ये साल्व्हाटोर बेलीनी याला सूक्ष्मदर्शकाखाली चिखलाचे परीक्षण करताना असे काही जीवाणू आढळले की जे उत्तर ध्रुवाकडे आकर्षित होत होते. हे जीवाणू पृथ्वीच्या चुंबकीय रेघांच्या अनुसार अनुचलित होतात म्हणून त्यांना चुंबकानुचलित जीवाणू म्हणतात.

जीवाणूंच्या बऱ्याच जाती-प्रजातींमध्ये अशी चुंबकीय संवेदना असते. उदाहरणार्थ मॅग्नेटोस्पिरीलम मॅग्नेटोटॅक्टिकम, मॅग्नेटोबॅक्टेरियम बव्हॅरिकम, मॅग्नेटोस्पिरीलम ग्रीफिसवाल्डेंस, मॅग्नेटोकोकस प्रजाती इत्यादी. सामान्यतः चुंबकानुचलित जीवाणूंना अत्यल्प प्रमाणात प्राणवायूची आवश्यकता असते. या जीवाणूंचे आकार गोल, दंडगोलाकर किंवा सर्पिल असे असतात. त्यांच्या पृष्ठावर असलेल्या कशाभिकांमुळे हे जीवाणू गतिशील असतात. चुंबकीय जीवाणू काही जीवाश्मातही आढळले आहेत.

या चुंबकानुचलित जीवाणूत छोट्या छोट्या पिशवीत चुंबकाकडे आकर्षित होणाऱ्या धातूचे स्फटिक असतात. याच स्फटिकांमुळे असे जीवाणू चुंबकीय रेघांनुसार अनुचलित होतात. अगदी मेलेल्या पेशीसुद्धा चुंबकार्षित होतात. चुंबकानुचलित जीवाणूत ५० ते १०० नॅनोमीटर एवढ्या छोट्या आकाराची चुंबकीय स्फटिके आढळतात. चुंबकानुचलित जीवाणूंचे वर्गीकरण त्यातील चुंबकाकडे आकर्षित होणाऱ्या स्फटिकांवर अवलंबून असते. हे स्फटिक चौकोनी, अष्टकोनी, दंडगोलाकार इत्यादी आकाराचे असतात. हे जीवाणू पाण्यातील लोहाच्या मॅग्नेटाइट (आयर्न ऑक्साइड) किंवा ग्रेगाइट (आयर्न सल्फाइड) क्षारांचा उपयोग करून स्वतःच्या पेशीच्या आवरणात छोटी छोटी स्फटिके किंवा नॅनो चुंबकीय कण तयार करतात. यासाठी त्यांच्या पेशीत असलेल्या मॅग्नेटोसोम या कोशिकांगाचा उपयोग होतो. या कोशिकांगात असे कण तयार करण्यासाठी लागणारी सर्व विकरे व सामुग्री असते. त्यातील धातूचे स्फटिक हळूहळू मोठे होत, एकमेकाशी संलग्न होत साखळी तयार करतात व अशा तऱ्हेने नॅनो चुंबकीय कण स्वतःभोवती चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करू शकतात. चुंबकानुचलित जीवाणू त्यांच्या वजनाच्या १-३% लोह पेशीत शोषून त्याचे एकसारखे नियमित आकाराचे, एकच चुंबकीय क्षेत्र असलेले नॅनो चुंबकीय स्फटिक तयार करतात.

अशा प्रकारच्या स्फटिकांची निर्मिती कृत्रिमपणे करताना त्यांचे आकार समसमान ठेवणे जवळजवळ अशक्यप्राय असते. या स्फटिकांचा उपयोग जैवनॅनोतंत्रज्ञानात व जैवविश्लेषण जैवोपचारण, विकरशास्त्रात, मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग आणि प्रतिरक्षाशास्त्रात करता येतो. नॅनो चुंबकीय कणांचा विविध कर्करोगविरोधी रसायनांबरोबर संयोग करून, बाहेरून चुंबकीयक्षेत्र वापरून त्यांना कर्करोगग्रस्त कोशिकांकडे प्रवाहित करता येते. शिवाय संगणकशास्त्रात स्मृतीनिर्मितीतदेखील नॅनो चुंबकीय कणांचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

– डॉ. जयश्री कृष्णा सैनिस
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

नगरपालिका निवडणुकीपासून सुरुवात करून लोकसभाध्यक्ष पदापर्यंतचा चढता आलेख शिवराज पाटील चाकूरकर यांचा राजकीय प्रवास एक संदेश आवर्जून देतो... तो म्हणजे यशस्वी होण्यासाठी प्रत्येक वेळी लोकानुनयाची गरज नसते. सध्या राजकीय पटावर निवडणुका जिंकण्यासाठी 'लाडके'पणाचा बाजार तेजीत असताना ऐन निवडणुकीच्या काळातही आपल्या दैनंदिनीमध्ये फारसे बदल न करणारा नेता अशी त्यांची ख्याती होती. 'देवघर' हे त्यांच्या घराचे नाव. घरात दोन छायाचित्रे. एक पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे आणि दुसरे इंदिरा गांधी यांचे. आयुष्यावर या दोन नेत्यांचा प्रभाव. व्यक्तिगत आयुष्यात पुट्टपूर्तीच्या सत्यसाईबाबांचे भक्त. भाषा कमालीची संयत. एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर देताना जणू निरुपणास बसवले आहे, ही जाणीव देणारे व्यक्तिमत्त्व. 'गीता', 'ओशो' येथपासून ते काँग्रेसचे राजकारण, संसदीय कामाच्या पद्धतीसह राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय समस्यांची जाण असणारा नेता. सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केल्यामुळे कायद्यातील पळवाटा शोधून काय केले जाते, याची जाणीव त्यांना होती. परिणामी संसदीय स्थायी समितीच्या रचनेमध्ये विधेयकाची चिकित्सा करण्यावर त्यांचा भर असे.

शिवराज पाटील

घटनेला अभिप्रेत असणारी राजकीय चौकट पाळणारा नेता हे चाकूरकर यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य. नगरपालिकेचे प्रश्न खासदारांनी सोडवायचे नसतात, हे तत्त्व त्यांनी कायम पाळले. मग कितीही जवळचा कार्यकर्ता असेल तर ते प्रश्न सोडवायला नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याला चाकूरकर यांनी कधीही फोन केला नाही. खासदार म्हणून निवडून गेले तेव्हा राष्ट्रीय विचार करणेच अभिप्रेत असते, हे मतदारांनाही समजावून सांगण्याचा स्वभाव. त्यामुळे कडक शिस्तीचा माणूस ही त्यांची प्रतिमा कायम होती. त्यांनी कार्यकर्ते हेरले नाहीत, असेही नाही. पण कार्यकर्ते हे झुंडीने असायला हवेत, असे त्यांना कधी वाटले नाही. त्यांचा एकदा पराभव करण्यासाठी काँग्रेसमधील नेत्यांनीच बऱ्याच कुरापती केल्या. पण चाकूरकर यांनी काँग्रेसमधील सहकाऱ्यांविरोधात कधी वावगा शब्द काढला नाही. कधी कोणी दुखावेल, अशी टीका केली नाही. दहशतवादी विचार मारायचा असतो, व्यक्ती नाही, असे तत्त्वज्ञान अंगी बाळगणारा नेता, हे त्यांचे वैशिष्ट्य.

लातूरचे प्रतिनिधित्व करणारे चाकूरकर हे लातूरचे कमी आणि देशाचे अधिक होते. विचारांची व्याप्ती राष्ट्रीय पातळीवर आडवा-उभा छेद घेणारी. त्यामुळे कोणत्या निर्णयाची अंमलबजावणी देशातील लोक कसे स्वीकारतील, त्यात कोणत्या उणिवा राहू शकतील, याचा अंदाज त्यांना होता. त्याच वेळी देशाचे शत्रू आणि मित्र घेतलेल्या निर्णयावर कसा विचार करतील, याची जाणीवही त्यांच्यामध्ये होती. चॉकलेटी, काळ्या तर कधी करड्या रंगाची जोधपुरी हा सार्वजनिक जीवनातील पेहराव त्यांनी फारसा बदलला नाही. स्वच्छता हा त्यांचा आवडता गुण. त्यामुळे कायमच परीटघडीचे कपडे वापरणाऱ्या या व्यक्तीवर माध्यमांमध्ये टीका झाली ती पोशाखावरूनच. कपडे बदलणे हा सार्वजनिक जीवनात मूल्यमापनाचा निकष कसा होऊ शकतो, अशी त्यांची भारतीय माध्यमांबाबतची तक्रार होती. लोकसभा अध्यक्ष म्हणून काम करणाऱ्या शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्यावर भाजप नेत्यांनीही कधी फार आक्षेप घेतले नाहीत. व्यक्तिगत आयुष्यात आध्यात्मिकता जोपासणारे चाकूरकर भाजप आणि रा. स्व. संघातील मंडळींचेही आवडते होते. पण तरीही त्यांनी काँग्रेसची विचारधारा शेवटपर्यंत जपली. एक घास ३२ वेळा चावून खावा, हा सल्ला भोजनात आणि व्यक्तिगत आयुष्यात जपणाऱ्या या नेत्याचे 'ओडिसी ऑफ माय लाइफ' हे पुस्तक त्यांचा राजकीय पट समजावून घेण्यासाठी उपयोगी पडते.

तर्कतीर्थ विचार

मराठी विश्वकोशाचे ध्यासपर्व

मराठीत प्रचलित ज्ञानकोश, महाकोश, विश्वकोश हे मूलतः इंग्रजीतील 'एन्सायक्लोपीडिया' शब्दाचे पर्यायवाची संज्ञापन होय. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या प्रमुख संपादकत्वाखाली सुरू झालेला 'मराठी विश्वकोश' आजमितीस २० संहिता खंड, १ परिभाषासंग्रह, १ सूचिखंड, १ परिचयग्रंथ, कुमारकोश ४ खंड अशा रूपात निरंतर विकासशील वाटचाल करीत आहे. यातील मूळ २० संहिता खंड आता महाजालावर (इंटरनेट) उपलब्ध आहेत. शिवाय ते तबकडी (कॉम्पॅक्ट डिस्क), संचयक (पेनड्राइव्ह) रूपातही उपलब्ध आहेत.

'एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका' (१७६८-२०१०)चा प्रारंभ झाला तोच मुळी 'अपरंपार ज्ञानवृद्धीने मानवी जीवन समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने.' (लेट नॉलेज ग्रो मोअर अँड मोअर, अँड दस बी ह्युमन लाइफ एन्रिच्ड). पुढे हेच जगातील सर्व विश्वकोशांचे ब्रीद होऊन गेले. मराठीत विश्वकोश तयार झाले पाहिजेत, असा विचार गोविंद नारायण माडगावकर यांनी मांडला होता. त्यानुसार पहिला प्रयत्न 'अनेक विद्या-मूलतत्त्व संग्रह' (१८६१)च्या रूपाने कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांनी केला; पण 'सर्वविषयक संग्राहक कोश' हे जे 'वैश्विक ज्ञानकोश'चे आदर्श रूप आहे, त्या स्वरूपाचा पहिला प्रयत्न डॉ. श्री. व्यं. केतकर यांच्या संपादकत्वाने 'महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश' (१९२०-२९) रूपात २३ खंडांत प्रसिद्ध झाला होता. त्याच्या व्यक्तिविशिष्ट मर्यादेमुळे तो परिपूर्ण मानला जाऊ शकला नाही. त्याची पूर्तता महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या आधिपत्याखाली तर्कतीर्थांनी केली.

मराठी विश्वकोश निर्मितीचा काळ १९६२ ते २०१९ असा राहिला आहे. यातील २० संहिता खंडांपैकी १५ खंडांचे संपादन तर्कतीर्थांनी केले. या प्रकल्पाचा संकल्प तर्कतीर्थांनी सोडला नि त्याचा अधिकांश भागही यांच्याच प्रयत्नाने पूर्णत्वास गेला.

मराठी विश्वकोशाच्या संकल्प ते सिद्धीचा विधिवत वृत्तांत अद्यापपर्यंत लिहिला गेला नव्हता. त्याची परिपूर्ती 'तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी समग्र वाङ्मय' प्रकल्पातील पहिल्या खंडाच्या (मराठी विश्वकोश नोंदसंग्रह) प्रस्तावनेत काहीएक प्रमाणात करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. तर्कतीर्थांनी हा प्रकल्प शास्त्रोक्त व्हावा म्हणून प्रथम एक 'परिचय ग्रंथक्ष (१९६५) लिहून तो विविध वृत्तपत्रे, नियतकालिके, तज्ज्ञ यांच्याकडे अभिप्रायार्थ धाडून जनप्रतिसाद व जनप्रतिक्रिया अजमावली. जी प्रतिक्रिया, टीका, प्रतिसाद पत्रे आली, त्यांना जाहीर व व्यक्तिशः उत्तरे, प्रतिक्रिया देऊन, प्रकाशित करून 'मराठी विश्वकोश' निर्मिती केली. हा प्रकल्प म्हणजे लोकसहभाग नि लोकनिधीतून केलेला ज्ञाननिर्मितीच्या लोकशाहीकरणाचा आदर्श वस्तुपाठ होय. हे कार्य तर्कतीर्थांच्या जीवनातील ज्ञानसाधना व ज्ञाननिर्मितीचे ध्यासपर्व होते. या प्रकल्पपूर्तीने मराठी भाषेत ज्ञानविज्ञानाची परिभाषा वापरून ज्ञान-विज्ञानातील विविध विषय अर्थघनता व विशदार्थतेने परिपूर्ण रूपात संदर्भस्त्रोत म्हणून उपलब्ध झाले आहेत. तेच तर्कतीर्थांचे मराठी भाषा ज्ञानभाषा करण्यातील योगदान होय. यातील 'परिभाषासंग्रह' निर्मिती ही तर्कतीर्थांची मराठीस ज्ञानभाषा सिद्ध करण्यातील खरी कामगिरी होय.

तर्कतीर्थांनी हा प्रकल्प पूर्ण करतानाच्या काळात अत्यल्प मानधन घेतले. त्यांच्या पत्नी सत्यवतीबाई यांनी एका मुलाखतीत 'पस्तीस रुपये पगारात (मानधन) संसारात जे कौशल्य होते (चालविण्याचे) ते पस्तीसशे मिळाल्यावरही कायम होते,' हे नमूद करून ठेवले आहे. नोंद लेखनार्थ येणाऱ्या अभ्यागतांना दैनिक भत्ता म्हणून ३५ रुपये मानधन दिले जाई. त्याच हिशेबाने तर्कतीर्थांना मासिक मानधन मिळत होते. सत्यवतीबाईंनी सात रुपये किमतीची तीन लुगडी वर्षाला वापरत आयुष्य काढले. तर्कतीर्थ विविध समारंभ, भाषणे, चर्चासत्रे, परिसंवाद इत्यादींमध्ये नित्य सहभागी होत. त्यातून जे तुटपुंजे मानधन लाभे, त्यात समाधानाने त्यांनी संसार करीत आयुष्य काढले. त्यांना प्रतिष्ठा मोठी होती; पण त्यांचे जगणे काटकसरीचे राहिले.

मराठी विश्वकोश छपाईची जी नियमावली आहे. त्यावरून या कोशाच्या शास्त्रोक्त निर्मितीचे रहस्य अवगत होते. मराठी विश्वकोश निर्मितीसाठी कागद कारखाना, मुद्रणालय चालविणे यांतूनही या ध्यासपर्वाची प्रचीती येते. बहुतांश महत्त्वपूर्ण नोंदींचे संपादन तर्कतीर्थ करीत. 'मराठी विश्वकोश' पूर्ण होऊन त्याचा पुनर्लेखन रूपात विकास होत आहे. तथापि सुबोधता, पारिभाषिकता, देशीयता ही नव्या नोंदींपुढची आव्हाने होत. या कोशाचे किमान हिंदी, इंग्रजीत भाषांतर झाल्याशिवाय हा मराठी समृद्ध ज्ञानकोश खऱ्या अर्थाने विश्वकोश सिद्ध होणार नाही.

– डॉ. सुनीलकुमार लवटे
drsklawate@gmail.com

दर्जाशून्यांची दरडावणी?

नियामक संस्थांच्या एकत्रीकरणाचे स्वागत होत असले, तरी नव्या शिखर संस्थेची रचना आणि तिच्या नेतृत्वाचे स्वातंत्र्य, पारदर्शकता याबाबत स्पष्टतेची प्रतीक्षा आहे...

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात उच्च शिक्षण व्यवस्थेविषयी एकच एक नियामक विकसित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. याआधी २०१८ साली असाच प्रयत्न झाला. त्या वेळी त्याचे नाव होते 'हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया'. उच्च शिक्षण आयोग. विद्यमान सरकारने तोच विषय पुढे रेटताना त्याचे नामकरण केले 'विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण'. हे विद्यमान सरकारच्या नामांतर हौसेप्रमाणे झाले. ते ठीक. यामागील शिक्षण क्षेत्राच्या नियमनाचे केंद्रीकरण, प्रमाणीकरण इत्यादी उद्देश रास्त असला तरी सध्या बाकीच्या केंद्रीकृत संस्थांचे जे भुसभुशीकरण झाले आहे, ते पाहता शिक्षण क्षेत्राच्या नियामकाचेही असे होणार नाही असा आशावाद बाळगणे तसे धार्ष्ट्याचेच. यानिमित्ताने शिक्षणासारख्या क्षेत्राबाबत जो नवा प्रयोग अपेक्षित आहे; त्याबाबत ऊहापोह आवश्यक.

गेली काही वर्षे देशातील उच्च शिक्षण यंत्रणा उच्च शिक्षणातील पटनोंदणी अर्थात ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्योच्या (जीईआर) वाढीतच समाधान मानत होती. काहीही करून तो वाढवून प्रगत देशांच्या, गेला बाजार चीनच्या पंक्तीत जाऊन बसण्याची ही धडपड. सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर १०० जण बारावी उत्तीर्ण झाले, तर त्यातील पदवी शिक्षण घेण्यासाठी पुढे किती जातात, याचा आकडा म्हणजे 'जीईआर'. भारताचा सध्या तो साधारण ३० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे वेगवेगळी आकडेवारी सांगते. चीनसह अनेक प्रगत देशांचा हा आकडा कधीच ५०-६० टक्क्यांच्या वर गेला आहे. आपण उद्दिष्टच २०३५ पर्यंत ५० पर्यंत पोचण्याचे ठेवले आहे! 'विकसित' होण्याच्या स्पर्धेत आपण किती मागे आहोत, यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी. पण, आपण समाधान मानून घेत आहोत, ते २०१४ पासून उच्च शिक्षण संस्थांच्या संख्येत किती चांगली, १३ टक्के वगैरे वाढ झाली, यात. प्रत्यक्षात शिक्षण संस्थांत इतकी वाढ होऊनही 'जीईआर'मध्ये चारच टक्के वाढ झाली आहे. त्यातून 'परवडणारे' व्यावसायिक उच्च शिक्षण किती संस्थांतून मिळते, हा संशोधनाचा आणखीच वेगळा भाग. अत्यंत वेगाने खासगीकरण होत चाललेल्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात त्याचे उत्तर काय येईल, हे वेगळे सांगायला नको.

जास्तीत जास्त विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची धडपड करायलाच हवी आहे, यात वाद नाही. पण, विद्यार्थीसंख्या वाढवताना, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जाचे काय आणि वर उल्लेखल्याप्रमाणे मुळात उच्च शिक्षण परवडण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, त्याचे काय, या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात उच्च शिक्षण व्यवस्था कायम कमी पडत गेली हे वास्तव. दर्जाची आणि त्यानुसार निधीवाटपाची ही जबाबदारी सध्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या वेगवेगळ्या नियामकांवर आहे. प्रवेश प्रक्रिया, त्यातील पारदर्शकता, शिक्षण संस्थांच्या अध्ययन-अध्यापन आणि संशोधनातील गुणवत्तेवर आधारित निधीवाटप, प्राध्यापक भरती-कुलगुरू नियुक्तीचे निकष तयार करणे, उच्च शिक्षणाचे प्रमाणीकरण, मूल्यांकन, गुणवत्ता निदान आदी यांची कामे. ती करताना उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे अनस्यूत. तसे प्रयत्न झालेच नाहीत, असे नाही. पण, अपेक्षित परिणाम साधला गेला नाही, हे खरे.

...विशेषतः निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेचे सरकारीकरण, तसेच अभ्यासक्रमात कोणती भाषा असावी, मुलांनी काय शिकावे, शिकू नये याचेही होत असलेले केंद्रीकरण पाहता आगामी नियामकाविषयी शंका येणे साहजिक.

या वेगवेगळ्या नियामकांकडून दर्जाच्या मुद्द्यावर भर देण्यापेक्षा नियमांची जंत्रीच तेवढी बनत राहिली. त्यातून, पारंपरिक अभ्यासक्रमांचे नियमन विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी), व्यावसायिक तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे (एआयसीटीई), अध्यापक शिक्षणाचे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेकडे (एनसीटीई) असे कप्पे पाडले गेल्याने जंत्रीचा पसारा झाला. यातही त्रांगडे असे, की नियमन संस्थांची बरीचशी कामे समान असली, तरी अस्तित्व वेगळे असल्याने अधिकार गाजविण्याची प्रत्येक नियामकाची इच्छा पोसली गेली. उदाहरणार्थ, एखाद्या शिक्षण संस्थेला अभियांत्रिकी वा तत्सम व्यावसायिक तंत्रशिक्षण पदवी अभ्यासक्रम सुरू करून तो चालविण्यासाठी 'एआयसीटीई'कडे जावे लागते. पारंपरिक अभ्यासक्रमांसाठी, तसेच अनुदान, प्राध्यापक भरती, संशोधन आदींची निकषपूर्ती यूजीसीच्या म्हणण्यानुसार करावी लागते. तर, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुरचनाशास्त्र अशा अभ्यासक्रमांच्या नियम-निकषांच्या पूर्ततेसाठी त्या-त्या विषयाच्या स्वायत्त शिखर परिषदेकडे - फार्मसी कौन्सिल, आर्किटेक्चर कौन्सिल - धाव घ्यावी लागते. आता या सगळ्या वेगवेगळ्या नियामक संस्थांचे त्यांच्या त्यांच्या विषयांचे म्हणून काही विशिष्ट निकष सोडले, तर मूलभूत काही निकष समानच असतात. पण, तरी त्यात एकवाक्यता नसते. इतकी, की एखाद्या नियामकाचा साधा शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तरासारखा निकष दुसऱ्या नियामकासारखा असतोच असे नाही. यामुळे शिक्षण संस्थांची भलतीच अडचण होते. थोडक्यात, परवानग्या आणि निकषपूर्ती यातच शिक्षण संस्थांचा कालापव्यय होत राहतो. असे असेल, तर दर्जाकडे कधी लक्ष देणार?

सुमारे दीडेक दशकापूर्वीही हाच प्रश्न उपस्थित होऊन या सर्व नियामक संस्था एकत्रित करून एकच उच्च शिक्षण नियामक संस्था असावी, अशी कल्पना पुढे आली. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात २०११ मध्ये तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिबल यांनी यासंदर्भात राज्यसभेत उच्च शिक्षण आणि संशोधन विधेयकही मांडले. त्यामध्ये यूजीसी, एआयसीटीई आणि एनसीटीईचे एकत्रीकरण करून राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आणि संशोधन परिषदेच्या स्थापनेची कल्पना होती. मात्र, तिन्ही नियामक संस्थांच्या एकत्रीकरणाच्या मुख्य तरतुदीवरच अधिक आक्षेप घेतला गेल्याने त्या वेळी या कल्पनेवर एकमत होऊ शकले नाही, आणि हे विधेयक बारगळले. नंतर तीन वर्षांनी सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने हे विधेयक राज्यसभेतून मागे घेण्याचा निर्णय घेऊन यूजीसी बळकट करण्याचे ठरवले. आता तेही पडले बाजूला आणि सुमारे एका दशकानंतर परवा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०११ चीच कल्पना 'विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक' या नावाने पुढे आणली. भाजप सरकारने तयार केलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात या कल्पनेचा आग्रह आहे, हे त्याचे प्रमुख कारण.

आता खरे तर ही कल्पना २०११ नंतर उच्च शिक्षण परिषदेच्या रूपात २०१८ मध्येही मांडली गेली होती. पण, तेव्हाही ती बारगळली. उच्च शिक्षण नियमनाचे अधिकाधिक केंद्रीकरण हा त्यातील प्रमुख आक्षेप होता. नव्याने सादर केल्या जाणाऱ्या विधेयकात केंद्रीकरणावर उपाय म्हणून एका शिखर संस्थेअंतर्गत नियमन, मूल्यांकन व अधिस्वीकृती, शैक्षणिक परिणाम व प्रमाणीकरण आणि निधीपुरवठा अशा चार कामांचे चार स्वतंत्र विभाग अपेक्षित आहेत. मात्र, शिखर संस्था एकच असल्याने शिक्षण संस्थांना वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या नियामकांकडे धाव घ्यायची गरज नाही. थोडक्यात, ही शिखर संस्था एक खिडकी सुविधेसारखे काम करील. सध्या या नियमनातून विधि आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रम वगळण्यात आले आहेत. त्यांचे नियमन सध्याप्रमाणेच त्या विषयांच्या स्वायत्त नियामक संस्था करतील.

एकीकडे नियामक संस्थांच्या एकत्रीकरणाचे स्वागत होत असले, तरी नव्या शिखर संस्थेची रचना आणि त्यावर नेमल्या जाणाऱ्या नेतृत्वाला मिळणारे स्वातंत्र्य, तसेच पारदर्शकता याबाबत स्पष्टतेची प्रतीक्षा आहे. विशेषतः निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेचे सरकारीकरण, अभ्यासक्रमात कोणती भाषा असावी, मुलांनी काय शिकावे, शिकू नये याचेही होत असलेले केंद्रीकरण पाहता आगामी नियामकाविषयी शंका येणे साहजिक. त्यात केंद्र आणि राज्य यांच्या सामाईक सूचीतील शिक्षणासारखा विषय या नियामक संस्थेच्या निमित्ताने मूल्यांकनापासून निधी वितरणापर्यंत केंद्राच्या दावणीला तर बांधला जाणार नाही ना, हाही प्रश्न आहेच. उच्च शिक्षणाच्या नियमनाचे लक्ष्य मध्यवर्ती नियामक स्थापण्याबरोबरच शिक्षण दर्जा सुधारणे हेही हवे. दर्जाशून्यांची दरडावणी अंतिमतः निरर्थक ठरते.

लाल किल्ला

महेश सरलष्कर

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

शशी थरूर कोणाला फायद्याचे?

केरळमधील थिरुवनंतपूरम महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपपेक्षा अधिक चर्चा झाली ती काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांची. भाजपचा हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महत्त्वाचा विजय असला तरी त्याचे राजकीय अर्थ लावताना थरूर, काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील गुंतागुंतीचे संबंध पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.

केरळमध्ये थिरुवनंतपूरमच्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने विजय मिळवल्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेस नेते शशी थरूर चर्चेत आले आहेत. तसेही ते अलीकडच्या काळात चर्चेतच राहिलेले आहेत. थिरुवनंतपूरम हा थरूर यांचा लोकसभा मतदारसंघ. पण, थरूर यांच्यामुळे भाजपचा विजय झालेला नाही. केरळमध्ये भाजपचा हा मोठा विजय असला तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काँग्रेसच्या आघाडीने बाजी मारली आणि डावी आघाडी या वेळी पिछाडीवर राहिली. थिरुवनंतपूरम हा 'माकप'चा गड होता. महापालिका त्यांच्या ताब्यात होती, ती हिसकावून घेण्यात या वेळी भाजपला यश आले आहे. हा निकाल काँग्रेस आघाडीसाठी नव्हे, तर केरळमधील डाव्या आघाडीसाठी धोक्याची घंटा आहे. मुद्दा असा की, केरळमध्ये भाजप डाव्या आघाडीला अधिक कमकुवत करत आहे, त्यामुळे या राज्यात शशी थरूर यांच्यामुळे काँग्रेसचे फारसे नुकसान होईल असे दिसत नाही. आणि थरूर यांचा भाजपला फायदा होणार असता तर भाजपने त्यांना कधीच आपल्या पक्षात घेतले असते. तसेही होताना दिसत नाही. काँग्रेसने थरूर यांना पक्षातून काढले तरी भाजपसाठी ते उपयुक्त नाहीत, त्यामुळे ते काँग्रेसमध्येच राहणे भाजपसाठी अधिक योग्य आहे. पण, काँग्रेसने त्यांना पक्षातून काढले नाही याची कारणे वेगळी आहेत.

मोदी-शहा, केंद्र सरकारची धोरणे आणि भाजप या सगळ्यांकडे कसे बघायचे, त्यांना विरोध कसा करायचा याबाबत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि शशी थरूर यांचे विचार वेगवेगळे आहेत. अहमदाबादला झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये थरूर यांनी त्यांचे विचार सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासमोर व्यासपीठावरून बोलून दाखवले होते. थरूर यांचे म्हणणे होते की, काँग्रेस सातत्याने नकारात्मक विचार करत आहे. मोदींना दूषणे देण्यातून काँग्रेसला काही मिळणार नाही. त्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने काँग्रेसने भाजपच्या राजकारणाला सामोरे गेले पाहिजे. देशातील तरुणांचा जास्त ओढा भाजपकडे आहे. तरुणांना जोडून घेण्यासाठी, संघटनेची नवी बांधणी करण्यासाठी काँग्रेसने सकारात्मक विचार केला पाहिजे. नव्या पिढीसाठी सशक्त पर्याय दिला

पाहिजे. आत्ता काँग्रेस फक्त मोदींवर टीका करण्याचे काम करत आहे, लोकांसाठी पर्याय देत नाही! थरूर करतात तसा विचार राहुल गांधी विचार करत नाहीत. त्यांचा अधिक भर संघ-भाजपला विरोध करण्यावर आहे. आता ते मतचोरी वगैरे मुद्द्यांकडे वळले आहेत. थरूर आणि राहुल गांधी यांचे भाजपविरोधाचे मार्ग वेगवेगळे आहेत. शिवाय, पक्षाध्यक्षाच्या निवडणुकीत थरूर हे खरगेंविरोधात लढले होते. गांधी कुटुंबाचा पाठिंबा खरगेंना होता. हेही नाही म्हटले तरी थरूर दुखावण्याचे कारण आहे. त्यातून थरूर आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये दरी निर्माण होऊन ती वाढू लागली आहे.

थरूर यांच्यामुळे काही उच्चवर्णीय, उच्चमध्यमवर्गीय काँग्रेसकडे आकर्षित होऊ शकतील, पण काँग्रेसने खरगेंची निवड करून भाजपला अनेकदा माघार घ्यायला भाग पाडले आहे. राज्यसभेत 'वंदे मातरम'वर चर्चा करताना खरगेंनी, दलितांना मंदिरात जाऊ दिले जात नाही, असे विधान केल्याबरोबर नड्डा उठून उभे राहिले. त्यांना, दलित आमचेच आहेत, भाजप सरकारच्या काळात त्यांच्या विकासाकडे अधिक लक्ष दिले गेले, असे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. काँग्रेससाठी खरगे ही ताकद आहे, थरूर नव्हे. काँग्रेसने थरूर यांना पक्षाध्यक्ष केले असते तर सर्वाधिक लाभ भाजपला झाला असता आणि आत्ता तो कसा होतो हे दिसले. थरूर हे काँग्रेसचे खासदार असल्यामुळे पक्षातून त्यांना काढले जात नाही. शिवाय, त्यांची हकालपट्टी करणे म्हणजे भाजपच्या हाती कोलीत देण्याजोगे ठरेल. पण, थरूर यांना काँग्रेसची धोरणे मान्य नसतील तर त्यांना पक्षातून बाहेर पडण्याचा मार्ग खुला आहे. मग, ते तो का स्वीकारत नाहीत, असा प्रश्न आहे. पक्षात असाल तर पक्षशिस्त पाळली पाहिजे ही पक्षाची अपेक्षा असणारच. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्या स्नेहभोजनाला मोदींनी थरूर यांना निमंत्रण दिले, पण लोकसभा व राज्यसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांना वगळले. पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांचा मोदींनी अपमान केलेला असताना थरूर स्नेहभोजनाचे निमंत्रण स्वीकारत असतील तर ते पक्षनेतृत्वाला एक प्रकारे नाकारणेच ठरते. मग, काँग्रेस थरूर यांच्याविरोधात बोलणारच! 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर केंद्र सरकारने परदेशात पाठवलेल्या शिष्टमंडळांसाठी काँग्रेसने शशी थरूर यांचे नाव दिलेले नव्हते. तरीही केंद्राने थरूर यांचा समावेश केला. तृणमूलच्या अभिषेक बॅनर्जींनाही केंद्राने घेतलेले नव्हते. तेव्हा ममता बॅनर्जींनी दबाव आणून अभिषेकना शिष्टमंडळात घ्यायला लावले. थरूर यांनी मात्र काँग्रेस नको म्हणत असताना शिष्टमंडळाचे नेतृत्व स्वीकारले होते.

थरूर यांच्याकडे जागतिक दृष्टिकोन किंवा शहाणपण आहे, परराष्ट्र धोरणाची जाण आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगले नेटवर्किंग आहे. देशांतर्गतही त्यांचे वेगवेगळ्या पक्षांतील नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत. त्यांचे वाचन, त्यांचे इंग्रजी, त्यांचे वक्तृत्व यामुळे त्यांच्याशी संवाद साधणारे प्रभावित होतात. या कलागुणांचा काँग्रेसला योग्य वापर करता आला असता हेही खरे. पक्षात प्रगती होत नाही म्हणून अनेक काँग्रेस नेते भाजपमध्ये गेले तसे थरूर यांनाही जाता आले असते. मग, ते का जात नाहीत? कदाचित भाजप त्यांना पक्षात घ्यायला तयार नसावा. जे काँग्रेस नेते भाजपमध्ये गेले त्यांचा भाजपला निवडणुकीच्या गणितासाठी फायदा होतो. जातीची गणितेही असतात. थरूर यांना पक्षात घेऊन यापैकी भाजपला कशाचा फायदा होईल? थरूर लोकसभा निवडणूक जिंकू शकतात, पण ते लोकनेते नाहीत, ते संघटना मजूबत करू शकत नाहीत. त्यांचा वावरही संपूर्ण केरळभर नाही. त्यांच्या असण्याने काँग्रेस मजबूत होऊ शकत नसेल तर भाजप कसा होणार? केरळमध्ये संघ-भाजपचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. 'माकप' आणि संघ यांचे कार्यकर्ते सातत्याने एकमेकांना भिडत असतात. केरळमध्ये भाजपला 'माकप'ची जागा घ्यायची आहे, काँग्रेसची नव्हे. भाजपला 'माकप'चा उच्चवर्णीय आणि ओबीसी मतदार स्वतःकडे खेचून घ्यायचा आहे. काँग्रेसचा मतदार प्रामुख्याने ख्रिश्चन, मुस्लीम, हिंदू दलित-आदिवासी आहे. हा भाजपचा मतदार नव्हे. या केरळच्या जातींच्या राजकारणात थरूर कुठे बसतात? थरूर यांना भाजपमध्ये घेतले तर कुठला मतदार भाजपकडे वळेल? केरळमध्ये मजबूत होण्यासाठी भाजपला थरूर यांची गरज नाही. तिथे भाजपने राजीव चंद्रशेखर यांच्यासारखे नवे नेते निर्यात केलेले आहेत. थिरुवनंतपूरममध्ये भाजपने या वेळी महापालिका जिंकली तशी पक्ष पुढची लोकसभा निवडणूकही जिंकू शकेल. चंद्रशेखर कदाचित दुसऱ्यावेळी थरूर यांच्याविरोधात यशस्वी ठरू शकतील. असे असेल तर थरूर यांना पक्षात घेण्याची घाई भाजप कशाला करेल?

काँग्रेसचा अपमान करण्यासाठी भाजप थरूर यांचा वापर करत असल्याचे दिसते आणि थरूरही जाणीवपूर्वक आपला वापर होऊ देत असावेत असे वाटते. नाही तर त्यांनी पुतिनसाठी आयोजित स्नेहभोजनाचे निमंत्रण स्वीकारले नसते. काँग्रेसचा विरोध असताना ते शिष्टमंडळ परदेशात घेऊन गेले नसते. थिरुवनंतपूरमच्या महापालिकेच्या निकालानंतर थरूर यांनी, हीच तर लोकशाहीची किमया आहे, असे काँग्रेसला डिवचणारे विधान केले नसते. काँग्रेसच्या नेत्यांनी थरूर यांच्याविरोधात वारंवार जाहीर टिप्पणी केली आहे, पण त्याचा परिणाम उलट झालेला दिसतो. भाजप थरूर यांच्या भूमिकांची अधिकाधिक चर्चा घडवून आणतो, त्यावर काँग्रेस भाजपला अपेक्षित प्रतिसाद देतो. त्यातून काँग्रेसचा काही फायदा होत नाही. त्यापेक्षा काँग्रेसने थरूर यांच्यावर प्रतिक्रिया देणे बंद करण्याची गरज आहे. जितके थरूर यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाईल तेवढी भाजपसाठी थरूर यांची उपयुक्तता कमी होईल. शिवाय, थरूर यांचे राहुल गांधी-प्रियंका गांधी यांच्याशी पूर्ण बिनसले आहे, असेही नाही. दोन दिवसांपूर्वी लोकसभेच्या सभागृहात थरूर आणि प्रियंका गांधी एकमेकांशी संवाद साधताना दिसले. थरूर यांना अडचणीत आणण्यासाठी सावरकरांच्या नावाचा पुरस्कार थरूर यांना जाहीर झाला, पण हा पुरस्कार कोणता हे आपल्याला माहीत नाही, आपण तो स्वीकारणार नाही, अशी ठाम भूमिका थरूर यांनी घेतली. हे पाहिले तर थरूर आणि काँग्रेस यांच्यातील सगळेच धागे तुटलेले नाहीत. भाजपसाठी थरूर यांचा जेवढा उपयोग व्हायचा तेवढा कदाचित झालेला आहे. थरूर यांनीही काँग्रेसशी जुळवून घेणे जरुरीचे ठरते, अन्यथा ना ते काँग्रेसचे राहतील ना भाजपचे!

अन्वयार्थ

अधिकारांपेक्षा महसूल वाढावा

मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या निर्णयाच्या विरोधात थेट उच्च न्यायालयात दाद मागण्याऐवजी राज्य शासनाकडे अपील करण्याची तरतूद असलेले विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. परिणामी यापुढील काळात मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालयाने एखाद्यास मुद्रांक भरण्याची नोटीस बजाविल्यास त्या विरोधात शासन म्हणजेच महसूलमंत्र्यांकडे अपील करता येईल. सध्या मुख्य नियंत्रक, महसूल प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाच्या विरोधात केवळ उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा होती. यातून उच्च न्यायालयातील खटल्यांचा भार वाढत होता तसेच पक्षकारांना न्यायालयीन खर्च करावा लागे आणि न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने शासनाचा महसूल अडकून पडत असे. म्हणून कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आल्याचा दावा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधेयक मांडताना केला. नवीन कायद्यामुळे पक्षकारांना आता एक हजार रुपये भरून शासनाकडे अपील करता येईल. राज्य शासन दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यावर निवाडा करेल आणि तो अंतिम असेल, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. वरवर बघता नागरिकांच्या फायद्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरेल, असेच वाटते. पण सरकारने अधिकार स्वतःकडे घेतल्याने त्याला अनेक फाटे फुटणार आहेत. सरकारकडे अपील केल्यावर फायलींचा प्रवास होणाऱ्या टेबलांची संख्या वाढेल. ती वाढल्यावर सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराला वाट फुटते हे जगजाहीर आहे. सरकारने एखादा निर्णय घेतला तरी तो मान्य नसल्यास पक्षकार पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवू शकतो. म्हणजे परत न्यायालयीन प्रक्रिया आलीच.

या कायद्याचा उद्देश कदाचित चांगला असू शकतो, पण त्यासाठी निवडलेली वेळ ही संशयाला वाव देणारी ठरते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीच्या पुण्यातील जमीन खरेदीचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. १८०० कोटींची जमीन केवळ ३०० कोटींमध्ये खरेदी करण्याचा व्यवहार केल्यावरून बरीच ओरड झाली. यासाठी २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क तांत्रिक कारणावरून माफ करण्यात आले. यावरून बरीच ओरड झाल्यावर हा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याचे अजित पवार यांनीच पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. व्यवहार रद्द केल्याचे नुसते जाहीर करून चालत नाही तर त्यासाठी तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागते. वादग्रस्त व्यवहार रद्द करण्याकरिता २१ कोटी रुपये भरण्याची नोटीस मुद्रांक शुल्क कार्यालयाने पार्थ पवार यांच्या कंपनीला बजावली आहे. नवीन कायद्यामुळे पार्थ पवार यांच्या कंपनीला सरकारकडे अपील करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अजित पवारांच्या पुत्राची कंपनी म्हटल्यावर सरकारी यंत्रणा वरिष्ठांच्या आदेशानुसार निर्णय घेणार हे ओघानेच आले. परिणामी नोटिशीला सरकारकडून स्थगिती दिली जाऊ शकते. सबब पार्थ पवार व त्यांच्या कंपनीला दिलासा मिळू शकतो. यामुळेच कायदा करण्याच्या वेळेवरून बावनकुळे किंवा महायुती सरकारने शंका घेण्यास वाव ठेवला आहे. एरव्ही या कायद्याची फारशी दखलही घेतली गेली नसती. पण सरकारमधील उच्चपदस्थांसाठी हा खटाटोप तर नाही ना, असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. 'महायुतीकडे बहुमत असल्याने लोकशाहीत योग्य वाटेल तो निर्णय सरकार घेऊ शकते', अशी भूमिका अजित पवारांनी मांडली. अजित पवारांचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. पण मग मुलाला २१ कोटी रुपये भरण्याचा सल्ला ते का देत नाहीत, हा प्रश्न आहे. सहकार कायद्यात सरकारकडे अपील करण्याची तरतूद आहे म्हणून महसूल खात्यात तशी तरतूद करण्यात आल्याचा अजित पवारांचा त्यावरील युक्तिवादही न पटणाराच. मुद्रांक शुल्क विभागात वार्षिक सरासरी ६० हजार कोटी रुपये महसूल रूपाने जमा होतात. याउलट सहकार विभागात साखर कारखाने, सूत गिरण्या आदींनी पैसे वाटण्यातच अधिक खर्च होतात. हा मुख्य फरक आहे.

मंत्र्यांच्या विशेषाधिकारावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये मंत्र्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या अधिकारांवरून ताशेरे ओढले आहेत. मुद्रांक शुल्क विभागाच्या निर्णयाच्या विरोधात सरकारकडे अपील करण्याची तरतूद करण्यात आली असली तरी मलईदार प्रकरणांवर ते होण्याची शक्यता अधिक. मंत्र्यांकडे अधिकार असल्यावर त्याला वेगळे फाटे फुटतात. जमिनीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये स्वतःच्या अधिकारात घेतलेल्या निर्णयांमुळे मनोहर जोशी व अशोक चव्हाण या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना घरी जावे लागले होते. राज्य सरकारने अधिकार स्वतःकडे घेण्यापेक्षा मुद्रांक शुल्क विभागातून अधिक महसूल कसा मिळेल या दृष्टीने महसूलमंत्री वा सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

विश्लेषण

जितेंद्र पाटील

patil.jitendra@expressindia.com

केळी उत्पादकांची परवड थांबणार कधी?

जळगावमधील केळीच्या उत्पादन खर्चात अलीकडच्या काळात विविध कारणांमुळे मोठी वाढ झाली. अपेक्षित बाजारभावाअभावी उत्पादन खर्च वसूल होणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, जळगाव जिल्ह्यातील केळीबागांची स्थिती, त्यांचे दर, उत्पादनासाठी येणारा खर्च याचा थोडक्यात वेध.

केळी लागवडीची स्थिती काय?

जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादनाला देशभरात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देशात सर्वाधिक केळी लागवड करणारा जिल्हा अशी जळगावची ओळख आहे. तब्बल ६० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रात वर्षभर केळीची लागवड होत असल्यामुळे जळगावला 'केळीची राजधानी' अशी खास ओळख मिळाली आहे. विशेष म्हणजे एकूण लागवड क्षेत्रापैकी सुमारे ८० टक्के क्षेत्र जी-९ टिश्यूकल्चर या उच्च दर्जाच्या आणि निर्यातक्षम वाणाखाली येते. यामुळे जळगावचे केळी उत्पादन केवळ राज्यात नव्हे, तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अग्रस्थान मिळवताना दिसते. रावेर, यावल, भुसावळ आणि मुक्ताईनगर या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक लागवड होते. जळगावमधील शेतकरी मार्च ते जुलै या कालावधीत मृगबाग प्रकारातील केळी, तर ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरच्या कालावधीत कांदेबाग प्रकारातील केळी लागवड करतात.

केळीची आवक कशी?

जिल्ह्यातील रावेर, यावल, मुक्ताईनगर तसेच परिसरातील इतर तालुक्यांमधील मृगबाग केळीची काढणी आता जवळपास पूर्ण झाली आहे. सध्या चोपडा, जामनेर, एरंडोल आणि जळगाव तालुक्यांमधील कांदेबाग केळीची काढणी वेगाने सुरू आहे. वाढलेल्या थंडीमुळे निसवणीचा वेग मंदावला आहे. परिणामी बाजारात केळीची आवक अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी प्रमाणात होत आहे. जळगावलगत मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर बाजार समितीत महिनाभरापूर्वी दररोज सुमारे ८० ते ८५ मालमोटारी (प्रत्येकी १० टन क्षमता) केळीची आवक सुरू होती, त्या ठिकाणी सध्याच्या घडीला जेमतेम १५ मालमोटारी केळीची आवक होत आहे. हीच स्थिती कमी-अधिक फरकाने रावेर तालुक्यातही दिसून येत आहे.

आवकमध्ये घट होण्याचे कारण?

जिल्ह्यातील केळी लागवडीच्या भागात यंदा एप्रिलपासूनच गारपिटीसह पाऊस आणि वादळी वाऱ्याचे संकट आले. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्येही अतिवृष्टीसह पुराच्या पाण्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या केळीबाग पाण्याखाली गेल्या होत्या. दुसरीकडे, सततच्या ढगाळ वातावरणामुळे बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने करपा रोगाने पाय पसरण्यास सुरुवात केली. अनेक ठिकाणी बागेतच अकाली केळी पिकण्यास सुरुवात झाली. त्यात थंडीचा तडाखा वाढल्याचाही परिणाम केळींवर झाला. अशा स्थितीत मागणीच्या तुलनेत खूपच कमी केळी विक्रीसाठी येत आहेत.

केळी दराची स्थिती?

मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर बाजार समितीत नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला केळीला ७०० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत होता. त्यानंतर भावातील घसरण सुरू झाली, पुन्हा काही दिवसांतच भाव ४७५ रुपयांपर्यंत खाली आले. त्यानंतर हळूहळू दरात सुधारणा होऊ लागली. आठ डिसेंबर रोजी केळीला १२०० रुपयांपेक्षा अधिक भाव मिळाला. भावात बऱ्यापैकी सुधारणा झाली असली, तरी बाजारात सध्या खूपच कमी केळी विक्रीसाठी येत आहेत. हा भाव उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी असला, तरी काही दिवसांतील तीव्र घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना हा भावही समाधानकारक वाटू लागला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी बऱ्हाणपूर बाजार समितीत दररोज अंदाजे १० टन क्षमतेच्या सुमारे १५० मालमोटारी केळी आवक होत होती. परंतु, आता हीच आवक घटत जाऊन दिवसाला अवघ्या १५ ते २० मालमोटारींवर येऊन थांबली आहे. तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांसमोर दर वाढविण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

दर कमी का झाले?

केळीला देशभरात बाराही महिने मागणी असते. साधारण डिसेंबरअखेरपर्यंत केळीला बाजारात चांगले दर त्यामुळे मिळतात. त्यानंतर मात्र पेरू, सीताफळ, बोरे, मोसंबी, संत्री यांसारख्या फळांची आवक वाढू लागते. अर्थात, बाजारातील स्पर्धा वाढल्याने केळीच्या मागणीवर आणि दरावर काहीअंशी परिणाम संभवतो. त्या तुलनेत यंदा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातच केळीचे दर खालावले. प्रतिकूल हवामानामुळे बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे केळीच्या घडांवर ठिपक्यांचे प्रमाण वाढल्यानंतर दर्जा खालावलेल्या मालाची खरेदी व्यापाऱ्यांनी थांबवली. काही ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी संगनमताने केळीचे दर कमी केल्याचे प्रकारदेखील उघडकीस आले.

केळीचा उत्पादन खर्च किती?

केळीच्या बागेला लागवडीपासून काढणीपर्यंत एका घडासाठी साधारणपणे १०० ते १२०, क्विंटलला ७०० ते ८०० आणि प्रति एकरी ७० ते ८० हजार खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागतो. केळी लागवडीचा खर्च हा रोपांची एकूण संख्या, लागवडीचे तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. उत्पादन खर्चात प्रामुख्याने रोपांची किंमत, शेतीची मशागत, सिंचन प्रणाली, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकाचा खर्च समाविष्ट असतो.